महानगर नई दिल्ली गुरुवार 2 अप्रैल, 2020, रु. 5.00 (12 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा

निजामुद्दीन के मरकज से देश में बढ़ी संक्रमितों की संख्या

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 अप्रैल।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले दिनों अचानक बढ़ी संक्रमितों की संख्या राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण के फैलने की दर को नहीं दर्शाती है, बल्कि इस बढ़ोतरी में निजामुद्दीन मरकज की घटना प्रमुख वजह रही। दिल्ली स्थित निजामुद्दीन इलाके में एक से 15 मार्च तक हुए तबलीगी जमात के एक आयोजन में हिस्से लेने वालों में कोरोना विषाणु के संक्रमण के कई मामले सोमवार और मंगलवार को सामने आए थे।

अचानक बढ़ी संक्रमितों की संख्या राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण के फैलने की दर को नहीं दर्शाती

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम लोगों से पूर्ण बंदी के दौरान दिशानिर्देशों का पालन करने, जमावड़ों और धार्मिक समागमों से दूर रहने का अनुरोध करते हैं।

उन्होंने बताया कि हमने राज्यों को तबलीगी जमात में शामिल संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों की जांच सुनिश्चित करने के लिए गहन अभियान चलाने को कहा गया है। अग्रवाल ने कहा कि संक्रमण बाकी पेज 8 पर

उत्तर प्रदेश में दो की मौत

लखनऊ, 1 अप्रैल (भाषा)।

उत्तर प्रदेश में कोरोना के संक्रमण से अब तक दो मरीजों की मौत हो गई है। मृतकों में से एक बस्ती का रहने वाला था जबकि दूसरा मेरठ का रहने वाला था। बस्ती निवासी मरीज को पिछले एक साल से किडनी की बीमारी थी।

8 दिन

अगरतला : दिल्ली के निजामुद्दीन में हुए मरकज में शामिल लोगो को परीक्षण के लिएं ले जाते स्वास्थ्यकर्मी।

संपर्क में आए यात्रियों का पता लगाने को पांच ट्रेनों पर नजर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 अप्रैल।

रेलवे ने दिल्ली में पांच ट्रेनों में तबलीगी जमात में भाग लेने वाले लोगों के साथ सफर शुरू करने वाले हजारों यात्रियों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की है। तबलीगी जमात के कई लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इनलोगों ने दिल्ली से विभिन्न बाकी पेज 8 पर

मरकज खाली कराने के बाद शुरू हुई मौलाना साद की तलाश

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 अप्रैल।

दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज को पूरी तरह से खाली कराने के बाद पुलिस ने इसके प्रमुख मौलाना साद की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस की कई टीमें पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर साद और अन्य आयोजकों की तलाश के लिए छापेमारी कर रही हैं। उधर, दिल्ली पुलिस ने जलसे में शामिल लोगों की तलाश में मंगलवार देर रात से बुधवार शाम तक दिल्ली के अलग-अलग मस्जिदों और मदरसों में दबिश दी।

वजीराबाद की मस्जिद से मिले 15 विदेशी, मौलवी पर मामला

जांच से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक तीन दिन तक चले ऑपरेशन के बाद मरकज से 2361 लोगों को बाहर निकाला गया है जिसमें 617 में कोरोना के लक्षण मिले हैं। इन्हें दिल्ली के बाकी पेज 8 पर

24 घंटे में 437 मामले, अब तक 41 की मौत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 अप्रैल।

चौबीस घंटे में देश भर में कोरोना विषाणु संक्रमण के 437 नए मामले और संक्रमण ने छह लोगों की जान ली है। इससे बुधवार शाम तक कुल संक्रमितों की संख्या 1834 पहुंच गई जबकि इस महामारी से मौत का आंकड़ा 41 हो गया।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 1649 कोरोना विषाणु संक्रमितों का इलाज चल रहा है, वहीं 143 लोग या तो ठीक हो गए हैं या उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। एक रोगी दूसरे देश जा चुका है। दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 152 हो गई है। उत्तर प्रदेश में भी संक्रमण के 103 मामले सामने आ चुके हैं। असम और झारखंड में भी एक-एक मामले सामने आए हैं। अब तक 29 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं।

भारत में संक्रमितों की संख्या

मंगलवार : 1397
बुधवार : 1834

स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार शाम साढ़े सात बजे के आंकड़ों के अनुसार चौबीस घंटे में मौत के छह नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना विषाणु से मौत के सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र हैं। इस राज्य में नौ रोगियों की मौत हो चुकी है।

दिल्ली और यूपी में मामलों में बढ़ोतरी

देश में मरने वालों की संख्या 41 हुई, संक्रमण के कुल मामले 1834।
असम और झारखंड में भी एक-एक मामला सामने आया।
दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 152 और उत्तर प्रदेश में 103 हुई।

गुजरात में छह, कर्नाटक में तीन, तेलंगाना में तीन, मध्य प्रदेश में तीन, पश्चिम बंगाल में तीन, पंजाब में तीन, दिल्ली में दो, केरल में दो, उत्तर प्रदेश में दो और जम्मू कश्मीर में कोरोना विषाणु संक्रमण से मौत के दो मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु, बिहार और हिमाचल प्रदेश में इस महामारी से एक-एक रोगी की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में बाकी पेज 8 पर

अमेरिका में मरने वालों की संख्या चार हजार के पार

न्यूयार्क, 1 अप्रैल (भाषा)।

अमेरिका में कोरोना विषाणु से मरने वालों की संख्या बुधवार को चार हजार के पार पहुंच गई है। अमेरिका में कोरोना विषाणु से मारे गए लोगों की संख्या चीन में मृतकों की संख्या 3,310 से भी अधिक हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को सामुदायिक दूरी के कदमों को अगले 30 दिन के लिए 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। उन्होंने आगाह किया है आने वाले दो सप्ताह अमेरिका के लिए बेहद मुश्किल होंगे। शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस महामारी से एक लाख से दो लाख अमेरिकी लोग मारे जा सकते हैं।

अमेरिका में कोरोना विषाणु से मारे गए लोगों की संख्या 11 सितंबर (9/11) को हुए आतंकवादी हमलों में मारे गए लोगों की संख्या से भी अधिक हो गई है। इस आतंकवादी हमले में लगभग 3000 लोगों की मौत हुई थी। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय कोरोना विषाणु संसाधन केंद्र के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में कोरोना विषाणु से मृतकों की संख्या चार हजार से अधिक पहुंच गई है और लगभग 1,90,000 लोग इससे संक्रमित हैं।

शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस महामारी से एक लाख से दो लाख तक अमेरिकी मर सकते हैं।
चीन में मृतकों की संख्या 3,310 से भी अधिक हो गई है अमेरिका में मरने वालों की तादाद चीन से ज्यादा हुई।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना विषाणु को लेकर किए संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मैं चाहता हूं कि अमेरिकी आने वाले मुश्किल दिनों के लिए तैयार रहें। हमें बेहद मुश्किल दो हफ्तों का सामना करना होगा और फिर उम्मीद करते हैं कि जैसा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि हमें बाकी पेज 8 पर

आज मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली, 1 अप्रैल (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि इस संवाद के दौरान कोरोना संक्रमण, प्रवासी श्रमिकों के पलायन और तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।

सूत्रों ने बताया कि इस संवाद के दौरान आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के मुद्दों पर भी चर्चा की जा सकती है। कोविड-19 के प्रकोप और इससे जुड़े मुद्दों के सामने आने के बीच पिछले दो सप्ताह से कम समय में प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की यह दूसरी बातचीत होगी। पहली ऐसी बातचीत 20 मार्च को हुई थी।

चीनी प्रधानमंत्री से मोदी ने कहा, विश्व स्तर पर सहयोग जरूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और चीन के बीच अच्छे संबंधों को दोनों देशों, क्षेत्र व दुनिया की शांति और समृद्धि के लिए महत्त्वपूर्ण बताया।
खबर पेज-2

मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से की बात
खबर पेज-2

पहली से आठवीं तक के छात्र अगली कक्षा में

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 अप्रैल।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कोरोना विषाणु संक्रमण के बाद बनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए दसवीं और बारहवीं की सिर्फ 29 मुख्य विषयों की परीक्षा ही आयोजित करने का निर्णय किया है।

बोर्ड का कहना है कि केवल उन विषयों की ही परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी जिनकी आवश्यकता बाकी पेज 8 पर

नौवीं और ग्यारहवीं के छात्रों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अगली कक्षा में भेजने की सलाह।

जेईई एडवांस स्थगित

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 अप्रैल।

देश में मौजूद 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) एडवांस को स्थगित कर दिया गया है। यह परीक्षा 17 मई 2020 को होने वाली थी। इस परीक्षा का आयोजन आइआइटी दिल्ली कर रहा है। संस्थान की ओर से कहा गया है कि देश में कोरोना विषाणु संक्रमण की वजह से जेईई मुख्य को स्थगित कर दिया गया है।

ग्राहकों को मोहलत से लाभ नहीं, भरना होगा ब्याज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 अप्रैल।

रिजर्व बैंक की कर्ज की मासिक किस्त (ईएमआइ) भुगतान पर तीन महीने की रोक से ग्राहकों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से संभवतः कोई बहुत ज्यादा लाभ होता नहीं दिख रहा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस बारे में घोषित योजना के अनुसार वे इन तीन महीनों का ब्याज बाद में वसूलेंगे।

रिजर्व बैंक ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को खुदरा और फसल समेत सभी प्रकार के कर्ज (टर्म लोन) और कार्यशील पूंजी भुगतान पर तीन महीने की रोक बाकी पेज 8 पर

पंद्रह साल से रह रहे लोगों को मिलेगा मूल निवासी का दर्जा

नयी दिल्ली, 1 अप्रैल (भाषा)।

जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लिए जाने के आठ महीने बाद केंद्र सरकार ने वहां के मूल निवासी के संबंध में नियम जारी किए। इसके अनुसार इस केंद्रशासित प्रदेश में 15 वर्षों तक रहने वाले किसी भी व्यक्ति को यह दर्जा मिल सकता है। इस कदम को नेताओं ने जख्म पर नमक छिड़कना करार दिया है।

ये प्रावधान जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (राज्य कानूनों का अंगीकार) आदेश-2020 नामक एक गजट अधिसूचना के माध्यम से किए गए हैं जिसमें पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर के 138 कानूनों की समीक्षा, संशोधन और निरसन किया गया। संशोधित कानूनों में एक जम्मू कश्मीर सिविल सेवा बाकी पेज 8 पर

जम्मू कश्मीर में मूल निवासी के संबंध में नए नियम जारी।
समूह चार की नौकरियां मूल निवासियों के लिए सुरक्षित।
पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के 138 कानूनों में से 28 निरस्त।
जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों ने की संशोधनों की निंदा।

अमेरिकी विज्ञानियों ने कहा

कोरोना में बीसीजी टीके भारत के लिए कवच

नई दिल्ली, 1 अप्रैल (भाषा)।

अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कहा है कि क्षय रोग (टीबी) से बचाव के लिए भारत में जन्म के तुरंत बाद लाखों बच्चों को दिया जाने वाला बीसीजी का टीका कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में परिवर्तनकारी साबित हो सकता है।

न्यूयॉर्क इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनवाईआइटी) का एक अध्ययन अभी प्रकाशित होने वाला है जिसमें इटली और अमेरिका का उदाहरण देते हुए राष्ट्रीय नीतियों के तहत कई देशों में लगाए जाने वाले बीसीजी के टीके और कोविड-19 के प्रभाव का आपस में संबंध बताया गया है।

अमेरिकी वैज्ञानिकों ने बीसीजी टीके का संबंध कोविड-19 के भारत में कम मामलों से जोड़ा, कहा नीदरलैंड, अमेरिका व इटली में नहीं है इन टीकों का सुरक्षा चक्र, भारतीय वैज्ञानिक आशावान

एनवाईआइटी में जैव चिकित्सा विज्ञान के सहायक प्रोफेसर गोंजालू ओटाजू के नेतृत्व में जाने-माने अनुसंधानकर्ताओं ने कहा, 'हमने पाया कि जिन देशों में बीसीजी टीकाकरण की नीतियां नहीं हैं, वहां कोरोना वायरस से लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं जैसे कि इटली, नीदरलैंड और अमेरिका। वहीं, उन देशों में लोगों पर कोरोना वायरस का ज्यादा असर नहीं पड़ा है जहां लंबे समय से बीसीजी टीकाकरण की नीतियां चली आ रही हैं।' अमेरिका में कोरोना वायरस के लगभग 1,90,000 मामले सामने आए हैं और वहां चार हजार से बाकी पेज 8 पर

दरअसल

सादी जीवन शैली से ठीक हुए पति-पत्नी | **मिसाल** | **चिकित्सक समुदाय ने कहा - चमत्कार**

बुजुर्ग दंपति के आगे कोरोना हुआ बेदम

पथनमथिट्टा (केरल), 1 अप्रैल (भाषा)।

ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में ज्यादातर बुजुर्ग कोरोना संक्रमण के खिलाफ जीवन की लड़ाई हार रहे हैं, केरल के 93 और 88 वर्षीय पति-पत्नी ने अपनी सादी जीवन शैली और पौष्टिक भोजन की मदद से इस बीमारी को हरा कर सभी के सामने मिसाल पेश की है। कई दिन तक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती रहने के बाद दोनों के कोरोना संक्रमण से पूरी तरह मुक्त होने को चिकितसक समुदाय 'चमत्कार' बता रहा है।

अस्पताल के पृथक वार्ड में भर्ती रहने के दौरान भी 93 साल के थॉमस अब्राहम ने अपने खाने-पीने का अंदाज नहीं बदला था। वहां भी वह पझनकांजी (चावल से बना व्यंजन), कप्पा और कटहल ही खा रहे थे। थॉमस और मरियम्मा (88) को यह संक्रमण इटली से पिछले महीने लौटे उनके बेटा, बहू और पोते से लगा। लेकिन अब परिवार के पांचों सदस्य संक्रमण मुक्त हो गए हैं और एक साथ रहने की राह देख रहे हैं। दोनों कोट्टायम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती थे।

अस्पताल के पृथक वार्ड में भर्ती रहने के दौरान भी 93 साल के थॉमस अब्राहम ने अपने खाने-पीने का अंदाज नहीं बदला था। वहां भी वह पझनकांजी (चावल से बना व्यंजन), कप्पा और कटहल ही खा रहे थे। थॉमस और मरियम्मा (88) को यह संक्रमण इटली से पिछले महीने लौटे उनके बेटा, बहू और पोते से लगा। लेकिन अब परिवार के पांचों सदस्य संक्रमण मुक्त हो गए हैं और एक साथ रहने की राह देख रहे हैं।

बातचीत के दौरान थॉमस के पोते रिजो मॉन्सी ने हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि दोनों अपनी जीवन शैली के कारण स्वस्थ हो पाए हैं। उन्होंने बताया कि उनके दादा पथनमथिट्टा जिले के रानी में किसानी करते हैं और शराब तथा सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाते हैं। वे हंसते हुए कहते हैं, 'जिम गए बगैर भी दादा के सिक्स पैक एब्स हैं।' इटली में रेडियोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाले रिजो का कहना है, 'यह चमत्कार है कि वे इस महामारी से बच गए।

डॉक्टरों और स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें बचाने का हरसंभव प्रयास किया।' रिजो और उनके माता-पिता बरसों से इटली में रहे रहे हैं। उन्होंने अपने दादा-दादी के इलाज के लिए राज्य सरकार की प्रशंसा की।

रिजो ने बताया, 'हम अगस्त में केरल आने वाले थे, लेकिन दादा जी ने कहा कि जल्दी आ जाओ, इसलिए हम आ गए। लेकिन, अब लगता है कि यह अच्छा ही हुआ वरना अभी हम इटली में होते।'

उन्होंने कहा, 'अपनी पढ़ाई के दिनों में मैं दादाजी के साथ ही रहता था, हम काफी करीब हैं। उन्होंने कहा कि हम उनसे मिलने जल्दी आ जाएं।' रिजो का कहना है कि इटली के मुकाबले केरल में उनके सुरक्षित रहने की संभावना ज्यादा है।

रिजो से उनके दादा-दादी के पसंदीदा भोजन के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया, 'दादा को पझनकांजी, कप्पा और चक्का पसंद है जबकि दादी मछली पसंद से खाती हैं।' पझनकांजी, पके हुए चावल (भात) से बना व्यंजन है, जिसमें रात को भात में पानी डाल कर छोड़ दिया जाता है। कप्पा एक प्रकार का जड़ है जिससे सब्जी और चिप्स आदि बनते हैं। चक्का केरल में कटहल को कहते हैं। उन्होंने बताया कि पृथक वार्ड में रहने के बाकी पेज 8 पर

www.readwhere.com

अफगान वार्ता सकारात्मक कदम : भारत

कैदियों की अदला-बदली पर तालिबान और अफगान सरकार की बातचीत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 अप्रैल।

भारत ने 'अंतर अफगान वार्ता दल' के गठन की अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के निर्णय का स्वागत करते हुए बुधवार को कहा कि यह एक सकारात्मक कदम है, जो उस युद्धग्रस्त देश को बाहर से प्रायोजित आतंकवाद की बुराई से मुक्ति दिलाने तथा उसके शांतिपूर्ण एवं स्थिर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। वार्ता दल ने तालिबान और अफगान सरकार के कैदियों की अदला-बदली को लेकर बातचीत की है। शांति प्रक्रिया को पटरी पर लाने के उद्देश्य से कैदियों की अदला-बदली के मुद्दे पर पहली बार काबुल में तालिबान से बातचीत की है अफगान सरकार ने।

विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, 'भारत, अफगानिस्तान सरकार द्वारा 'अंतर अफगान वार्ता दल' के गठन की घोषणा का स्वागत करता है। भारत ने अफगान नीत, अफगान नियंत्रित शांति एवं मेल-मिलाप प्रक्रिया का निरंतर समर्थन किया है।' बयान के अनुसार, 'इस दिशा में हम अंतर अफगान वार्ता दल के गठन को एक सकारात्मक कदम मानते हैं, जो अफगानिस्तान को बाहर से प्रायोजित आतंकवाद की बुराई से मुक्ति दिलाने तथा उसके शांतिपूर्ण एवं स्थिर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा।' विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम राजनीति से जुड़े सभी वर्गों के लोगों से आह्वान करते हैं कि वे अफगानिस्तान के सभी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने एवं सुरक्षित एवं समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करें, जिसमें वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी शामिल हैं।

> विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, 'भारत, अफगानिस्तान सरकार द्वारा 'अंतर अफगान वार्ता दल' के गठन की घोषणा का स्वागत करता है। भारत ने अफगान नीत, अफगान नियंत्रित शांति एवं मेल-मिलाप प्रक्रिया का निरंतर समर्थन किया है।' बयान के अनुसार, 'इस दिशा में हम अंतर अफगान वार्ता दल के गठन को एक सकारात्मक कदम मानते हैं, जो अफगानिस्तान को बाहर से प्रायोजित आतंकवाद की बुराई से मुक्ति दिलाने तथा उसके शांतिपूर्ण एवं स्थिर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा।'

भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान से पहले अफगानिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के कार्यालय ने ट्विटर पर जानकारी दी कि दोनों पक्षों के बीच मंगलवार को मुलाकात हुई और बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए वे आगे भी मिलेंगे। यह चर्चा रेडक्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति की देखरेख में हो रही है। सुरक्षा परिषद ने कहा, 'दोनों पक्षों के बीच अफगान नेशनल डिफेंस और सुरक्षा बल के जवानों तथा तालिबान के कैदियों की रिहाई के बारे में आमने-सामने बातचीत हुई।'

कैदियों के मुद्दे पर दोनों पक्षों ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पहले भी बात की है। लेकिन 2001 में अमेरिकी नीत गठबंधन बलों द्वारा तालिबान को सत्ता से बाहर करने के बाद से यह पहली बार है जब कट्टरपंथी इस्लामी समूह के सदस्यों को सरकारी अधिकारियों से सीधे मुलाकात करने के लिए काबुल आमंत्रित किया गया है।

वाशिंगटन ने फरवरी में तालिबान के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत तालिबान के काबुल से वार्ता शुरू करने और अन्य वादों पर कायम रहने के बदले में अगले वर्ष जुलाई तक अफगानिस्तान से अमेरिकी और अन्य विदेशी सैनिकों को वापस बुलाने की बात थी। इस समझौते के तहत ही अफगान सरकार को तालिबान के 5,000 कैदियों को रिहा करना था और उग्रवादियों को सरकार समर्थक 1,000 बंदियों को रिहा करना था।

राज्य सरकारों के आश्रय गृहों में 6.75 लाख से अधिक मजदूरों ने ली शरण : गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 अप्रैल (भाषा)।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए घोषित किए गए लॉकडाउन के दौरान 6.75 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों ने राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा स्थापित 21,486 आश्रय गृहों में शरण ली है।

संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि घरों को लौट रहे 25 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों को राहत शिविरों में भोजन उपलब्ध कराया गया।

उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल सचिव ने बुधवार को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभ वितरण त्वरित और प्रभावी होना चाहिए।

श्रीवास्तव ने कहा कि क्योंकि लाभ वितरण बैंकों के जरिए होता है, इसलिए योजना 'सटीक' होनी चाहिए और एक-दूसरे से भौतिक दूरी बनाए रखने के नियम का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति संतोषजनक है। लॉकडाउन की घोषणा के बाद प्रवासी मजदूरों के पलायन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश 21,486 आश्रय गृहों में उनके लिए इंतजाम कर रहे हैं जिनमें 6.75 लाख श्रमिक रह रहे हैं और 25 लाख को भोजन उपलब्ध कराया गया।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप आश्रय गृहों में मौजूद प्रवासी मजदूरों की काउंसलिंग के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्रशिक्षित परामर्शदाताओं और सामुदायिक नेताओं की मदद लेने को कहा गया है। अधिकारी ने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि लॉकडाउन सफल हो और आवश्यक सेवाएं बहाल रहें।

इंदौर में 600 लोग पृथक केंद्रों में पहुंचाए गए

इंदौर, 1 अप्रैल (भाषा)।

कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद यहां पिछले आठ दिनों में करीब 600 लोगों को पृथक केंद्रों में पहुंचाया गया है ताकि इस महामारी का फैलाव रोका जा सके। इंदौर, देश में कोरोना वायरस संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में है जहां अब तक इस बीमारी के 63 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से तीन लोगों की पहले ही मौत हो चुकी है, जबकि अन्य 60 का इलाज जारी है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रवीण जड़िया ने बुधवार को संवाददाताओं को बताया, शहर के मैरिज गार्डनों और अन्य स्थानों पर बनाए गए पृथक केंद्रों में करीब 600 लोगों को सावधानी के तौर पर पहुंचाया गया है। इन्हें वहां इसलिए रखा गया है क्योंकि इनके बारे में संदेह है कि वे कोरोना से संक्रमित मरीजों के संपर्क में किसी न किसी तरह आए हैं। इनमें से ज्यादातर लोग कोरोना मरीजों के परिजन हैं।

उन्होंने बताया, पृथक केंद्रों में रखे गए सभी 600 लोगों की हालत पर लगातार निगाह रखी जा रही है। कोरोना वायरस संक्रमण के संदेह पर इनमें से 400 लोगों के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं।

चीनी प्रधानमंत्री से मोदी ने कहा, विश्व स्तर पर सहयोग जरूरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 अप्रैल।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और चीन के बीच अच्छे संबंधों को दोनों देशों, क्षेत्र व दुनिया की शांति व समृद्धि के लिए महत्त्वपूर्ण बताया और कहा कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सही अर्थों में वैश्विक प्रक्रिया को अपनाने की जरूरत है।

विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर चीनी प्रधानमंत्री ली क्विंग को भेजे संदेश में यह बात कही। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पत्र लिखकर दोनों देशों के मजबूत संबंधों को रेखांकित किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'कोविड-19 महामारी हमें इस बात की याद दिलाती है कि दुनिया एक दूसरे से परस्पर किस प्रकार से जुड़ी हुई है और इसलिए इससे (कोरोना) मुकाबला करने के लिए सही अर्थों में वैश्विक प्रक्रिया को अपनाने की जरूरत है।' मोदी ने कहा कि भारत और चीन दो प्राचीन सभ्यताएं हैं, जिनके बीच सदियों से परस्पर लाभकारी आदान-प्रदान का लंबा इतिहास रहा है।

उन्होंने कहा कि हम दो बड़े विकासशील देश और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं और आज तेजी से वैश्विक परिदृश्य पर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मोदी ने कहा कि भारत और चीन के बीच अच्छे संबंध न केवल दोनों देशों के लिए उपयुक्त हैं बल्कि हमारे क्षेत्र और विश्व की शांति, स्थिरता और समृद्धि के दृष्टिकोण से भी महत्त्वपूर्ण हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वह दोनों देशों के संबंधों को और अधिक गहरा और मजबूत बनाने के लिए चीनी प्रधानमंत्री के साथ काम करने को लेकर आशान्वित हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लिखे पत्र में चीन की सरकार और वहां के लोगों के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की हैं।

कोविंद ने कहा कि दोनों देशों ने पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र और लोगों से लोगों के बीच संबंधों सहित लिपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने में काफी प्रगति हासिल की है। वहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी को लिखे पत्र में कहा कि पिछले सात दशकों में भारत-चीन संबंधों को काफी विस्तार मिला है और इसका स्वरूप बहुआयामी हो गया है।

The Indian EXPRESS
Classifieds
FROM ANYTHING TO EVERYTHING.

CLASSIFIED AD DEPOT (CAD)
Book classified ads at your nearest Express Group's authorised Classified Ad Depots

EAST
PATPARGANJ : CHAVI ADVERTISERS, Ph.: 9899701024, 22090987, 22235837, **PREET VIHAR :** AD BRIDGE COMMUNICATION, Ph.: 9810029747, 42421234, 22017210, **SHAKARPUR :** PARICHAY ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9350309890, 22519890, 22549890

WEST
JANAKPURI : TRIMURTI ADVERTISERS, Ph.: 9810234206, 25530307, **KAROL BAGH (REGHARPURA) :** K R ADVERTISERS, Ph.: 9810316618, 9310316618, 41547697, **KARAMPURA :** GMJ ADVERTISING & MARKETING PVT. LTD., Ph.: 9310333777, 9211333777, 9810883377, **NEW MOTI NAGAR :** MITTAL ADVERTISING, Ph.: 25178183, 9810538183, 9555945923, **MOTI NAGAR :** UMA ADVERTISERS, Ph.: 9312272149, 8800276797, **RAMESH NAGAR :** POSITIVE ADS, Ph.: 9891195327, 9310006777, 65418908, **TILAK NAGAR :** SHIVA ADVERTISERS, Ph.: 9891461543, 25980670, 20518836, **VIKAS PURI :** AAKAR ADVT. MEDIA Ph.: 9810401352, 9015907873, 9268796133

CENTRAL
CHANDNI CHOWK : RAMNIWAS ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9810145272, 23912577, 23928577, **CONNAUGHT PLACE :** HARI OM ADVERTISING COMPANY Ph.: 9811555181, 43751196

NORTH
TIS HAZARI COURT : SAI ADVERTISING, Ph.: 9811117748 **KINGWAY CAMP :** SHAGUN ADVERTISING, Ph.: 9818505505, 27458589, **PATEL CHEST (OPP. MORRIS NAGAR POLICE STATION) :** MAHAN ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9350304609, 7042590693, **PITAMPURA (PRASHANT VIHAR) :** PAAVAN ADVERTISER Ph.: 9311564460, 9311288839, 47057929

SOUTH
CHATTARPUR : A & M MEDIA ADVERTISING, Ph.: 9811602901, 65181100, 26301008, **KALKAJI :** ADWIN ADVERTISING, Ph.: 9811111825, 41605556, 26462690, **MALVIYA NAGAR :** POOJA ADVERTISING & MARKETING SERVICE, Ph.: 9891081700, 24331091, 46568866, **YUSUF SARAI :** TANEJA ADVERTISEMENT & MARKETING Ph.: 9810843218, 26561814, 26510090

NCR
FARIDABAD (NEELAM FLYOVER) : AID TIME (INDIA) ADVERTISING, Ph.: 9811195834, 0129-2412798, 2434654, **FARIDABAD (NIT, KALYAN SINGH CHOWK) :** PULSE ADVERTISING, Ph.: 9818078183, 9811502088, 0129-4166498, **FARIDABAD :** SURAJ ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9810680954, 9953526681, **GURGAON :** SAMBODHI MEDIA PVT. LTD., Ph.: 0124-4065447, 9711277174, 9910633399, **GURGAON :** AD MEDIA ADVERTISING & PR, Ph.: 9873804580, **NOIDA (SEC. 29) :** RDX ADVERTISING, Ph.: 9899268321, 0120-4315917, **NOIDA (SEC. 65) :** SRI SAI MEDIA, Ph.: 0120-4216117, **NOIDA (SEC. 58) :** JAI LAKSHMI ADVERTISERS, Ph.: 9873807457, 9911911719 **GHAZIABAD (HAPUR ROAD TIRAHA, NR GURUDWARA) :** TIRUPATI BALAJI ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9818373200, 8130640000, 0120-4561000

EDUCATION (IAS & PMT ACADEMIES)
FRIENDS PUBLICITY SERVICE 23287653, 23276901, 9212008155

For CAD enquiries please contact :
ROHIT JOSHI 9818505947, **ABHINAV GUPTA** 9910035901
For booking classified ads, please contact 011-23702148, 0120-6651215, E-mail : delhi.classifieds@expressindia.com

मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से की बात

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 अप्रैल।

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के फैलते प्रकोप से निबटने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री से टेलीफोन पर बातचीत की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक, कोविड-19 संक्रमण की वजह से भारी संख्या में फ्रांस में लोगों की जानें जाने पर शोक जाहिर किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने कोरोना संकट के घरेलु और अंतरराष्ट्रीय पहलुओं पर बातचीत की और मौजूदा माहौल में वैश्विक सहयोग और एकजुटता बनाए रखने की जरूरत पर बल दिया।

फ्रांस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी के इस विचार से सहमत हुए कि कोविड-19 इतिहास में एक मोड़ लाने वाला साबित होगा और दुनिया के सामने एक मानव आधारित वैश्वीकरण की जरूरत दोनों ने मानी। दोनों इस बात से भी सहमत हुए कि अफ्रीका और एशिया के कुछ अल्प विकसित देशों की जरूरतों को पूरा करने पर विश्व समुदाय का ध्यान होना चाहिए।

फ्रांस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के इस कथन की सराहना की कि कोरोना संकट के इस दौर में व्यक्ति की भौतिक और मानसिक जरूरतों को पूरा करने में योग सहायक हो सकता है। राष्ट्रपति मैक्रों ने इस बात की पुष्टि की कि मौजूदा संकट के दौरान फ्रांस में योग की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है।

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता के मुताबिक विदेश मंत्री पोम्पियो ने कोरोना से उपजे अंतरराष्ट्रीय संकट से निबटने के लिए भारत और अन्य देशों के बीच निकट का सहयोग बनाए रखने की अहमियत बताई और कहा कि विश्व के स्वास्थ्य उपकरण बनाने वाले कारखानों और आपूर्ति करने वाली एजंसियों के बीच तालमेल की जरूरत है।

केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब तलब

नई दिल्ली, 1 अप्रैल (भाषा)।

> मास्क और सैनिटाइजर की उचित दाम पर बिक्री संबंधी याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना विषाणु के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर की समान रूप से उपलब्धता और बिक्री सुनिश्चित करने के लिए दायर याचिका पर बुधवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर के पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किए।

यह याचिका 'जस्टिस फॉर राइट्स फाउंडेशन' नामक संगठन ने दायर की है। इस संगठन की ओर से पेश वकील ने बताया कि कोरोना महामारी फैलने के बाद सरकार ने इससे बचाव के बारे में अनेक निर्देश और परामर्श जारी किए हैं जिनकी वजह से मास्क और हाथों को साफ रखने वाले सैनिटाइजर और लिक्विड सोप की कीमतों में इजाफा हो गया है। याचिका में लोगों को मास्क और सैनिटाइजर उचित कीमत पर उपलब्ध कराने का केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश देने के लिए न्यायालय से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही याचिका में मूल्य नियंत्रण रखने और आवश्यक वस्तुओं की बिक्री का प्रबंध देखने वाली प्रशासनिक एजंसियों को सरकार के तमाम आदेशों पर सख्ती से अमल करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाले भत्ते बंद

नई दिल्ली, 1 अप्रैल (भाषा)।

केंद्र सरकार द्वारा पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के 138 कानूनों में बदलाव किए जाने या समाप्त किए जाने से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाले भत्ते बंद कर दिए गए हैं। बुधवार को जारी गजट अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर राज्य विधानसभा सदस्य पेंशन कानून मे संशोधन कर पेंशन की राशि 50 हजार रुपए से बढ़ा कर 75 हजार रुपए प्रतिमाह कर दी है। यह प्रावधान जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश-2020 गजट अधिसूचना के जरिए जारी गए हैं।

कोरोना से मरे बुजुर्ग का गांव प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित

भोपाल/ खरगोन, 1 अप्रैल (भाषा)।

जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर धरगांव के 65 वर्षीय एक मरीज की कोरोना वायरस संक्रमण से मौत के बाद जिला प्रशासन ने गांव के आसपास के तीन किलोमीटर के इलाके को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है। धरगांव के निवासी में कोरोना संक्रमण की पुष्टि बुधवार को हुई थी।

शीर्ष न्यायालय के सभी न्यायाधीशों ने 'पीएम केयर्स' में 50-50 हजार दिए

नई दिल्ली, 1 अप्रैल (भाषा)।

प्रधान न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों ने कोरोना महामारी के खिलाफ राष्ट्र की लड़ाई में सहायता देने के लिए 'प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष' (पीएम केयर्स) में 50-50 हजार रुपए दान में दिए हैं। शीर्ष न्यायालय के एक अधिकारी ने बताया कि सीजेआइ सहित सभी 33 न्यायाधीशों ने इसमें 50-50 हजार रुपये का दान दिया है। उन्होंने बताया कि इस कोष के लिए चेक भेजे जा चुके हैं।

इससे पहले, सीजेआइ एसए बोबडे के बाद सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश एनवी रमण ने पीएम केयर्स में और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के मुख्यमंत्री कोष में एक-एक लाख रुपए दान में दिए थे।

"IMPORTANT"
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

कला और वाणिज्य के विद्यार्थियों के लिए एप्लाइड गणित का विकल्प

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 अप्रैल।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने वर्तमान सत्र से ग्यारहवीं में कला और वाणिज्य विषयों से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए एप्लाइड गणित (241) शुरू किया है। अगले सत्र से यह विषय बारहवीं के विद्यार्थियों को भी पढ़ाया जाएगा। विज्ञान विषयों की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी गणित का पुराना पाठ्यक्रम ही पढ़ते रहेंगे।

सीबीएसई के निदेशक (अकादमिक) डॉक्टर जोसेफ एम्मनुएल की ओर से जारी परिपत्र के मुताबिक बोर्ड राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की सिफारिशों के अनुरूप गणित और अंग्रेजी जैसे विषयों के विकल्प विद्यार्थियों को उपलब्ध करा रहा है। दो साल पहले नौवीं और पिछले साल दसवीं के लिए बेसिक गणित की शुरुआत की गई थी। इसी क्रम में इस साल ग्यारहवीं के लिए एप्लाइड गणित विषय की शुरुआत की जा रही है। अगले साल इस विषय को बारहवीं के विद्यार्थी भी पढ़ पाएंगे।

डॉक्टर एम्मनुएल के मुताबिक ग्यारहवीं और बारहवीं में इस समय गणित का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में विज्ञान, इंजीनियरिंग या डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के मुताबिक है। देश में बड़ी संख्या में विद्यार्थी कला और वाणिज्य विषयों से ग्यारहवीं और बारहवीं की पढ़ाई करते हैं। ऐसे में या तो वे गणित विषय पढ़ते ही नहीं है या उन्हें मजबूरन वह गणित पढ़ना पड़ता है जो विज्ञान के विद्यार्थियों के अनुरूप है। इस समस्या के समाधान के लिए बोर्ड की पाठ्यचर्या समिति की सिफारिश पर एप्लाइड गणित को शुरू का निर्णय किया गया है। एप्लाइड गणित के अंतर्गत विद्यार्थियों को विशेष रूप से वाणिज्य, वित्त, अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान से संबंधित टॉपिक पढ़ाए जाएंगे।

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक आज

नई दिल्ली, 1 अप्रैल।

कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई, कांग्रेस कार्यसमिति की गुरुवार सुबह बैठक होगी। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुआई में होने वाली इस बैठक में अन्य राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के अलावा कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा घोषित लॉक डाउन के बाद पैदा हुए हालातों, विशेषकर शहरी क्षेत्रों से मजदूरों के पलायन के मुद्दे पर खास तौर पर चर्चा किए जाने की संभावना है। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा, पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी सहित अन्य सदस्यों के मौजूद रहने की संभावना है।

अंतिम संस्कार का हिस्सा बना कीटाणु नाशक द्रव्य

अगरतला, 1 अप्रैल (भाषा)।

कोविड-19 के संक्रमण के बीच त्रिपुरा के बट्टाला के सबसे बड़े श्मशान गृह में अंतिम संस्कार कराने वाले पुजारी सुबीर चक्रबर्ती एक शव के बगल में बैठे हैं और अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। वे संस्कार के लिए सभी जरूरी सामान, जूट की डंडियां, घी, तुलसी के पत्ते, सफेद सूती कपड़ा, अगरबत्ती, मिट्टी के बर्तन और अन्य जरूरी सामग्री को देख रहे हैं। जरूरत का सभी सामान देखने के बाद वे एक बर्तन से कीटाणु नाशक द्रव्य निकालते हैं, अपने हाथों पर मलते हैं और शोक में डूबे परिवार को बताते हैं कि अब वे तैयार हैं।

कोरोना संक्रमण के बीच कीटाणु नाशक द्रव्य 46 साल के पुजारी के जरूरी सामान का हिस्सा हो गया है।

चक्रबर्ती ने कहा, छह से आठ शव श्मशान गृह में रोजाना लाए जाते हैं। इनमें ऐसे भी शव होते हैं जो पोस्टमार्टम के बाद यहां आते हैं। अंतिम संस्कार में सफाई, प्रार्थना करना, शवों की आंखों पर तुलसी की पत्तियां रखना शामिल है। हमें सतर्क रहना होगा इसलिए कीटाणु नाशक द्रव्य जरूरी है।'

हालांकि बाजार में कीटाणु नाशक द्रव्य की कमी को देखते हुए चक्रबर्ती अपना कीटाणु नाशक द्रव्य खुद बना रहे हैं। उन्होंने कहा, स्थानीय बाजार में कीटाणु नाशक द्रव्य की अनुपलब्धता को देखते हुए मैंने इसके विकल्प की तलाश शुरू की। इंटरनेट पर देखते हुए मैंने इसे घर में बनाने की विधि सीख ली।

बट्टाला महा श्मशान घाट में पुजारी ने बताया, केमिस्ट के पास से अल्कोहल खरीदा और एक दुकान से एलोवेरा खरीद कर इन दोनों को 70:30 के अनुपात में कीटाणु नाशक द्रव्य बनाने के लिए मिला दिया। मैं जहां भी जाता हूं घर में बने हुए इस कीटाणु नाशक द्रव्य को साथ ले जाता हूं।' चक्रबर्ती के अलावा इस श्मशान घाट में दो पुजारी हैं और दोनों भी इसी कीटाणु नाशक द्रव्य का इस्तेमाल कर रहे हैं।

> त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने हाल ही में यह स्वीकार किया था कि बाजार में कीटाणु नाशक द्रव्य और मास्क की कमी है। उन्होंने लोगों को हमेशा गमछा रखने की सलाह दी थी ताकि मास्क के अभाव में लोग इससे अपना चेहरा ढक सकें। चक्रबर्ती ने कहा कि इस संकट के समय में लोगों से कहा जाना चाहिए कि वे बड़ी संख्या में अंतिम संस्कार में न आएं।

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने हाल ही में यह स्वीकार किया था कि बाजार में कीटाणु नाशक द्रव्य और मास्क की कमी है। उन्होंने लोगों को हमेशा गमछा रखने की सलाह दी थी ताकि मास्क के अभाव में लोग इससे अपना चेहरा ढक सकें। चक्रबर्ती ने कहा कि इस संकट के समय में लोगों से कहा जाना चाहिए कि वे बड़ी संख्या में अंतिम संस्कार में न आएं।

एक अन्य पुजारी ने बताया कि श्मशान का संचालन करने वाले अगरतला नगर निगम से अपील की गई है कि वे लोगों से अपील करें कि अंतिम संस्कार में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ सात लोग ही हिस्सा लें। हालांकि इस संबंध में नगर निगम का विचार नहीं लिया जा सका।

ये अलग बात है कि अपील के बाद भी श्मशान घाट में बड़ी संख्या में लोगों को अपने रिश्तेदारों और मित्रों के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेते हुए देखा गया।

त्रिपुरा राज्य बिजली निगम के अधिकारी गौतम चक्रबर्ती के पिता का निधन मंगलवार को हो गया था। उन्होंने कहा, हमने अपने संबंधियों को अपने पिता की मौत के बारे में जानकारी दी थी लेकिन उन्हें अंतिम संस्कार में आने से मना किया था लेकिन हमारे आग्रह के बाद भी 13 लोग आए।' वहीं देशव्यापी बंद की वजह से अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होने वाले जरूरी सामान की आपूर्ति भी प्रभावित है।

www.readwhere.com

दिल्ली सरकार ने कोरोना के मद्देनजर बैठक में लिया फैसला

संक्रमितों की फोन से होगी निगरानी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 अप्रैल।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में अब कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए फोन की मदद से निगरानी की जाएगी। निगरानी की जद में संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने वाले लोग होंगे। बुधवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में यह फैसला लिया है। सरकार लोगों के मोबाइल फोन से यह पता लगाएगी कि ऐसे कितने लोग हैं जो घर पर रहने की सलाह के बाद भी लोगों के बीच आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों को एक करोड़ का मुआवजा व राशन के लिए बिना कार्ड वाले लोगों का पंजीयन करने का फैसला लिया है। कुछ देशों ने तकनीक का इस्तेमाल करके कोरोना से बचने की कोशिश की है।

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि सरकार ऐसे सभी लोगों के फोन ट्रेस करेंगे जिन्हें घर में रहने की हिदायत है। ये लोग किसके संपर्क में थे। अब तक सरकार ने 11084 नंबर ट्रेस किए हैं और आज ही में सरकार 14345 के नंबर दे देगी। उन्होंने बताया कि यह वह लोग हैं जिनको सरकार ने आदेश दिया कि आप अपने घर में रहेंगे। घर से नहीं निकलेंगे। लोगों के संपर्क में नहीं आओगे लेकिन सुनने में आया है कि इनमें से कुछ लोग अभी भी सरकारी आदेश को नहीं मान रहे और वह बाहर निकल जाते हैं। इसकी वजह से और लोगों को खतरा है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जिसके बारे में पता चलेगा पुलिस की रिपोर्ट में उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही भी होगी। हमें आगे यह भी देखना पड़ेगा कि वह लोग आगे और कितने लोगों के संपर्क में आए हैं। इन्होंने कितने लोगों को संपर्क किया। उसकी सारी रिपोर्ट आने के बाद हमें पता चलेगा।

निजामुद्दीन मस्जिद के आसपास के इलाके को विषाणुमुक्त करते हुए स्वास्थ्यकर्मी।

मरीजों की संख्या

- 112 मरीज विभिन्न अस्पताल में भर्ती हैं
- पांच मरीजों की अस्पताल से ठीक होने के बाद छुट्टी हुई
- दो लोगों की मौत हो चुकी है
- एक मरीज दिल्ली से सिंगापुर चला गया था
- 120 में से 49 विदेशी लोगों के संक्रमण में आए थे
- 24 मामले निजामुद्दीन के मरकज से मिले
- 29 लोगों को संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से संक्रमण हुआ

निजामुद्दीन मरकज से निकले 2346 लोग, 120 में मिला संक्रमण

मुख्यमंत्री अरविंद अरविंद ने बताया कि निजामुद्दीन इलाके से 2346 लोगों को बुधवार तक मरकज से निकाला है। 120 में संक्रमण मिला है। उन्होंने बताया है कि अब तक 536 अस्पताल में और 1800 से ज्यादा क्वारन्टीन में हैं। अभी स्थिति नियंत्रण में है और सामुदायिक संक्रमण रुका है। उन्होंने कहा कि घर में रहें और सुरक्षित रहें। केवल इससे ही मामलों को बढ़ने से रोका जा सकता है। वहीं, ट्वीट कर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि निजामुद्दीन के आलमी मरकज में 36 घंटे का सघन अभियान चलाकर सुबह चार बजे पूरी बिल्डिंग को खाली करा लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन ने कहा कि यह घोर श्रेणी का अपराध किया है, जबकि देश में आपदा प्रबंधन के प्रावधान लागू थे।

'10 लाख परिवारों को देंगे राशन'

राशन कार्ड नहीं होने पर भी लोगों को राशन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। केवल आवेदन के आधार पर ही यह राशन मिल जाएगा। इसका लाभ 10 लाख लोगों को होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि जिनके राशन कार्ड हैं उनको प्रति व्यक्ति साढ़े सात किलो राशन बांटना शुरू हो गया है। इसका लाभ 71 लाख लोगों को मिलेगा। राशन कार्ड तो बाद में मिलेगा लेकिन पहले राशन मिलना शुरू हो जाएगा। खाद्य एवं वितरण विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं।

स्वास्थ्य कर्मचारियों को मिलेगा सैनिकों जैसा सम्मान : मुख्यमंत्री

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 अप्रैल।

देश के सैनिकों व पुलिस को दिए जाने वाला सम्मान दिल्ली के स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ रहे कर्मचारियों में से अगर किसी की अकस्मात मौत होती है तो दिल्ली सरकार डॉक्टर के परिवार को एक करोड़ का मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री ने दिल्ली के लोगों की तरफ से सभी चिकित्सकों और नर्सों का शुक्रिया अदा किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में स्थिति नियंत्रण में नजर आ रही है। अभी तक सामुदायिक संक्रमण नहीं फैला है। कोरोना संक्रमण के इलाज में लगे होने के दौरान यदि किसी कर्मचारी की जान जाती है तो सरकार एक करोड़ रुपए परिवार को देंगे।

'वेतन देने के लिए दो दिन दिया जाएगा ई-पास'

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब भी आप वेतन देते हैं, आपको दो दिन के लिए वाहन और ई-पास दिया जाएगा। आप जाकर वेतन बना दीजिए और ऑनलाइन सबकी तनख्वाह खाते में डाल दीजिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वेतन काटना नहीं है। सबकी तनख्वाह का समय हो गया है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि तनख्वाह तब देंगे, जब दफ्तर जाकर बनाएंगे। कर्मचारियों की तनख्वाह तो बनानी ही पड़ेगी। जो भी मालिक और उसका अकाउंटेंट है, वह कार्यालय जाकर तनख्वाह बनाएगा, तभी लोगों के खाते में पैसा जाएगा।

इंडोनेशिया की एक जमात सीलमपुर जामा मस्जिद में भी फंसी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 अप्रैल।

निजामुद्दीन मरकज से निकले इंडोनेशिया के नागरिकों की एक जमात सीलमपुर जामा मस्जिद में भी फंस गई थी। विदेशियों को इस जमात को खजूरी सीआरपीएफ कैंप में बनाए गए पृथक केंद्र में रखा गया है। निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज से करीब एक दर्जन इंडोनेशिया के नागरिकों की जमात सीलमपुर की जामा मस्जिद में पहुंची थी। उसी दिन प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था, जिसके बाद ये जमात मस्जिद से बाहर नहीं निकली। सीलमपुर जामा मस्जिद कमेटी के सदस्य ने बताया कि मस्जिद में जमात के लिए अलग से इंतजाम हैं। जमात में विदेशी सदस्य शामिल थे, ऐसे में इनको मस्जिद के अलग बने हिस्से में रखा गया था। पूर्णबंदी की वजह से मस्जिद को भी बंद किया गया था और स्थानीय नागरिक नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं जा रहे थे। उनका कहना है कि जमात के ये साथी किसी भी स्थानीय निवासी के संपर्क में नहीं थे। ये लगातार मस्जिद में ही रुके थे और अपने दूतावास के अफसरों के संपर्क में थे। कमेटी के पदाधिकारियों के मुताबिक इस विदेशी जमात के बारे में लगातार सीलमपुर पुलिस को जानकारी दी जा रही थी।

कोरोना संदिग्ध ने अस्पताल में मचाया हंगामा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली ,1 अप्रैल।

दिल्ली के राजीव गांधी सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल में कोरोना के एक संदिग्ध ने बुधवार दोपहर में आत्महत्या की धमकी देने के साथ जमकर हंगामा किया। इससे अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई। बाद में मरीज को समझाबुझा कर मनाया गया। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक बाद में मरीज को मानसिक चिकित्सक की ओर से भी परामर्श दिया गया है।

अस्पताल के पृथक केंद्र में भर्ती यह मरीज भी निजामुद्दीन से आया है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, मरीज की मानसिक स्थिति संतुलित नहीं थी। दोपहर करीब सवा बारह बजे यह मरीज अपने कमरे की खुली खिड़की पर चढ़ गया और वहां से शोर मचाने लगा कि मुझे बाहर निकालो वरना मैं यहीं से कूद जाऊंगा। इसके जोर-जोर से चिल्लाने से अस्पताल में हड़कंप मच गया।

30 जून तक हो सकेगी ऑटो-टैक्सी मीटर जांच

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली,1 अप्रैल।

दिल्ली के ऑटो, टैक्सी समेत होने वाली माप-तौल की जांच अब 30 जून तक हो सकेगी। दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने बंद के मद्देनजर विभिन्न इकाइयों में किए जाने वाले माप-तौल के सत्यापन और मुद्रांकन की वैधता अवधि तीन महीने के लिए बढ़ा दी है। इसका लाभ गैर-स्वचालित तराजू, तेल की वितरक इकाइयां, टैंक-लॉरी, ऑटो, टैक्सी, सीएनजी व एलपीजी वितरकों को होगा। सरकार ने देरी होने पर लगने वाली जुर्माना राशि में भी राहत का फैसला लिया है।

इन इकाइयों के पास केवल 31 मार्च 2020 तक की ही मान्यता थी। इमरान हुसैन ने बुधवार को गैर-स्वचालित तराजू, तेल की वितरण इकाइयों, टैंक-लॉरी, ऑटो टैक्सी मीटर और सीएनजी, एलपीजी वितरण इकाइयों आदि के वैधानिक सत्यापन और मुद्रांकन के संबंधित विभाग के कामकाज की समीक्षा की। इमरान हुसैन ने परिस्थितियों और जनहित को ध्यान में रखते हुए इस बढ़ी हुई अवधि के लिए वैधानिक सत्यापन और मुद्रांकन की वैधता अवधि समाप्त होने पर दोबारा सत्यापन के दौरान लिए जाने वाला अतिरिक्त शुल्क भी माफ कर दिया गया है।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने बंद के मद्देनजर विभिन्न इकाइयों में किए जाने वाले माप-तौल के सत्यापन और मुद्रांकन की वैधता अवधि तीन महीने के लिए बढ़ाई

दिल्ली के तीन अस्पतालों के चार चिकित्सक कोरोना संक्रमित

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 अप्रैल।

दिल्ली के सफदरजंग, कैंसर संस्थान व पटेल चेस्ट अस्पताल के कुल चार और डॉक्टर कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। इन सभी को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही कैंसर संस्थान को बंद कर संक्रमण रहित करने का काम किया जा रहा है। इसके पहले दिल्ली के दो मोहल्ला क्लिनिक के चिकित्सकों को कोरोना का संक्रमण हो चुका है।

कैंसर संस्थान के बाहर गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मचारी लोगों को मुख्य गेट के बाहर से ही वापस लौटा रहे थे। जब सुरक्षा कर्मचारी से बात की गई, तो उसने बताया कि आज किसी भी व्यक्ति को अस्पताल में जाने की अनुमति नहीं है। अस्पताल में संक्रमण मुक्ति का कार्य किया जा रहा है। प्रशासन से आदेश हैं कि केवल स्टाफ कर्मचारियों को ही अनुमति दी जाए। अस्पताल को एक दिन के लिए ही बंद करने के आदेश हैं। आगे जो भी आदेश दिए जाएंगे, उनका पालन किया जाएगा। अस्पताल में केवल डॉक्टर, नर्स व अन्य जरूरी स्टाफ ही प्रवेश कर सकता है। ज्ञात हो कि दिलशाद गार्डन में पहले भी संक्रमण का मामला सामने आ चुका है। इसके बाद पूरे क्षेत्र में सरकार ने स्क्रिनिंग भी कराई थी। अस्पताल के अतिरिक्त मोहल्ला क्लीनिक के डॉक्टर में भी संक्रमण के मामले आ चुके हैं। इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए सरकार पहले ही इन जगहों पर जाने वाले लोगों को घर में ही 15 दिन रहने के आदेश दे चुकी है ताकि संक्रमण को आगे बढ़ने से रोका जा सके।

मोहल्ला क्लीनिक के बाद सरकारी अस्पताल में संक्रमण

बिन दस्ताने और मास्क के बंट रहा सरकारी खाना

पंकज रोहिला
नई दिल्ली, 1 अप्रैल।

कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। संक्रमण के डर से केंद्र व राज्य सरकारें आम जनता को मुंह पर मास्क और हाथों में दस्ताने पहनने की नसीहत भी दे रही हैं ताकि मामलों को बढ़ने से रोक जा सके। इस अपील का असर दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर नहीं पड़ रहा है। इस वजह से खाना वितरण के काम में जुटे सिविल डिफेंस कर्मचारियों को बिना इन सुविधाओं के काम कर रहे हैं। विभिन्न स्कूलों में खाने के इंतजाम की जांच में यह बड़ा संकट साफ नजर आया।

नहीं मिलते है दस्ताने, मास्क और विषाणुनाशक द्रव्य : खाने की सेवा दे रहे कर्मचारियों को पता है कि कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। सिविल डिफेंस के कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें सरकार की तरफ से दस्ताने व विषाणुनाषक द्रव्य जैसी सुविधा दी जानी चाहिए। इसके लिए एसडीएम समेत अन्य अधिकारियों को भी सूचना है। इससे पहले भी बीते दिनों में कई अधिकारी जांच करके जा चुके हैं। ये केंद्र दिल्ली सरकार ने यमुना विहार, दुर्गापुरी व जाफराबाद में लगाए हैं। इन केंद्र पर कर्मचारी इन सुविधाओं के बिना ही वितरण करते नजर आए। तैनात कर्मचारियों ने बताया कि जब उन्हें सरकार से दस्ताने नहीं मिले तो उन्होंने खुद के खर्च पर ये चीजें खरीदी है।

- नागरिक सुरक्षा के कर्मचारियों के पास जरूरी चीजों की कमी
- अधिकारियों को सूचना भेजने के बाद भी नहीं बदली व्यवस्था
- कोरोना संक्रमण के डर से लोगों ने नहीं बांटने दिया खाना, बदलना पड़ा स्कूल

स्थानीय लोगों ने किया विरोध, बाद में स्थान बदला : उत्तर पूर्वी दिल्ली के अशोक नगर में स्थित एक सरकारी स्कूल में दिल्ली सरकार ने सुबह-शाम खाना देने की योजना तैयार की थी। इस केंद्र पर खाना देने का स्थानीय नागरिकों ने ही विरोध दर्ज कर दिया। लोगों का मानना था कि खाना बांटने से क्षेत्र में भीड़ लगेगी। इस वजह से संक्रमण का खतरा होगा। इसलिए इस केंद्र को एलआइजी के सरकारी स्कूल से हटाकर अशोक नगर के स्कूल में भेजा गया।

जरूरी सामान की कमी को पूरा करेगा उत्तरी रेलवे

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली,1 अप्रैल।

देश भर में मास्क, एप्रेन, विषाणुनाशक द्रव्य और दस्तानों की भारी कमी व मांग को देखते हुए उत्तर रेलवे ने इन सभी चीजों को बनाने का फैसला किया है। इसकी कार्यशालाएं कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। पूरी क्षमता व तेजी के साथ सैनिटाइजर, फेस मास्क, कवरॉल व एप्रेन बनाने का काम शुरू हो चुका है। इसके साथ ही 16 एलएचबी बोगी पहले ही पृथक केंद्र के तौर पर बन रही बोगी में परिवर्तित कर दी गई हैं।

उत्तर रेलवे की ओर से अत्याधुनिक सुविधाओं वाले 20 एलएचबी बोगी बदलकर गैर-वातानुकूलित बोगी में बन कर अब तक तैयार हो गए हैं। यह जरूरत पड़ने पर पृथक केंद्र के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। दो बोगी कल तक पृथक केंद्र कोच के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। उत्तर रेलवे के मुख्य प्रवक्ता दीपक कुमार ने बताया कि कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए सभी उत्तर रेलवे कार्यशालाओं को तैयार किया गया है और इस संबंध में कार्यशालाओं के लिए अहम पहल की गई हैं।

सभी उत्तरी रेलवे कार्यशालाओं को प्रतिदिन 700 लीटर विषाणुनाशक द्रव्य बनाने के लिए तैयार किया गया है। हालांकि कार्यशालाओं में उपलब्ध भंडार 740 लीटर के लिए है। उत्तर रेलवे की दोनों कोचिंग कार्यशाला को प्रतिदिन 700 फेस मास्क बनाने के लिए तैयार किया गया है। अभी तक उत्तर रेलवे में 1600 नग फेस मास्क का निर्माण किया गया है। कार्यशालाओं में अभी 650 मास्क के लिए स्टाक उपलब्ध है।

आरएमएल में ट्रॉमा सेंटर में बनाया गया कोरोना केंद्र

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 अप्रैल।

दिल्ली के राममनोहर लोहिया अस्पताल में महिला व बच्चों के वार्ड के बीच बने कोरोना वार्ड को अब यहां से हटा दिया गया है। अब इसे बाहर की ओर बने आरएमएल ट्रॉमा सेंटर में स्तानांतरित किया गया। इसके साथ ही एक और इमारत को खाली किया जा रहा है जहां कोरोना मरीजों को रखने का इंतजाम किया जाएगा। हालांकि अभी तक कोरोना से संक्रमित मरीज के संपर्क में आए लोगों का कुछ पता नहीं लगाया गया है।

आरएमएल अस्पताल में महिला व बच्चों के वार्ड को बीच में बने कोरोना वार्ड से दूसरे मरीजों को संक्रमण के खतरे की बावत जनसत्ता में छपी खबर पर संज्ञान लेते हुए अस्पताल प्रशासन ने दूसरे मरीजों के बीच से कोरोना वार्ड को हटा दिया है।

फैसला | ई-कॉमर्स कंपनियों को साथ जोड़ने की पहल शुरू

कोरोना संक्रमण : दूधिया से बनी दूरी, मदर डेयरी की मांग बढ़ी

प्रियरंजन
नई दिल्ली, 1 अप्रैल।

पूर्णबंदी के दौरान हर घर का ध्यान रसोई पर है। इन दिनों सही दाम पर दूध, दही पनीर, फल, सब्जियां आदि की आपूर्ति बड़ी चुनौती बन चुकी है। दिल्ली एनसीआर में दूध की मांग में बेतहाशा वृद्धि हुई है। पूर्णबंदी के बाद दिल्ली-एनसीआर में मदर डेयरी के दूध की मांग छह लाख लीटर तक बढ़ी है। आमतौर पर जो मांग व आपूर्ति 28-30 लाख लीटर तक रहती है। लेकिन अब यह मांग 36 लाख लीटर तक पहुंच गई है। मदर डेयरी के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की। जन जन तक पहुंचने के उद्देश्य में खरा उतरने के लिए मदर डेयरी ने कुछ और पहल की है। ताकि आपूर्ति श्रृंखला की दुरुस्तगी बनी रहे। आने वाले दिनों में आपूर्ति श्रृंखला को और मजबूत करने के लिए मदर डेयरी ने ई-कॉमर्स कंपनियों को साथ काम करने के ऑफर भी दिए हैं। इस बाबत मदर डेयरी के वरिष्ठ महाप्रबंधक रूपाराम चौधरी की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है कि ई-कामर्स कंपनियां और मदर डेयरी मिलकर ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक अपनी पहुंच बना सकते हैं।

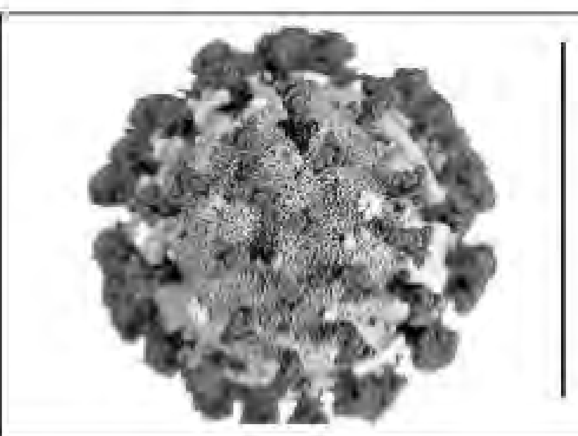

पूर्णबंदी के बाद दिल्ली-एनसीआर में मदर डेयरी के दूध की मांग छह लाख लीटर तक बढ़ी है। आमतौर पर जो मांग व आपूर्ति 28-30 लाख लीटर तक रहती है। लेकिन अब यह मांग 36 लाख लीटर तक पहुंच गई है। मदर डेयरी के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की

मदर डेयरी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कोरोना विषाणु के प्रसार के कारण दिल्ली में भी असामान्य स्थिति है। मदर डेयरी ने प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों से आग्रह किया है कि दिल्ली-एनसीआर में दूध की सुचारु आपूर्ति बनाए रखने के लिए हमें मिलकर एक टीम के रूप में काम करना चाहिए। मदर डेयरी के प्रवक्ता ने कहा कि पहले से ही विभिन्न स्थानों पर हम लोगों ने भागीदारी के तहत एक साथ काम किए हैं। किसानों-पशुपालकों को जोड़ा है। मौजूदा परिदृश्य में और समय की जरूरत के तहत हमने ई-कामर्स दिग्गजों के साथ सहयोग को और मजबूत करने की पहल की है। जहां कुछ राज्य सरकारों ने जरूरी वस्तुओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसी को देखते हुए ई-कामर्स कंपनियों के साथ जुड़ने के प्रस्ताव के साथ जुड़कर मदर डेयरी ने भंडार को बरकरार रखने और संचालन की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान लगाया है।

जनता का सहकारी तंत्र पर भरोसा ज्यादा

मौजूदा हालात में दिल्ली के जरूरी सामानों खासकर फल-सब्जियों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी और संक्रमण के खतरे की आशंका के कारण इन दिनों लोग मदर डेयरी के सफल की दुकानों में ज्यादा पहुंच रहे हैं। वायरस की आशंका से लोगों ने रोज आने वाले दूधिया या खटाल से दूरी बना ली है। मदर डेयरी का रूख कर लिया है। कालकाजी के गिरीनगर स्थित इन दुकानों की गोल घेरे वाली लाइन में खड़ी अर्चना ने कहा-भले नंबर आधे घंटे बाद आए लेकिन सेफ चलूंगी। ऐसा सोचने वाली अर्चना अकेली नहीं हैं। अब तक रेहड़ी वालों से सब्जियां लेने वालों में शामिल कई गृहणियों का दावा है कि संक्रमण और कालाबाजारी के इस दौर में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड सहायक साबित हुआ है।

अधिकारी के मुताबिक, पूर्णबंदी के बाद एक दिन में 36 लाख लीटर तक दूध की मांग की पूर्ति की गई, जो एक रिकार्ड है, जबकि पूर्णबंदी से ठीक पहले यह 20-30 लाख लीटर प्रतिदिन ही थी।

उन्होंने कहा-हम अपनी पूरी क्षमता से काम करने के लिए तैयार हैं। कई ऐसे मौके आए, जब हमने लगभग 36 लाख लीटर प्रतिदिन दूध की सुचारू आपूर्ति की। इतना ही नहीं अपनी क्षमता को 10 फीसद और अधिक बढ़ा सकते हैं। दरअसल इस समय मदर डेयरी अपने सभी 850 ऑपरेटिंग बूथों पर दूध और दूध उत्पादों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखने के जुगत में है। उन क्षेत्रों में रहने वाले ग्राहकों तक पहुंचने के प्रयास में जहां दूध के बूथ मौजूद नहीं हैं।

www.readwhere.com

मौसम

तापमान	नोएडा		गाजियाबाद		गुरुग्राम		फरीदाबाद	
अधिकतम	32.7	डि.से.	32.7	डि.से.	32.8	डि.से.	32.8	डि.से.
न्यूनतम	17.4	डि.से.	17.4	डि.से.	27.0	डि.से.	17.4	डि.से.

जनसत्ता, नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2020 4

निजामुद्दीन मरकज में हुए थे शामिल

48 लोगों को किया गया अलग-थलग

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 1 अप्रैल।

दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में आयोजित तबलीगी जमात से आए कुछ लोगों के दादरी, दनकौर व रबूपुरा क्षेत्र में ठहरे होने की सूचना पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने आनन फानन में इनकी तलाश शुरू कर दी। ग्रेटर नोएडा इलाके से 48 लोगों को पृथक किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ऐसे लोगों को भी चिह्नित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो इनके संपर्क में आए थे। पृथक किए गए 48 लोगों में से 17 झारखंड और एक सहारनपुर के रहने वाले हैं।

दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में पिछले दिनों हुए तबलीगी जमात में शामिल लोगों में कोरोना की पुष्टि होने पर दिल्ली समेत पूरे देश में हड़कंप मच गया है। इस बीच गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन को सूचना मिली कि दनकौर, दादरी, जारचा, रबूपुरा व जेवर के कुछ लोग भी जमात में शामिल होकर आए हैं। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम गांवों में पहुंची और जमात से आए सभी लोगों को पृथक केंद्रों तक पहुंचाया।

निजामुद्दीन मसजिद के पास के इलाकों को विषाणुमुक्त करने के बाद अपने सहयोगियों को विषाणुमुक्त करता स्वास्थ्यकर्मी

डीसीपी ग्रेटर नोएडा राजेश कुमार सिंह ने बताया कि दनकौर के अट्टा फतेहपुर गांव में 10 और ऊंची दनकौर गांव में एक व्यक्ति जमात के कार्यक्रम में शामिल हुआ था। जेवर क्षेत्र से पांच, दादरी से 11, जारचा से तीन और रबूपुरा क्षेत्र में ठहरे हुए 18 लोग दिल्ली जमात व इस तरह के अन्य कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। रबूपुरा से मिले 18 लोगों में 17 झारखंड व 1 सहारनपुर के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि झारखंड और सहारनपुर के रहने वाले लोग गन्ने के खेत में छिपकर रह रहे थे। डीसीपी ने बताया कि ग्रेटर नोएडा क्षेत्र से अब तक 48 लोगों को पृथक करा दिया गया है। एहतियात के तौर पर ऐसे लोगों को भी चिह्नित किया जा रहा है, जो इनके संपर्क में आए हैं।

पूर्ण बंदी के दौरान दुर्घटना में गई युवक की याददाश्त

पूर्णबंदी के चलते दुर्घटना में घायल हुए एक युवक के घर में खाने तक के लाले पड़ गए हैं। घायल युवक याददाश्त खो चुका है। वह परिवार में अकेला कमाने वाला था। पीड़ित परिवार मूलरूप से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लोकसभा क्षेत्र अमेठी का रहने वाला है। परिवार की स्थिति के बारे में जानकारी होने पर सामाजिक संगठन के लोग मदद के लिए आगे आए। पीड़ित परिवार केंद्रीय मंत्री से मदद की गुहार लगाई है।

उत्तर प्रदेश के जिला अमेठी के हरिकनपुर गांव निवासी अमित भारद्वाज (30) करीब चार महीने पहले नौकरी करने के लिए ग्रेटर नोएडा आए थे।

वह क्षेत्र के कस्बा दनकौर के पास स्थित एक टाइल बनाने वाली फैक्टरी में काम करते थे। अमित भारद्वाज अपने पिता जमुना प्रसाद, माता शिव कुमारी, पत्नी वंदना व दो बच्चों के साथ कस्बा बिलासपुर में किराये के मकान में रहते हैं। बताया गया है कि गत 7 मार्च को वह फैक्टरी से घर लौट रहे थे। तभी किसी वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल अमित भारद्वाज की याददाश्त चली गई। घर में जो जमा पूंजी तो परिजन इलाज में खर्च कर चुके हैं। परिवार में अमित भारद्वाज ही अकेले कमाने वाले हैं। दुर्घटना के बाद परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इस बीच लागू हुई पूर्णबंदी के चलते परिवार पर और संकट आ गया। इसकी जानकारी मीडिया को हुई तो पीड़ित परिवार के बारे में समाजसेवियों व स्थानीय विधायक को हुई। डॉ.अदिति भाटी से पीड़ित परिवार की बात कराकर उनके लिए दवाई मुहैया कराई। सामाजिक संगठन के लोगों ने घर पहुंचकर पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद व खाद्य सामग्री भी दी। पीड़ित परिवार ने अमेठी की सांसद व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से भी मदद की गुहाई लगाई है। वहीं, स्थानीय विधायक धीरेंद्र सिंह ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है।

कामगारो के खाते में बैंक पहुंचाएंगे राशि

आज गौतम बुद्ध नगर की 499 शाखाएं खुली रहेंगी

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 1 अप्रैल।

पूर्ण बंदी के दौरान गरीब, मजदूरों, किसानों को केंद्र व राज्य सरकार की ओर से सहायता राशि जारी करने का काम शुरू कर दिया गया है। यह सभी सहायता मनरेगा, किसान राहत, जनधन समेत अन्य माध्यमों से सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जा रही है। इस दौरान लोगों को नकदी की दिक्कत ना हो, इसके लिए बैंक शाखाओं के संचालन में बदलाव किया गया है। अब सुबह दस से शाम चार बजे तक बैंक शाखाएं पहले की ही काम करेंगी। इसके चलते उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर राम नवनी के अवकाश को भी स्थगित कर दिया गया है। गुरुवार को जिले में 41 बैंकों की 499 शाखाओं को खोला जाएगा।

एसबीआइ दिल्ली सर्कल उप महासचिव अमर कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शासन के निर्देश पर 24 से 30 मार्च तक बैंकों के संचालन समय में बदलाव किया गया था। सुबह दस से दोपहर दो बजे तक ही बैंकों को खोला जा रहा था, लेकिन 30 मार्च को शासनादेश जारी हुआ है। अब इसमें बदलाव किया गया है। दो अप्रैल से बैंक सुबह दस से शाम चार बजे तक खोले जाएंगे। एक अप्रैल को वित्तीय वर्ष 2019-20 समाप्ति के चलते जनता का कार्य शाखाओं में नहीं हुआ। गुरुवार से व्यवस्था पूर्व की भांति सुचारू रहेगी।

लीड बैंक प्रबंधक वेद रतन ने बताया कि जिले में 12 सरकारी व 29 निजी एवं कॉपरेटिव बैंक हैं। जिनकी 499 शाखाएं गुरुवार को रामनवमी के दिन भी खोली जाएंगी। यह फैसला शासन ने इसलिए लिया है कि मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर का काम चल रहा है।

दमकल से किया जाएगा विषाणुरहित

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 अप्रैल ।

दिल्ली के संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों, पृथक केंद्र, अस्पतालों, कोरोना के रोगियों/संदिग्धों के आस-पास के स्थानों को विषाणुरहित करने के लिए दमकल का उपयोग किया जाए। उपराज्यपाल ने यह भी निर्देश दिए हैं कि उन्होंने बुधवार को समीक्षा बैठक में कहा कि यह कार्य जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निगरानी में किया जाए। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव, अतिरिक्त सचिव, गृह, दिल्ली पुलिस आयुक्त, सचिव (स्वास्थ्य) और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

पृथक केंद्र, अस्पतालों, कोरोना के रोगियों/संदिग्धों के पास के स्थान शामिल

खाना वितरण

पूर्ण बंदी के बीच रेलवे सुरक्षा बल के कर्मी जरूरतमंदों के बीच खाना बांटते हुए

आबादी 22 लाख, वेंटिलेटर केवल 177

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 1 अप्रैल।

कोरोना विषाणु के बढ़ते मरीजों की संख्या के चलते शहर में भी वेंटिलेटर समेत अन्य उपकरणों की मांग बढ़ रही है। हालांकि अब तक जितने मरीज भर्ती हुए है उनके इलाज में वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ी है। लेकिन जरूरत पड़ने पर इसकी आपूर्ति करने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। बताया गया कि केवल पांच फीसद मरीजों में ही वेंटिलेटर की आवश्यकता हो सकती है।

गौतमबुद्धनगर की आबादी करीब 22 लाख है। यहां दो सरकारी अस्पताल के अलावा कई सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। ग्रेटरनोएडा के जिम्स व नोएडा के चाइल्ड पीजीआइ में पृथक वार्ड बनाए गए है। इसके अलावा निजी अस्पताल है। जिनमें पहले से अन्य बीमारियों के मरीज भर्ती है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शहर के अस्पतालों में कुल 177 वेंटिलेटर है। इनमें से अधिकांश मरीजों के इलाज में इस्तेमाल हो रहे हैं। हालांकि कोविड-19 के लिए कुछ वेंटिलेटरों को आरक्षित रखा गया है।

गौतम बुद्ध नगर में भर्ती मरीजों को फिलहाल वेंटिलेटर की जरूरत नहीं

महज पांच फीसद संक्रमित मरीजों को पड़ती है वेंटिलेटर की जरूरत

डीएम ने बताया कि यह अच्छी बात है कि शहर में संक्रमित किसी मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ने पर एतिहातन तैयारी की जा चुकी है। वहीं, क्षेत्रीय सांसद डॉ. महेश शर्मा ने सेक्टर-40 में बनाए गए पृथक केंद्र, गुडविल अस्पताल का निरीक्षण किया। आइएमए के अध्यक्ष डॉ. एनके शर्मा ने बताया कि इस अस्पताल में पृथक वार्ड बनाने की योजना है।

कोरोना मरीजों के लिए क्यों जरूरी है वेंटिलेटर

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक, कोविड-19 से संक्रमित 80 फीसद मरीज अस्पताल गए बिना ठीक हो जाते हैं लेकिन औसतन छह में से एक मरीज की स्थिति गंभीर हो जाती है और उसे सांस लेने में मुश्किल आने लगती है।

ऐसे मरीजों में विषाणु रोगी के फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। फेफड़ों में पानी भर जाता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है इसलिए वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। इसके जरिए मरीज के शरीर को समान्य मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच जाती है।

पूर्ण बंदी : शराब की आपूर्ति करते दो तस्कर गिरफ्तार

फरीदाबाद, 1 अप्रैल।

पूर्ण बंदी के दौरान शराब ठेके बंद होने के चलते शराब तस्करों की बढ़ती गतिविधियों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस की अपराध शाखा ने दो शराब तस्करों को दबोच कर इनके कब्जे से 405 पेटी शराब की बरामद की है। ये लोग दो गाड़ियों में शराब भरकर ले जा रहे थे। पुलिस ने तस्करों के खिलाफ आबकारी कानून के तहत और बंद की उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक को एक दिन के पुलिस रिमांड पर और दूसरे को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले हैं। यह जानकारी पुलिस प्रवक्ता सुबे सिंह ने दी है। अपराध शाखा ने आरोपियों से 300 पेटी देसी शराब, 84 पेटी अंग्रेजी शराब और 21 पेटी बियर बरामद की गई है।

अपराध शाखा के एसीपी अनिल यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए तस्करों के नाम दीपक और राजेश है। दीपक बिहार के फरीदाबाद का निवासी है। वहीं, राजेश उत्तर प्रदेश के जिले गोरखपुर हाल निवासी शास्त्री कॉलोनी बल्लभगढ़ का रहने वाला है।

अपराध शाखा प्रभारी सेक्टर-65 एसआइ लाजपत ने बताया कि सूचना के आधार पर नाकाबंदी कर दोनों आरोपियों को अलग अलग गाड़ियों सहित आकाश सिनेमा के नजदीक से गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा थाना आदर्श नगर बल्लभगढ़ में दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों को बुधवार को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी राजेश को एक दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया और आरोपी दीपक को जेल भेज दिया है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि एक तरफ जहां पुलिस की अपराध शाखा पूर्ण बंदी के दौरान फरीदाबाद में जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचा रही है वहीं दूसरी तरफ सौ नाके लगा कर अपराधिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखे हुए हैं।

पूर्ण बंदी के बीच एनडीएमसी के सामने चुनौती

लुटियंस जोन की हरियाली को बचाएं कैसे

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 अप्रैल।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद की कोरोना विषायु के खिलाफ जंग जारी है। परिषद की जंग न केवल कोरोना विषाणु के खिलाफ है बल्कि पुरानी लुटियंस की हरियाली की विरासत को बचाने के लिए भी है। कोरोना विषाणु संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए देश में लागू की गई पूर्ण बंदी के परिणाम स्वरूप, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) का बागवानी विभाग आजकल लुटियंस दिल्ली की हरियाली को बचाए और बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है । इस बीमारी के खतरे के बावजूद पार्कों और उद्यानों में स्वच्छ वातावरण बनाए रखना भी किसी चुनौती से कम नहीं है और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पालिका परिषद की बागवानी की समर्पित टीम तत्परता से कार्यरत है, जिस के कारण इसकी देश में एक विशिष्ठ पहचान है।

नई दिल्ली क्षेत्र में एक सदी पुरानी लुटियंस द्वारा स्थापित हरियाली का बचाव अब एक व्यापक प्रयास है, जिसमें 1500 एकड़ का हरित क्षेत्र, 135 ग्रीन एवेन्यू, 10 प्रमुख पार्क, 1400 आवासीय कॉलोनी पार्क, 52 गोलचक्कर ,10 विभागीय नर्सरी शामिल हैं। इसमें 3 हाई-टेक नर्सरी, 3 अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्मारक पार्क, 3 खुशहाली क्षेत्र और प्रतिष्ठित गार्डन जैसे नेहरू पार्क, लोदी गार्डन, तालकटोरा गार्डन और संजय झील, चिल्ड्रन पार्क, इंडिया गेट, सेंट्रल पार्क, कनॉट प्लेस, सीडब्ल्यूजी पार्क, शांति पथ इत्यादि शामिल है। इन सबकी देखरेख और रखरखाव का दायित्व नई दिल्ली नगरपालिका परिषद का एक महत्वपूर्ण कार्य है।

गंभीर रोगजनक कोरोना विषाणु को नियंत्रित करने के लिए देशव्यापी पूर्ण बंदी के कारण, पालिका परिषद स्टाफ सहित हर कोई घर पर रहने के लिए बाध्य है। हालांकि, लुटियंस दिल्ली की हरियाली के रखरखाव के महत्व को देखते हुए, यहां की हरियाली को बचाने के लिए पालिका परिषद अपने न्यूनतम कर्मचारियों की तैनाती कर रहा है। इस आवश्यक सेवा के लिये प्रतिदिन कुल कर्मचारियों में से 25 फीसदी को रोस्टर में तैनात करने की योजना बनाई गई है। यह देखा गया है कि इस महत्वपूर्ण समय में किसी भी कार्य में अंतराल आने से, जैसे स्वच्छता कार्यों के ठहराव, प्राथमिकता वाले क्षेत्र में रखरखाव के कारण स्थिति और अधिक खराब हो सकती है। पूर्ण बंदी के अंत तक प्रतीक्षा करने से निश्चित रूप से हरियाली में भारी अपूरणीय क्षति हो सकती थी। इसलिए, पालिका परिषद के उद्यान विभाग द्वारा बागवानी की आवश्यक सेवाओं को निरंतर जारी रखना जरूरी माना गया ।

पालिका परिषद के कर्मचारियों में व्यक्तिगत आत्म-स्वच्छता उपायों को अच्छी तरह से ध्यान में रखा जा रहा है। माली / बागवानों को मास्क पहनने, साबुन से हाथों को बार-बार धोने, विषाणुनाशक से हाथों को बार-बार रगड़ने, सामाजिक दूरी बनाए रखने आदि जैसे तरीकों को अपनाने से अत्यधिक आत्म-सुरक्षित और सतर्क रहने के लिए शिक्षित किया जा रहा है। इसको उच्चाधिकारियों द्वारा लगातार निगरानी करके सुनिश्चित भी किया जा रहा है। सभी व्यक्तिगत सुरक्षा उपाय और उपकरण आवश्यक सेवा के फील्ड कर्मचारियों को दिए गए हैं।

प्रांतीय प्रवासी संगठन ने बुराड़ी में बांटे खाने के पैकेट

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 अप्रैल।

अखिल भारतीय प्रान्तीय प्रवासी एवं दलित विकास मंच ने प्रधानमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल और अन्य राज्यों के संबंधित मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया है कि वे प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था उसके जगह पर ही करें। मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल झा ने कहां है कि प्रांतीय प्रवासी मजदूर दिल्ली के सारे इलाकों में रहते हैं। उनके लिए भोजन पैकेट का बंदोबस्त बहुत जरूरी है। बुराड़ी विधानसभा इलाके में अपनी ओर से उन्होंने कई हजार लोगों को खाने के पैकेट वितरित किए। झा ने बुधवार को सुबह से शाम तक अपने कार्यकताओं के साथ बुराड़ी, जहांगीरपुरी, जीटीबी नगर और आसपास के इलाके में प्रवासी मजदूर और जरूरतमंदों के बीच खाने के पैकेट वितरित किए। उन्होंने कहा कि सरकार को इसी तरह के पैकेट्स दिल्ली के कोने-कोने में वितरित करने की आवश्यकता है!

खबरों में शहर

'सफाईकर्मियों की तनख्वाह तुरंत दे दिल्ली सरकार'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 अप्रैल।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. नरेश कुमार ने उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को एक ज्ञापन देकर मांग की है कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के स्वास्थ्यकर्मियों और सफाईकर्मियों की तनख्वाह तुरंत दी जानी चाहिए। उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि यह स्वास्थ्यकर्मी और सफाईकर्मी अपनी जान हथेली पर रखकर दिन-रात दिल्ली को साफ-सुथरा रखने का काम कर रहे हैं ताकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ा जा सके। वहीं इन लोगों को तीन-तीन महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के अंदर करीब 47 हजार एमसीडी के कर्मचारी हैं और इनमें ज्यादातर स्वास्थ्यकर्मी और सफाईकर्मी हैं।

संपत्तिकर आम माफी योजना 30 जून तक बढ़ाई

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 अप्रैल।

पूर्वी दिल्ली की महापौर अंजु कमलकांत ने कहा है कि कोरोना विषाणु संक्रमण की स्थिति को देखते हुए पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर आम माफी योजना 2019-20 को 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया है। इसके तहत पूर्वी दिल्ली नगर निगम अपने अधिकार क्षेत्र में संपत्तिकरदाताओं को बकाया संपत्तिकर के ब्याज और जुर्माने में सौ फीसद की छूट दे रहा है। महापौर ने कहा कि इस संबंध में जरूरी आदेश जारी कर दिए गए हैं। महापौर ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन होने से नागरिक आम माफी योजना का पूर्ण लाभ नहीं उठा पा रहे थे जिसके चलते आम माफी योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। महापौर ने नागरिकों से आम माफी योजना को लाभ उठाने की अपील की। साथ ही, यह भी फैसला लिया गया है कि तृतीय निगम मूल्यांकन समिति (एमवीसी-3) की सिफारिशों के लागू होने के कारण संपत्ति कर में हुई वृद्धि को नगण्य करने के लिए 2019-20 में प्रदान की गई प्रभावी छूट 2020-21 में भी यथावत लागू रहेगी।

232 बहुंमजिला इमारतों को किया गया विषाणुमुक्त

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 1 अप्रैल।

कोरोना विषाणु के संक्रमण से शहर को मुक्त बनाने के लिए प्राधिकरण युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। अब तक 232 बहुंमजिला भवनों को पूर्ण रूप से विषाणुमुक्त किया जा चुका है। इसके अलावा जहा भी संक्रमित व्यक्ति मिल रहे है उस क्षेत्र को तत्काल विषाणुमुक्त किया जा रहा है।

शहर को पांच जोन और 26 उप क्षेत्रों में बांटकर 80 गांव व 160 सेक्टरों को विषाणुमुक्त करने का काम किया जा रहा है। इस कार्य के लिए 2800 सफाई कर्मचारी, संविदाकार व 1600 सफाई कर्मचारी श्रम आपूर्ति के माध्यम से काम कर रहे हैं। इसके अलावा 600 कर्मचारी घर-घर से कूड़ा एकत्र करने वाली संस्था के माध्यम से 50 टैंकर व 200 मानवचलित स्प्रे मशीन विषाणुमुक्त करने का काम कर रही हैं। वहीं, आवासीय, व्यवसायिक, संस्थागत व औद्योगिक संस्थाओं से निकलने वाले कूड़े को घरों एवं संस्थानों से 200 वाहन व 650 कर्मचारी प्रतिदिन काम कर रहे है। नगरीय सुविधाओं के लिए प्राधिकरण ने 24 घंटे शिकायते प्राप्त करने के लिए कॉल सेंटर स्थापित किया है। यहां आठ-आठ घंटो की पाली में विशेषाकार्यधिकारी की निगरानी में नौ ऑपरेटर काम कर रहे है।

'हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य हिस्सा संपेरा समुदाय'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 अप्रैल ।

प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री सिद्धार्थन ने आज कहा कि संपेरा जाति के लोग हमारी महान और गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं। इस समुदाय ने हमारे प्राचीन वाद्य यंत्र बीन वादन की परम्परा को न केवल कायम रखा है, बल्कि देश और दुनिया में इसको प्रतिष्ठित भी किया है। उन्होंने बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के मोलड़बन्द गांव में प्रतिपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी के साथ मिलकर संपेरा जाति के लोगों के बीच राशन और अन्य सहायता सामग्री बांटी।

www.readwhere.com

तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों ने डॉक्टरों पर थूका

नई दिल्ली, 1 अप्रैल (भाषा)।

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में रेलवे के पृथक केंद्रों में रखे गए, तबलीगी जमात के कार्यक्रम से जुड़े करीब 160 लोगों ने उनकी जांच कर रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया और यहां तक कि उन पर थूका भी। रेलवे के एक प्रवक्ता ने बुधवार को यह बात कही।

निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों में से 167 को मंगलवार की शाम तुगलकाबाद में रेलवे के पृथक केंद्रों में लाया गया था। सूत्रों ने बताया कि रेलवे के केंद्र में इन 167 लोगों को रखे जाने के बाद रेलवे कॉलोनी के लोगों ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। इस पर वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थानीय अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया।

उत्तर रेलवे के प्रवक्ता दीपक कुमार ने कहा, 'पृथक केंद्रों में उन्होंने (निजामुद्दीन मरकज से निकालकर लाए गए लोगों ने) स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार किया और खुद को दिए जा रहे भोजन को लेकर आपत्ति जताई...यहां तक कि उन्होंने उन्हें देख रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों पर थूक तक दिया। इन लोगों ने पृथक केंद्रों में इधर-उधर घूमना बंद करने से भी मना कर दिया।'

रेलवे कॉलोनी के लोगों ने आरोप लगाया कि मरकज से वहां लोगों को लाए जाने के 24 घंटे बाद भी कॉलोनी को संक्रमण मुक्त नहीं किया गया है। वायरस के प्रसार के डर से निवासी घरों के अंदर रहे और आवश्यक चीजें लेने भी बाहर नहीं जा पाए।

कुमार ने कहा, 'हमने जिलाधिकारी दक्षिण-पूर्वी दिल्ली को सूचना दी और उन्हें (पृथक केंद्रों में रखे गए लोगों) नियंत्रित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा करने या इन्हें किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर भेजने का आग्रह किया। शाम साढ़े पांच बजे दिल्ली पुलिस के चार और सीआरपीएफ के छह जवानों और एक पीसीआर वैन को पृथक केंद्रों पर तैनात किया गया। जिला अधिकारियों ने इन लोगों में से 97 को डीजल शेड ट्रेनिंग स्कूल हॉस्टल पृथक केंद्र और 70 को आरपीएफ बैरक पृथक केंद्र में रखा गया है।

रेलवे कॉलोनी के लोगों ने आरोप लगाया कि मरकज से वहां लोगों को लाए जाने के 24 घंटे बाद भी कॉलोनी को संक्रमण मुक्त नहीं किया गया है। वायरस के प्रसार के डर से निवासी घरों के अंदर रहे और आवश्यक चीजें लेने भी बाहर नहीं जा पाए। कॉलोनी के एक निवासी ने कहा, 'बस के पास खड़े बहुत से लोगों ने खांसा, छींक मारी और यहां तक कि सड़क पर थूका भी। हम कैसे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं?' सूत्रों ने बताया कि रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मुद्दे पर पहले ही जिले के अधिकारियों से बात कर चुके हैं।

'तबलीग के कार्यक्रम में शामिल 72 विदेशियों सहित 503 लोगों का पता लगा'

चंडीगढ़, 1 अप्रैल (भाषा)।

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बुधवार को बताया कि दिल्ली स्थित निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए 72 विदेशियों सहित 503 लोगों का राज्य में पता लगाया गया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा पुलिस द्वारा गुरुग्राम और अंबाला सहित विभिन्न जिलों में उनकी उपस्थिति का पता लगाने के बाद स्वास्थ्य दल अपना काम कर रहा है।

इनके हरियाणा में प्रवेश करने का उद्देश्य पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में शामिल होने के बाद इन्हें देशभर के विभिन्न इलाकों में तकरीर देने की जिम्मेदारी दी जाती है।

अफगानिस्तान गुरुद्वारा हमले की एनआइए करेगी जांच

नई दिल्ली, 1 अप्रैल (भाषा)।

राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) पिछले महीने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल स्थित गुरुद्वारे पर हुए हमले की जांच करेगी जिसमें भारतीय नागरिक सहित 27 लोगों की मौत हुई। एजंसी ने बुधवार को इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की जो विदेश में एनआइए द्वारा जांच किया जाने वाला पहला मामला है।

एजंसी की ओर से जारी बयान के मुताबिक, एनआइए कानून में संशोधन के बाद यह अपने तरह का पहला मामला है।

संशोधित कानून में एनआइए को देश के बाहर किसी भी ऐसे मामलों की जांच करने के लिए सशक्त किया गया है जिसमें भारतीय या भारत का हित प्रभावित हुआ हो।

एजंसी ने बताया कि मामला भारतीय दंड संहिता और आतंकवाद निरोधी कानून के धाराओं के तहत दर्ज किया गया है।

बताते चलें कि 25 मार्च को हुए हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोविंस (आइएसकेपी) ने ली थी।

रूस के 400 से अधिक नागरिक वापस लौटे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 अप्रैल।

भारत में फंसे रूस के 400 से अधिक नागरिक बुधवार को विशेष विमान से वापस अपने देश लौट गए। नई दिल्ली स्थित रूस के शीर्ष राजनयिक ने यह जानकारी दी। फंसे हुए रूसी नागरिकों को लेकर नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाला यह चौथा विमान था। भारत में रूस के राजदूत निकोलाय कुदशेव ने एक बयान में कहा, आज हमने 400 रूसी नागरिकों को मॉस्को जाने वाले विमान में सवार कर अलविदा किया। यह हमारे हमवतनों को घर वापस ले जाने वाली चौथी उड़ान थी। इस मिशन को कई एजंसियों के सहयोग से पूरा किया गया।

तबलीग समर्थकों के हमले में चार पुलिसकर्मी घायल

मधुबनी, 1 अप्रैल (भाषा)।

बिहार के मधुबनी जिले के अंधराथाडी थाना अंतर्गत गिदड़गंज गांव में तबलीगी जमात के समर्थकों द्वारा किए गए कथित पथराव में चार पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। ग्रामीण लॉकडाउन का उल्लंघन कर 'दीनी मजलिस' का आयोजन कर रहे थे और पुलिस की टीम उन्हें मना करने गई थी।

पुलिस अधीक्षक सत्य प्रकाश ने बुधवार को बताया कि तत्काल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उक्त मजलिस में शामिल हुए लोग क्या दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज के कार्यक्रम में शामिल होकर लौटे थे। उन्होंने बताया कि मंगलवार देर रात पुलिसकर्मियों पर पथराव करने वालों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है।

इस बीच , बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने अपने ट्विटर हैंडल पर दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज के कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों से अपील की है कि वे हेल्पलाईन नंबर पर फोन करें या नजदीकी सरकारी अस्पतालों में जाकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण करा लें।

बिहार में अब तक 81 लोगों की पहचान की गई है जो दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में मरकज कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उनमें से पटना और बक्सर जिलों में कुल 30 लोगों की पहचान कर उनकी जांच की जा रही है।

PUBLIC ANNOUNCEMENT
THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, INTO THE UNITED STATES OR OUTSIDE INDIA.

refex

REFEX INDUSTRIES LIMITED

Our Company was incorporated as a private limited company under the Companies Act, 1956 in the name of 'Refex Refrigerants Private Limited' vide a certificate of incorporation dated September 13, 2002 issued by the Registrar of Companies, Tamil Nadu at Chennai ("**RoC**"). Thereafter, our Company was converted into a public limited company and the name of our Company changed to 'Refex Refrigerants Limited' and a fresh certificate of incorporation was issued by the RoC on March 30, 2006. Subsequently, the name of our Company was changed to 'Refex Industries Limited' and a fresh certificate of incorporation was issued by the RoC on November 22, 2013. For further details relating to change in the registered office address of our Company, please see "*History and Corporate structure*" on page 50 of the Draft Letter of Offer ("**DLOF**").

Registered and Corporate Office: 11th Floor, Bascon Futura IT Park, New No. 10/2, Old No. 56L, Venkat Narayana Road, T Nagar, Chennai 600 017, Tamil Nadu.
Contact Person: S. Gopalakrishnan, Company Secretary & Compliance Officer; **Telephone:** +91 44 4340 5950; **E-mail:** admin@refex.co.in; **Website:** www.refex.co.in
Corporate Identification number: L45200TN2002PLC049601

OUR PROMOTERS: MR. ANIL JAIN, MR. TARACHAND JAIN AND M/S SHERISHA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

ISSUE OF UPTO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ [•]) PER EQUITY SHARE ("RIGHTS EQUITY SHARES") FOR AN AMOUNT AGGREGATING UPTO ₹2,500 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF [•] RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY [•] FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY SUCH ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON [•] (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 138 OF THE DLOF.

THE ISSUE PRICE OF EACH RIGHTS EQUITY SHARE IS [•] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE.

This Public Announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 72(2) of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 as amended (the "**SEBI ICDR Regulations**"), to inform the public that our Company is proposing, subject to requisite approvals, market conditions and other considerations, an issue of Rights Equity Shares to its eligible equity shareholders on rights basis and has on March 31, 2020 filed a DLOF with the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"). Pursuant to Regulation 72(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DLOF filed with SEBI is open to public, for comments, if any, for a period of at least twenty one days from the date of filing with SEBI, by hosting it on the websites of the SEBI at www.sebi.gov.in, website of recognised stock exchanges where the Equity Shares are listed i.e., the BSE Limited ("**BSE**") at www.bseindia.com, the National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**") at www.nseindia.com, website of the Lead Manager i.e. Keynote Financial Services Limited at www.keynoteindia.net and website of Company at www.refex.co.in. The public is requested to send a copy of the comments to SEBI, the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and the Lead Manager at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by our Company or the Lead Manager in relation to the DLOF on or before the 21st (twenty first) day from the aforementioned date of filing the DLOF with SEBI. The comments may be forwarded to SEBI at the following address: Securities And Exchange Board Of India; Overseas Towers, 7th Floor, 756-L, Anna Salai, Chennai – 600002, Tamil Nadu, India.

This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in any other jurisdiction. The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act, 1933, as amended ("**Securities Act**"), or any U.S. state securities laws and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States of America or the territories or possessions thereof ("**United States**" or "**U.S.**") or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in Regulation S under the Securities Act ("**Regulation S**"), except in a transaction exempt from the registration requirements of the Securities Act. The Rights Entitlements referred to in the DLOF are being offered in India, but not in the United States. The offering to which DLOF relates is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any securities or rights for sale in the United States or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said securities or rights. Accordingly, the DLOF should not be forwarded to or transmitted in or into the United States at any time.

Investors should note that investment in equity and equity related securities involves a degree of risk and investors should not invest any funds in the Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue including the risks involved. The Rights Equity Shares have not been recommended or approved by SEBI nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the DLOF. Investors are advised to refer "*Risk Factors*" beginning on page 15 before investing in the Issue.

Note: Capitalised terms not defined herein shall have the same meanings ascribed to such terms in the DLOF.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE

KEYNOTE
Keynote Financial Services Limited
(Formerly Keynote Corporate Services Limited)
The Ruby, 9th Floor, Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai – 400 028, India.
Telephone: +91 22 6826 6000; **Email:** mbd@keynoteindia.net
Website: www.keynoteindia.net; **Contact Person:** Mr. Akhil Mohod/ Mr. Shashank Pisat
SEBI Registration No.: INM000003606

REGISTRAR TO THE ISSUE

CAMEO
Cameo Corporate Services Limited
"Subramanian Building", No.1, Club House Road, Chennai 600 002
Telephone: +91 44 4002 0700 / 2846 0390
Email: priya@cameoindia.com; **Website:** www.cameoindia.com
Contact Person: Ms. Sreepriya K.
SEBI Registration No.: INR000003753

For **REFEX INDUSTRIES LIMITED**
Sd/-
S. Gopalakrishnan
Company Secretary and Compliance Officer

Place : Chennai
Date : April 01, 2020

REFEX INDUSTRIES LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make a rights issue of its Equity Shares to its eligible equity shareholders and has filed the DLOF with SEBI. The DLOF shall be available on the websites of SEBI, BSE and NSE at www.sebi.gov.in, www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on the website of the Lead Manager at www.keynoteindia.net. Potential investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see the section titled "*Risk Factors*" on page 15 of the DLOF. Potential investors should not rely on the DLOF filed with SEBI for making any investment decision.

CONCEPT

Dalmia Bharat Limited

DALMIA BHARAT LIMITED
(Formerly known as Odisha Cement Limited)
Corporate Identity Number (CIN): L14200TN2013PLC112346
Registered Office: Dalmiapuram Lalgudi, District Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India - 621 651
Corporate Office: 11th and 12th Floor Hansalaya Building, 15 Barakhamba Road, New Delhi, India - 110 001
Tel. No.: +91 11 2346 5100 | **Fax No.:** +91 11 2331 3303
E-mail: corp.sec@dalmiabharat.com | **Website:** www.dalmiabharat.com
Contact Person: Dr. Sanjeev Gemawat, Executive Director- Legal & Group Company Secretary

CORRIGENDUM TO THE PUBLIC ANNOUNCEMENT DATED MARCH 23, 2020 PUBLISHED ON MARCH 24, 2020 BY DALMIA BHARAT LIMITED FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF DALMIA BHARAT LIMITED FOR THE BUYBACK OF EQUITY SHARES FROM THE OPEN MARKET THROUGH STOCK EXCHANGES UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("BUYBACK REGULATIONS")

This corrigendum ("**Corrigendum**") is in continuation of, and should be read in conjunction with the public announcement dated March 23, 2020 and published on March 24, 2020 ("**Public Announcement**") by Dalmia Bharat Limited (the "**Company**") for buyback by the Company of its fully paid-up equity shares of a face value of INR 2/- (Indian Rupees Two Only) each ("**Equity Shares**") from the shareholders/beneficial owners (other than those who are promoters, members of the promoter group or persons in control), from the open market through stock exchange mechanism i.e., using the electronic trading facilities of the stock exchanges where the Equity Shares of the Company are listed i.e., National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**") and BSE Limited ("**BSE**") (collectively, "**Stock Exchanges**"), for an aggregate amount not exceeding INR 500,00,00,000/- (Indian Rupees Five Hundred Crores Only) ("**Maximum Buyback Size**") excluding the Transaction Costs and at a price not exceeding INR 700/- (Indian Rupees Seven Hundred Only) per Equity Share ("**Maximum Buyback Price**"), payable in cash (the process being referred hereinafter as "**Buyback**"). The terms used but not defined in this Corrigendum shall have the meanings as assigned in the Public Announcement.

The equity shareholders/ beneficial owners of the Equity Shares of the Company are requested to take notice of the following changes/ amendments to the Public Announcement:

1. Paragraph 8.1 of Part B of the Public Announcement, stands revised to the extent mentioned below:
   The Company has entered into an escrow agreement with the Manager to the Buyback and HDFC Bank Limited ("**Escrow Agreement**"). The Company has deposited in the Escrow Account an amount in cash aggregating to INR 125,00,00,000/- (Indian Rupees One Hundred and Twenty Five Crores Only), being 25% of the Maximum Buyback Size in accordance with the Buyback Regulations.
2. The details regarding '*Gautam Dalmia (in the capacity of trustee of Sumana Trust)*', appearing in the table in paragraph 4.3 of Part A of the Public Announcement, stands revised to the extent mentioned below:

Sr. No.	Nature of transaction	Aggregate number of Equity Shares purchased/sold	Minimum Price (INR)	Date of Minimum Price	Maximum Price (INR)	Date of Maximum Price
Gautam Dalmia (in the capacity of trustee of Sumana Trust)						
1.	Gift of Equity Shares to Sumana Dalmia on June 19, 2019	20,708	Not applicable			
Keshav Power Limited						
1.	Open market purchase	26,100	820.10	November 13, 2019	824.05	November 13, 2019

3. The immediate paragraph following the heading of paragraph 4 i.e., "***DETAILS OF PROMOTERS, MEMBERS OF THE PROMOTER GROUP, PERSONS IN CONTROL AND DIRECTORS OF PROMOTERS AND MEMBERS OF THE PROMOTER GROUP SHAREHOLDING AND OTHER DETAILS***" is marked as paragraph 4.1 and the following note has been added below the table appearing under paragraph 4.1 of Part A of the Public Announcement:
   *Note: Pursuant to the order dated April 12, 2018, the National Company Law Tribunal approved a scheme of amalgamation and arrangement which provided for (a) merger of Ankita Pratisthan Limited, Mayuka Investment Limited, Puneet Trading and Investment Company Private Limited, Zipahead.Com Private Limited, Mahanadi Trading Private Limited and Shreevallabh Textile Private Limited with Rama Investment Company Private Limited; and (b) demerger of cement business of Keshav Power Limited and Shree Nirman Limited into Rama Investment Company Private Limited ("**Scheme**"). The aforesaid Scheme has been set aside by the National Company Law Appellate Tribunal ("**NCLAT**") by its order dated November 29, 2019 ("**NCLAT Order**"). Subsequently, a miscellaneous application has been filed by Rama Investment Company Private Limited with the NCLAT and the same is pending. The shareholding details of Rama Investment Company Private Limited in the table above, has been provided basis the aforesaid Scheme.*
4. The percentage of shareholding of Keshav Power Limited in the Company, appearing in the table in paragraph 4.1 of Part A of the Public Announcement should be read as "0.01" instead of "0.025".

All other information and terms of the Buyback as disclosed in the Public Announcement shall remain unchanged.

Directors' responsibility

As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board accepts responsibility for the information contained in this Corrigendum and confirms that the information in this Corrigendum contains true, factual and material information and does not and will not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of
Dalmia Bharat Limited

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Gautam Dalmia	**Jayesh Doshi**	**Dr. Sanjeev Gemawat**
Managing Director	**Whole Time Director & CFO**	**Executive Director - Legal & Group Company Secretary**
DIN: 00009758	**DIN: 00017963**	**Membership No.: FCS3669**

Date: April 1, 2020
Place: New Delhi

CONCEPT

PUBLIC ANNOUNCEMENT
THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, INTO THE UNITED STATES OR OUTSIDE INDIA.

EMERALD LEASING FINANCE AND INVESTMENT COMPANY LIMITED

Our Company was incorporated under the Companies Act, 1956 in New Delhi as "Emerald Leasing Finance and Investment Company Limited" on November 22, 1983 vide Certificate of Incorporation issued by the Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi & Haryana. Our Company obtained certificate of Commencement of Business on December 16, 1983. Our Company was granted Certificate of Registration dated November 20, 2015 by the Reserve Bank of India to carry on the business of Non- Banking Financial Institution. The Corporate Identity Number of our Company is L65993CH1983PLC041774. For details on change of Registered Office of our Company, please refer to chapter titled "General Information" beginning on page 27 of the Draft Letter of Offer ("**DLOF**").

Registered Office: SCO 7, Industrial Area, Phase II, Chandigarh – 160002, India. **Tel:** 0172 - 4005659; **Fax:** 0172 - 4603859; **Contact Person:** Mrs. Anju Sharma, Company Secretary and Compliance Officer
E-mail: info@emeraldfin.com; **Website:** www.emeraldfin.com

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. SANJAY AGGARWAL, MRS. ANUBHA AGGARWAL, MR. RAM SWAROOP AGGARWAL AND MRS. ANU AGGARWAL

ISSUE OF [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE) ("RIGHTS EQUITY SHARES") FOR AN AMOUNT AGGREGATING UPTO ₹ 2,500 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF EMERALD LEASING FINANCE AND INVESTMENT COMPANY LIMITED ("THE COMPANY" OR THE "ISSUER") IN THE RATIO OF [•] RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY [•] FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY SUCH ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, i.e. ON [•] (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 93 OF THE DLOF.

THE ISSUE PRICE OF EACH RIGHTS EQUITY SHARE IS [•] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE.

This Public Announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 72(2) of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 as amended (the "**SEBI ICDR Regulations**"), to inform the public that our Company is proposing, subject to requisite approvals, market conditions and other considerations, an issue of Rights Equity Shares to its eligible equity shareholders on rights basis and has on March 31, 2020 filed a DLOF with the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"). Pursuant to Regulation 72(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DLOF filed with SEBI is open to public, for comments, if any, for a period of at least twenty one days from the date of filing with SEBI, by hosting it on the websites of the SEBI at www.sebi.gov.in, website of recognised stock exchange where the Equity Shares are listed i.e., the BSE Limited ("**BSE**") at www.bseindia.com, website of the Lead Manager i.e. Keynote Financial Services Limited at www.keynoteindia.net and website of Company at www.emeraldfin.com. The public is requested to send a copy of the comments to SEBI, the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and the Lead Manager at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by our Company or the Lead Manager in relation to the DLOF on or before the 21st (twenty first) day from the aforementioned date of filing the DLOF with SEBI. The comments may be forwarded to SEBI at the following address: Securities And Exchange Board Of India; Corporation Finance Department of the SEBI, located at 5th Floor, Bank of Baroda Building, 16 Sansad Marg, New Delhi - 110001, India.

This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in any other jurisdiction. The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act, 1933, as amended ("**Securities Act**"), or any U.S. state securities laws and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States of America or the territories or possessions thereof ("**United States**" or "**U.S.**") or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in Regulation S under the Securities Act ("**Regulation S**"), except in a transaction exempt from the registration requirements of the Securities Act. The Rights Entitlements referred to in the DLOF are being offered in India, but not in the United States. The offering to which DLOF relates is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any securities or rights for sale in the United States or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said securities or rights. Accordingly, the DLOF should not be forwarded to or transmitted in or into the United States at any time.

Investors should note that investment in equity and equity related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the Risk Factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, Investors must rely on their own examination of our Company and the Issue including the risks involved. The Rights Equity Shares being offered in this Issue have not been recommended or approved by SEBI nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the DLOF. Investors are advised to refer to the "*Risk Factors*" on page 14 of the DLOF before making an investment in the Issue.

Note: Capitalised terms not defined herein shall have the same meanings ascribed to such terms in the DLOF.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE

KEYNOTE
Keynote Financial Services Limited
(formerly Keynote Corporate Serwes Limited)
The Ruby, 9th Floor, Senapati Bapat Marg, Dadar (W), Mumbai – 400028
Tel. No.: +91 – 22 – 6826 6000; **Email:** mbd@keynoteindia.net
Website: www.keynoteindia.net, **Contact Person:** Ms. Pooja Sanghvi/Mr. Amlan Mahajan
SEBI Registration No: INM 000003606

REGISTRAR TO THE ISSUE

MASS
MAS Services Limited
T-34, 2nd Floor Okhla Industrial Area, Phase II, New Delhi – 110020 India
Tel. No: +91 11 2638 7281-83, **E-mail:** info@masserv.com
Website: www.masserv.com
Contact Person: Mr. Sharwan Mangla
SEBI Registration No: INR 000000049

For **EMERALD LEASING FINANCE AND INVESTMENT COMPANY LIMITED**
Sd/-
Anju Sharma
Company Secretary and Compliance Officer

Place : Chandigarh
Date : April 01, 2020

EMERALD LEASING FINANCE AND INVESTMENT COMPANY LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make a rights issue of its Equity Shares to its eligible equity shareholders and has filed the DLOF with SEBI. The DLOF shall be available on the websites of SEBI and BSE at www.sebi.gov.in, www.bseindia.com, respectively and on the website of the Lead Manager at www.keynoteindia.net. Potential investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see the section titled "*Risk Factors*" on page 14 of the DLOF. Potential investors should not rely on the DLOF filed with SEBI for making any investment decision.

CONCEPT

www.readwhere.com

जनसत्ता

संकट में राहत

इस वक्त जिस तरह पूरी दुनिया कोरोना विषाणु से फैली महामारी के चलते बंदी और मंदी के दौर से गुजर रही है, रोजगार और कारोबार पर संकट गहरा गया है, उसमें लोगों को वित्तीय राहत देने की कोशिशें भी तेजी से हो रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का आवास, वाहन, खेती-किसानी आदि के लिए लिए गए मियादी कर्ज की किस्त वसूली अगले तीन महीनों तक रोक देने या उसमें ढील देने संबंधी आदेश भी इसी की एक कड़ी है। रिजर्व बैंक के आदेश का पालन करते हुए तमाम सरकारी बैंकों ने अपने ग्राहकों को यह सुविधा देने की घोषणा भी कर दी है। जो लोग इस दौरान अपने कर्ज की किस्तें नहीं चुका पाएंगे, उन पर सख्ती नहीं की जाएगी। पूर्ण बंदी के चलते तमाम कल-कारखाने बंद कर दिए गए हैं, बाजार में कारोबार ठप्प हैं, दूसरे देशों से वाणिज्य और व्यवसाय संबंधी गतिविधियां रुक गई हैं, होटल, पर्यटन आदि उद्योग बंद हैं। ऐसे में तमाम लोगों के रोजगार पर बुरा असर पड़ा है। हालांकि सरकारों ने अपील की है कि कंपनियां अपने कर्मचारियों का वेतन न काटें, पर हकीकत यही है कि धंधे में घाटा होने की स्थिति में अनेक उद्यमियों के सामने अपने कर्मचारियों का वेतन समय पर देने और पूरा भुगतान करने में बाधा खड़ी होगी। ऐसे में बहुत सारे लोगों के लिए अपने कर्ज पर मासिक किस्तें चुकाने में परेशानी पैदा होगी। इस दृष्टि से बैंकों का यह कदम निस्संदेह उनके लिए राहत भरा साबित होगा।

मगर बैंकों का कारोबार पहले से ही धीमा है, लोगों के वाहन, आवास आदि के लिए कर्ज लेने की गति मंद हुई है, बाजार में मंदी के चलते पूंजी का प्रवाह बाधित है, ऐसे में किस्तों के भुगतान में ढील देने से उन पर बोझ और बढ़ेगा। इसलिए रिजर्व बैंक ने लघु बचत योजनाओं में किए गए निवेश पर ब्याज दरों में कटौती की है। अब तीन साल तक की मियादी जमा राशि पर ब्याज 5.5 की दर से मिलेगा, जो पहले 6.9 फीसद था। इसी तरह लोक भविष्य निधि यानी पीपीएफ, राष्ट्रीय बचत पत्र पर ब्याज दरों में क्रमशः 0.8 और 1.1 फीसद की कटौती की गई है। इस कटौती से बैंकों को जो बचत होगी, वह किस्तें जमा करने के मामले में ढील देने से हुए नुकसान की कुछ भरपाई हो सकेगी। हालांकि जिन लोगों ने अपने भविष्य की वित्तीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लघु बचत योजनाओं में निवेश किया था, उन्हें थोड़ी निराशा हाथ लगेगी। पर यह फैसला केवल अगले तीन महीनों के लिए लागू होगा, इसलिए अगली तिमाही में अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने की दशा में इस फैसले के पलटने की उम्मीद बनी हुई है।

रिजर्व बैंक का यह फैसला सख्त नहीं कहा जा सकता। पहले भी जब-जब देश मंदी के दौर से गुजरा है, तब इस तरह की कटौतियां करनी पड़ी हैं। इसे अगर इस तरह देखें कि कुछ मामलों में ब्याज दरें कम हुई हैं, तो कर्जों की किस्तें चुकाने के मामले में दी जा रही ढील के जरिए बड़ी राहत पहुंचाने की भी कोशिश की गई है। अभी देश एक तरफ महामारी से पार पाने का प्रयास कर रहा है, तो दूसरी तरफ आर्थिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। पूरी दुनिया में भयंकर मंदी का दौर आने वाला है, जिसमें सारी चीजें प्रभावित होने वाली हैं। बैंकों की वित्तीय स्थिति ठीक रखना भी बड़ी चुनौती है। इसलिए ब्याज दरों में ताजा कटौती कोई बड़ी मार नहीं कही जा सकती।

नस्ली भेदभाव

पूर्वोत्तर के लोगों के साथ देश के विभिन्न शहरों में जब-तब ज्यादतियां देखी जाती हैं। इस बार लोग उन्हें चीनी मूल का समझ कर भेदभाव करते देखे जा रहे हैं। चूंकि पूर्वोत्तर के लोगों का हुलिया चीनी लोगों से मिलता-जुलता है, इसलिए कुछ लोगों को कई बार यह भ्रम हो जाता है। चूंकि कोरोना विषाणु चीन से पैदा होकर पूरी दुनिया में फैल रहा है, इसलिए उसके प्रति रोष देखा जा रहा है। यहां तक कि कुछ राष्ट्राध्यक्षों तक ने चीन को लेकर तल्ख टिप्पणियां की थीं। इसका भारत पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। चीन के साथ भारत के रिश्ते अक्सर तनाव भरे देखे जाते हैं, खासकर दोनों देशों से लगी सीमा पर सैन्य तनाव जब-तब उभर आता है। इसलिए कई मौकों पर लोग चीन में बनी वस्तुओं के बहिष्कार तक की मांग करते रहे देखे जाते हैं। कुछ साल पहले दिल्ली और उससे सटे शहरों में पढ़ाई करने आए पूर्वोत्तर के युवाओं के साथ बड़े पैमाने पर हिंसक हमलों, उन्हें किराएदारी से बेदखल करने, दुकानों में खरीदारी आदि से रोकने की कोशिशें देखी गई थीं। उसमें कई युवा गंभीर रूप से घायल हो गए थे, तो कुछ की जान भी चली गई थी। इस बार भी कुछ जगहों पर उनके प्रति हिकारत का भाव देखा जा रहा है।

स्वाभाविक ही ऐसी घटनाओं से आहत मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से इस नस्ली भेदभाव पर लगाम लगाने की अपील की है। उन्होंने अपने ट्वीट में एक वीडियो भी साझा की है, जिसमें कुछ नगा छात्रों को किराने की एक दुकान में घुसने से रोका जा रहा है। जोरामथंगा ने अपनी यह ट्वीट पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों असम, मेघालय, नगालैंड, और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी नत्थी कर भेजी है। वे सब भी इन घटनाओं से आहत हैं। भारत एक गणतांत्रिक देश है, जिसमें सभी राज्यों के नागरिकों को कहीं भी जाकर पढ़ाई-लिखाई, रोजगार, नौकरी आदि करने या फिर बस जाने का संवैधानिक अधिकार है। उन्हें इन अधिकारों से वंचित करना गणतांत्रिक मूल्यों हनन है। पर देशभक्ति या फिर प्रादेशिक अस्मिता के नाम पर कई बार लोग इस संवैधानिक तकाजे को भुला बैठते हैं और पूर्वोत्तर के लोगों के साथ नस्ली भेदभाव करते देखे जाते हैं। यों भी पूर्वोत्तर के लोगों को चिढ़ाने की मंशा से उनके लिए अपमानजनक संबोधन आम बात है। वहां से आई लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं भी कुछ अधिक देखी जाती है। एक देश के खास हिस्से के कुछ लोगों के साथ अपने ही देश के नागरिकों का इस तरह का नस्ली, अशोभन या फिर हिंसक व्यवहार किसी सभ्य समाज की निशानी नहीं मानी जा सकती।

यह समय एक-दूसरे के सहयोग से कोरोना जैसी महामारी से पार पाने का है। बंदी के इस दौर में जब लोग अपने घरों से दूर जगह-जगह फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग बेसहारा लोगों की मदद के लिए आगे आते देखे जा रहे हैं, यथाशक्ति सहयोग का हाथ बढ़ा रहे हैं, उसमें अपने ही देश के कुछ नागरिकों को बुनियादी जरूरत की वस्तुओं तक से महरूम कर देने की कोशिशें अमानवीय और असहिष्णुता ही कही जाएंगी। भारतीय समाज इतना असहिष्णु कभी नहीं रहा कि संकट के समय मदद के बजाय अपनी दुर्भावना का प्रदर्शन करे, जरूरतमंदों को बेदखल करने का प्रयास या उनके साथ हिंसक बर्ताव करे। फिर ऐसी हरकतों से चीन को भला क्या सबक सिखाया जा सकता है। इससे लोगों के भीतर बैठी अमानवीयता का ही प्रदर्शन होता है।

कल्पमेधा

यदि तुम अपनी आमदनी से कम में गुजारा कर सकते हो, तो निश्चय जानो कि पारस-पत्थर तुम्हारे पास है।

– बेंजामिन फ्रैंकलिन

नक्सली हमलों से उठते सवाल

ब्रह्मदीप अलूने

नक्सली अपने प्रभाव वाले इलाकों में विकास होने ही नहीं देना चाहते। गढ़चिरौली की भौगोलिक स्थिति नक्सलियों को महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में एक से दूसरे क्षेत्र में आसानी से जाने की सहूलियत देती है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की सीमा से अन्य राज्यों में आसानी से घुसा जा सकता है। इन इलाकों के लिए व्यापक रणनीति को बहुआयामी बनाने की जरूरत है।

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के चिंतागुफा जंगल में पिछले दिनों नक्सलियों ने एक बार फिर सुरक्षा बलों पर हमला कर सत्रह जवानों को मार डाला। यह वही इलाका है जिस पर सुरक्षा बलों ने 2009 में कब्जा कर लिया था। लेकिन सुरक्षा की बहुआयामी और समन्वित रणनीति के अभाव का फायदा उठा कर नक्सली ऐसे क्षेत्रों में मौका मिलते ही फिर से हावी हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी जिलों- बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के करीब चार हजार किलोमीटर क्षेत्र में घने जंगल हैं और इसे माओवाद का स्वर्ग माना जाता है। सुकमा की सरहद आंध्रप्रदेश और ओड़ीशा से मिलती है। यह माओवादियों के एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन का सुगम रास्ता है। इन इलाकों में माओवादी समांतर सरकार बनाने में भी कामयाब रहे हैं, जिसे जनताना सरकार कहा जाता है। सरकार इन इलाकों में सड़कों का जाल बिछाना चाहती है, लेकिन माओवादी सड़के खोद देते हैं, ठेकेदारों पर दबाव बनाते हैं, सुरक्षा बलों पर हमले करते हैं। इसलिए कई सालों से यह काम पूरा ही नहीं किया जा सका है।

दरअसल नक्सलवाद की यह कड़वी हकीकत है कि तमाम सरकारी कोशिशों के बाद भी वे अपना प्रभाव बनाए रखने में सफल रहे हैं और जंगलों में सुरक्षा बलों को घेरने की रणनीति में महारत हासिल कर ली है। वे अपने प्रभाव वाले इलाकों के ऊबड़-खाबड़ रास्तों और जंगलों की जानकारियों का जम कर फायदा उठाते हैं और सुरक्षा बलों पर घातक हमले कर उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी ओर पिछले कई दशकों से माओवादी हमलों से जूझने और हजारों जवानों को खोने के बाद भी देश में नक्सलवाद से निपटने की ऐसी कोई निर्णायक और दीर्घकालीन कार्ययोजना नहीं बन सकी है जिसके बेहद सकारात्मक परिणाम सामने आए हों। वहीं नक्सली परंपरागत गुरिल्ला युद्ध के बूते देश के दो सौ से ज्यादा जिलों और लगभग बीस राज्यों में अपना प्रभाव जमाए रखने मे लगातार सफल रहे हैं। नक्सलियों के सामने भारत का आधुनिक बल होता है, इसके बाद भी वे छापामार युद्ध पद्धति से सुरक्षा बलों को ज्यादा नुकसान पहुंचाने में सफल रहे हैं। भारत की भौगोलिक परिस्थितियां माओवाद की छापामार पद्धति के अनुकूल हैं और विभिन्न मोर्चों पर भिन्न-भिन्न कारणों से माओवादियों को मजबूती भी मिलती है।

नक्सलियों से निपटने के लिए भारत में कोशिशें तो की गईं, लेकिन वे कई कारणों से बहुआयामी और दीर्घकालीन नहीं बन सकीं। विकास और सुरक्षा के दबाव की रणनीति को माओवाद के खात्मे के लिए सबसे मुफीद माना गया। करीब दस साल पहले यूपीए सरकार के दौरान तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने राज्य पुलिस बलों को अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित करने और सशक्त बनाने की दो स्तरीय योजना शुरू की थी। इसके अनुसार वामपंथ प्रभावित जिलों में ज्यादा अर्धसैनिक बल तैनात करने और दूरदराज के इलाकों में किलेबंद पुलिस थाने बनाने की योजना थी। योजना का दूसरा चरण यह था कि माओवादियों से आज़ाद कराए गए इलाकों में स्कूल, सड़कों, शौचालयों और पीने के पानी की सुविधाओं का निर्माण करके इसे ताकतवर बनाया जाए। एक बार यहां से नक्सलियों को खदेड़ने के बाद वे पुनः यहां स्थापित न हो सकें, इसके लिए छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में एक एकीकृत कमांड बनाई गई, जिससे पुलिस, अर्धसैनिक बल और खुफिया एजंसियों की गतिविधियों के बीच नजदीकी तालमेल स्थापित किया जा सके। इस नीति के उत्साहवर्धक परिणाम तो आए, लेकिन इस योजना पर अन्य कारणों से लंबे समय तक काम नहीं हो सका। सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण बात है केंद्र को राज्यों का सहयोग। किसी एक राज्य की ढीली-ढाली नीति माओवादियों को सुरक्षित रखने में अप्रत्याशित मददगार बन जाती है और अंततः माओवाद पर नकेल ढीली पड़ जाती है। व्यापक स्तर पर सुरक्षा अभियान के साथ समन्वित विकास के लिए केंद्र को राज्यों का सहयोग चाहिए होता है, जिससे विकास पैकेज और प्रशासन की बहाली सुनिश्चित हो सके।

सितंबर, 2009 में कोबरा बटालियन, छत्तीसगढ़ पुलिस और स्थानीय आदिवासी पुलिसकर्मियों को मिला कर तैयार की गई टीम ने दो सौ माओवादियों के साथ जबरदस्त मुठभेड़ में दक्षिण छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा इलाके में किष्टरम और चिंतागुफा क्षेत्र में अवैध हथियार बनाने के ठिकानों को नष्ट किया था। पहली बार सुरक्षा बल चिंता गुफा तक पहुंचे थे। माओवादियों की पनाहगाह बना यह क्षेत्र बारूदी सुरंगों के कारण पहुंच से दूर नजर आता था। यह अभियान इसलिए भी सफल हो पाया था, क्योंकि इस दौरान पड़ोसी राज्यों आंध्र प्रदेश और ओड़ीशा में भी पुलिस बल तैनात थे, जिससे माओवादियों के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में भागने में बड़ी बाधा उत्पन्न हो गई थी।

माओवादी गरीबी और पिछड़ेपन का लाभ उठा कर अपने सिद्धांतों का प्रचार करते हैं और इस प्रकार स्थानीय जनसमुदाय पर अपना प्रभाव और नियंत्रण स्थापित करने में कामयाब हो जाते हैं। उनके लिए विस्थापन जैसे मुद्दे अपना प्रभाव कायम करने में खास योगदान देते हैं। अर्धसैनिक बलों को स्थानीय जंगलों की जानकारी ज्यादा नहीं होती और स्थानीय लोग उन पर भरोसा भी नहीं करते। ऐसे में स्थानीय पुलिस को मजबूत कर माओवादियों से बेहतर ढंग से निपटा जा सकता है। माओवादियों को सामान्य आदिवासियों से अलग करना होता है और यह काम स्थानीय पुलिस बेहतर ढंग से कर सकती है। अतः स्थानीय पुलिस को अग्रिम पंक्ति में रख कर अर्धसैनिक बलों को सहयोगी के रूप में रखने की जरूरत है और इस पर नीति बनने का इंतजार है। दुर्भाग्य यह है कि देश में अभी तक पुलिस सुधार ही लागू नहीं किए गए हैं, इससे पुलिस के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया बाधित हुई है।

माओवादियों के नियंत्रण वाले सबसे बड़े क्षेत्र बस्तर में चालीस हजार वर्ग किलोमीटर में फैला इलाका लौह अयस्क से समृद्ध क्षेत्र है। नक्सली हमलों के लिए कुख्यात दंतेवाड़ा से बीजापुर का मार्ग एक दशक बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं बन सका है। नक्सली अपने प्रभाव वाले इलाकों में विकास होने देना ही नहीं चाहते। गढ़चिरौली की भौगोलिक स्थिति नक्सलियों को महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्रप्रदेश में एक से दूसरे क्षेत्र में आसानी से जाने की सहूलियत देती है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की सीमा से अन्य राज्यों में आसानी से घुसा जा सकता है। इन इलाकों के लिए व्यापक रणनीति को बहुआयामी बनाने की जरूरत है। यहां बैक शाखाएं, डाक घर, एटीएम, सड़कें, मोबाइल टावर और अन्य विकास संसाधन उपलब्ध होने से नागरिकों का भरोसा सरकार पर बढ़ सकता है। लेकिन प्रशासनिक उदासीनता और नाकामी एक बड़ा संकट है। मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले का लांजी अनुभाग नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित है। इसके अंतर्गत डेढ़ सौ से ज्यादा गांव आते हैं, लेकिन बैंक या एटीएम जैसी सुविधाएं लांजी में ही उपलब्ध हैं। जाहिर है, ऐसी स्थितियों का लाभ अप्रत्याशित रूप से माओवादियों को मिलता है और वे भोले-भाले आदिवासियों को भ्रमित करने में सफल हो जाते हैं।

आदिवासियों के जमीन संबंधी विवादों की सुनवाई के लिए त्वरित अदालतें होनी चाहिए। ऐसे विवादों में न्याय मिलने में देरी का फायदा माओवादियों को मिलता है। आदिवासियों के लिए जल, जंगल और जमीन बड़े मुद्दे होते हैं, माओवादी ग्रामीणों के सामने सरकार की छवि को खराब कर-के उसे शोषणकर्ता के रूप में प्रचारित करते हैं। माओवादियों के खिलाफ जीतने के लिए स्थानीय लोगों का सहयोग और समर्थन मिलना जरूरी है। इसलिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं पर ध्यान देने की भी जरूरत है। इन सबके साथ माओवादी हमलों की उच्च तीव्रता के समय पर सावधानी रखने की भी जरूरत है। माओवादी मार्च से लेकर जून तक ज्यादा घातक हमले करते हैं। उग्रवादी इसे सालाना टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन (टीसीओसी) कहते हैं। नक्सलवाद से निपटने के लिए व्यापक कार्ययोजना की दरकार है जिसमें विकास, सुरक्षा और नक्सलियों के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई की समन्वित और दीर्घकालीन नीति बने और केंद्र व राज्य मिल कर अमल करें।

वे यायावर

हेमंत कुमार पारीक

दुनिया मेरे आगे

पता नहीं वे कौन हैं? लेकिन शहर के चौराहों पर आजकल बहुतायत में दिखाई देते हैं। चौराहा एक चलता-फिरता बाजार-सा बन जाता है। गंदे-फटे कपड़ों में ये लोग सिग्नल पर दिखाई देते हैं। पंद्रह अगस्त या छब्बीस जनवरी को प्लास्टिक या कागज के छोटे-छोटे झंडे लिए नजर आते हैं। अमूमन बड़ी गाड़ियों के सामने झंडे लहराते हुए खरीदने की गुजारिश करते दिखते हैं। मैंने कई बार उन्हें देखा है, लेकिन आश्चर्य होता है कि समय के अनुसार उनके बेचने का सामान बदल जाता है। उन लोगों में औरतें, आदमी और बच्चे दिखते हैं। कभी बूढ़ी औरतें हाथ में कलम लिए बेचती नजर आती हैं। उनके हाथों में 'यूज ऐंड थ्रो' वाले सस्ते पेन होते हैं, वेलेंटाइन-डे जैसे विशेष अवसरों पर हाथ में दिल के आकार के लाल-लाल गुब्बारे लिए होते हैं। गर्मियों में कार के शीशों पर लगाए जाने वाले काले-काले कवर होते हैं। कभी-कभी शनिवार के दिन बच्चों के हाथ में बाल्टी भी होती है। शनि का दान मांगते फिरते हैं। कभी छोटे-छोटे खिलौने और बार्बी डॉल जैसे शो-पीस लिए होते हैं, तो कभी नए साल के कैलेंडर होते हैं उनके हाथ में।

कौन हैं ये लोग? मन में विचार आता है। इतनी तेजी से तो बाजार का मिजाज भी नहीं बदलता, जितनी तेजी से इनके हाथों में रखे उत्पाद बदल जाते हैं। कहां से लाते हैं वे ये सब? कहां रहते हैं? शायद उनकी जीविका इन्हीं उत्पादों की बिक्री पर टिकी होती है।

पहले कभी जब मैं अपने मित्रों के साथ गांव के बाहर सैर पर निकलता था, तो गांव के बाहर खुले मैदान में यदाकदा एक दो तंबू नजर आते थे। भट्ठी जलती दिखती थी। उसमें लोहे की सलाखें गर्म कर वे दैनिक उपयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के सामान बनाते थे, जैसे कि हंसिया, कुल्हाड़ी, खुरपी, संड़सी आदि। पास में खड़ी बैलगाड़ी में इनका मोबाइल घर हुआ करता था। घर-घर घूमते-फिरते सामान की बिक्री करते नजर आते थे। सारा सामान 'हैंड मेड' होता था। बाजार की कीमत से कई गुना कम कीमत में बेचते थे। कुछ दिन दिखते वे लोग और फिर जाने कहां गायब हो जाते थे। वहीं मैंने लोहे को विभिन्न आकारों में ढलते देखा था। औरतें बड़े-बड़े घन चलाती थीं। और वे ही बाजार में सामान की बिक्री के लिए बैठी दिखती थीं। कभी-कभी सामान बेचने बस्ती में भी निकल आती थीं। खेती-किसानी करने वाले उनसे सस्ती दरों में सामान खरीदते थे, पर पढ़े-लिखे किस्म के लोग सीधे बाजार से ही सामान खरीदना पंसद करते थे। अभी भी आश्चर्य होता है कि कैसे इन छोटे-छोटे सस्ते सामान से उनकी गुजर-बसर होती होगी?

एक बार मैंने उनके डेरे में जाकर एक कैंची खरीदी थी। वह मजबूत कैंची आज भी मेरे पास है। यदाकदा धार लगवाने की जरूरत पड़ती है। उसी मैदान में मैंने उनमें से एक जवान आदमी से पूछा था, भाई, आप लोग कहां से आए हैं और इस प्रकार क्यों घूमते हैं?' उनके छोटे-छोटे बच्चे गंदे कपड़ों में खेल रहे थे। उनकी तरफ देख मैंने उससे यह सवाल किया था। दरअसल, मन में कहीं न कहीं एक पीड़ा थी। सर्दी, गर्मी और बारिश में देखा करता था।... ऊंचा पूरा नौजवान था वह। राजस्थानी लहजे में बोला, हम लोग राणा प्रताप के वंशज हैं। महाराणा जंगलों में घूमते रहे। आखिरी दम तक दुश्मन से लड़ते रहे। घास-फूस की रोटियां भी खाईं, मगर कभी घुटने नहीं टेके।

सदियां बीत गईं इस घटना को। हल्दीघाटी का युद्ध इतिहास में दर्ज हो गया, पर ये अभी तक उस परंपरा का निर्वाह करते चले आ रहे हैं। समय बदल गया। मगर ये अभी भी यायावर हैं। विमर्श का विषय है कि इनकी आने वाली संतानों का क्या होगा? आज हम सब सर्व सुविधायुक्त जीवन-यापन कर रहे हैं, पर उनकी हालत पर कोई गौर क्यों नहीं करता? आज जो बच्चे हैं कल वे इसी तरह घूमंतू जीवन जीते बड़े हो जाएंगे। क्या समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का इन्हें कोई अवसर मिलेगा? क्या इसी तरह वे भी अनपढ़ रह कर चौराहे पर लोगों से झंडा खरीदने का आग्रह करते फिरेंगे? फटे कपड़ों में खेलते इन बच्चों को देख कर मेरे मन में यही सवाल पैदा हुए थे। गंदे-मैले कपड़ों में वे बच्चे डेरे के आसपास मंडरा रहे थे। उस वक्त भी और आज भी जब हमें आजाद हुए एक अरसा हो गया, वे उसी तरह यायावर हैं। दुनिया भर की खाक छान रहे हैं। कभी चौराहे पर झंडे बेचते हैं, तो कभी बाजार में पारंपरिक हस्तकला से बने औजार!

जिम्मेदार कौन

पिछले दिनों मीडिया में सड़कों पर भीड़ की भयावह तस्वीरें दिखीं। एक ओर देश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र समेत देश के तमाम बड़े शहरों से पलायन करती भीड़ की ये तस्वीरें श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों के प्रति संवेदना पैदा करती हैं, तो दूसरी ओर कई आशंकाएं भी। इस वक्त जब पूरे देश की गति थमी हुई है और तमाम माध्यमों से यह खबर आम हो चुकी है कि कोरोना से लड़ने के लिए सामाजिक दूरी बना कर रखना आवश्यक है, तब सड़कों पर लाखों की संख्या में पसरी यह भीड़ वास्तव में डराने वाली है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या एक हजार से ऊपर पहुंच चुकी है, और अब यह स्थिति संक्रमण के तीसरे चरण की ओर बढ़ने की आशंका पैदा कर रही है, तब इस भीड़ ने यह आशंका पैदा कर दी है कि कहीं इस वायरस से संक्रमित कोई व्यक्ति हमारे समुदाय के बीच तो नहीं है। इस आशंका के बीच बड़ा प्रश्न यह है कि पलायन के लिए उकसाने के जिम्मेदार कहीं हम-आप तो नहीं हैं?

दरअसल, इस स्थिति के पीछे सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया का दुरुपयोग है। पिछले कुछ दिनों से जब फेसबुक, वाट्सएप, ट्विटर या टिकटॉक के माध्यम से आपको कितने ही ऐसे संदेश प्राप्त हुए होंगे, जिनमें कोई कोरोना वायरस का इलाज नौवीं कक्षा की किसी किताब में होना बता रहा था, कोई हेलीकॉप्टर से सेनेटाइजर बरसाने की बात कर रहा था, कोई पुलिस की जगह सेना की तैनाती की बात कर रहा था, कोई चांद के उल्टा होने की बात कर रहा था, कोई बंदी तीन महीने तक बढ़ने की बात कर रहा था, तो कोई आपको ऐसे संदेश भेजता है कि उसका कोई परिचित डब्लयूएचओ में है, उससे हुई बातचीत के आधार पर आपको कुछ बताने का प्रयास कर रहा है। निश्चित रूप से हम सबके पास इससे मिलते-जुलते तमाम संदेश पहुंचे भी होंगे और हम सबने इनमें से कुछ संदेशों को या तो सामान्य मजाक के तौर पर या बिना जांचे ही प्रामाणिक मान कर फॉरवर्ड भी किया होगा।

विचार करके देखिए तो तीन महीने बंदी वाला कोई संदेश आपके लिए सामान्य हो सकता है, लेकिन ऐसे वर्ग के लिए जो दिहाड़ी मजदूरी या अन्य किसी काम पर आश्रित है, उसके मन में भय पैदा करने के लिए क्या यह एक संदेश काफी नहीं है? खबर यह भी है कि पुलिस की जगह सेना की ड्यूटी लगाने की अफवाह फैलाने वाले और दो दिन के सार्वजनिक यातायात पुनः चालू हो जाने वाले कुछ लोगों पर रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित देश के तमाम बड़े शहरों से अपने गांवों की ओर पैदल ही पलायन करती इस भीड़ में बड़ी संख्या में अशिक्षित या अल्पशिक्षित समुदाय के वही लोग हैं, जो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते संदेशों को प्रामाणिकता जांचे बिना या उनके स्रोतों की पुष्टि किए बिना ही सच मान लेते हैं। यह किसी से छिपा नहीं है कि तमाम सांप्रदायिक दंगों के पीछे इसी वर्ग के लोगों की भावनाओं को इसी प्रकार के फर्जी संदेशों के माध्यम से भड़काया जाता है, दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगे इसके ताजा उदाहरण हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन संदेशों को तैयार कौन करता है? शायद हमारे बीच के ही कुछ लोग। पर समाज में अराजकता फैलाने के उद्देश्य से तैयार किए गए इन संदेशों को वायरल करने में हम सबकी भी भूमिका रहती है। सोशल मीडिया पर वायरल होते इन संदेशों के प्रति हमारे समाज को गंभीर होना ही होगा।

● *पंकज यादव, बरेली*

कुछ तो सोचो

दुनिया चिल्ला रही है, सरकारें गला फाड़-फाड़ कर कह रही हैं, मीडिया दिन-रात एक कर रहा है कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को सावधान रहने के लिए। पर अफसोस, अब भी हमारे समाज में ऐसे लापरवाह लोग हैं, जो न तो अपनी, न अपनों की और न ही देश की फिक्र कर रहे हैं और सैकड़ों का हुजूम बनाए रख रहे हैं, तो कहीं विदेशों से आकर गुपचुप घर में छिप रहे हैं संक्रमित होते हुए भी। इस तरह खुद भी बीमार हो रहे हैं और औरों को भी कर रहे हैं। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्थित तब्लीगी मकरज में विदेशियों द्वारा धर्म प्रचार का काम चलता रहा, जिसमें करीब दो हजार लोगों ने शिरकत की। इसमें अनेक कोरोना संक्रमिक थे, जो देश के विभिन्न हिस्सों से आए थे। तेलंगाना में तो इनमें से छह लोगों की मृत्यु भी हो गई, अंडमान में दस संक्रमित पाए गए, तमिलनाडु में भी ये प्रचार के लिए गए थे। इन पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इन्हें अपनी लापरवाही का दंड मिले और फिर कभी ये ऐसे गलत कदम न उठाने पाएं।

● *महेश नेनावा, इंदौर (मप्र)*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

लापरवाही की हद

अमेरिका ऐसे ही विश्व का सबसे महान शक्तिशाली विकसित देश नहीं बना है, उसने जरूर कुछ सही किया होगा। मगर जब संकट की घड़ी आती है तभी किसी इंसान या देश की सही परीक्षा होती है। अगर तीसरी दुनिया के देश इस तरह का आंकड़ा दें तब तो एक बार को समझा जा सकता है, पर अगर अमेरिका जैसे देश में अगर संक्रमित लोगों का आंकड़ा डेढ़ लाख तक पहुंचता है और वहां लोगों को अपनी मूलभूत चीजें लेने के लिए दिक्कत हो रही है और तब भी अगर वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूर्णबंदी के पक्ष में नहीं हैं तो यह बात गले से नहीं उतरती है। उन्हें ज्यादा दूर नहीं, बल्कि इटली, स्पेन, फ्रांस जैसे देशों की तरफ देखना चाहिए और जब इस महामारी ने ब्रिटेन जैसे देश के प्रधानमंत्री को अछूता नहीं छोड़ा और अमीर, गरीब सारे लोग इस त्रासदी से लड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो देश की आम जनता की सेहत और कुशल-मंगल से ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरा विश्व इस समय कोरोना और अर्थव्यवस्था की मंदी की दोहरी मार झेल रहा है, पर इस समय प्राथमिकता कोरोना को ही मिलनी चाहिए। एक बार विश्व इससे उबर गया तो अर्थव्यवस्था को भी उबार लिया जाएगा।

● *बाल गोविंद, सैक्टर 44, नोएडा*

इंतजाम की जरूरत

देश की 130 करोड़ की विशाल आबादी के मान में प्रशिक्षित ऐलोपैथिक चिकित्सकों की बहुत बड़ी कमी है, वहीं देश के सभी सरकारी अस्पतालों में अत्याधुनिक उपकरणों की भी भारी कमी है। आज इटली, फ्रांस, स्पेन, अमेरिका जैसे राष्ट्र, जो चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व भर में अग्रिम पंक्ति में आते हैं, वे जानलेवा कोरोना विषाणु की चपेट में हैं। हमारे यहां पूरे देश में बंदी लागू करना एक अहम फैसला है। बावजूद सबके प्रधानमंत्री से देश की जनता को बहुत सी अपेक्षाएं हैं, इसके पीछे उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति और आत्म विश्वास है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे पूरे देश के हर सरकारी अस्पताल में कोरोना से लड़ने वाले प्रथम योद्धाओं को उच्च क्वालिटी की 'पर्सनल प्रोटेक्शन किट' सहित सभी प्रकार के नए से नए उपकरणों की आपूर्ति तत्काल प्रभाव से कराएं।

● *अरविंद मिश्र, अवधपुरी, भोपाल*

www.readwhere.com

सोशल मीडिया से

प्रधानमंत्री कोष में दिए गए 25 लाख के योगदान के लिए मै हॉकी इंडिया की सराहना करता हूं। यह दिखाता है कि कोविड 19 महामारी के खिलाफ जंग में हम सभी भारतीय एकसाथ हैं। -किरन रिजीजू

जन्मदिन

अवतार सिंह	3 अप्रैल
ओएनाम बेमबेम देवी	4 अप्रैल
अतनु दास	5 अप्रैल
कविता चहल	8 अप्रैल
लिलिमा मिंज	10 अप्रैल

कोरोना विषाणु महामारी ने खेल जगत के गणित को बिगाड़ कर रख दिया है। क्रिकेट से लेकर फुटबॉल और अब ओलंपिक, सभी को टालना पड़ गया। इसका खामियाजा खिलाड़ी और कोच के साथ आयोजकों को भी उठाना पड़ रहा है। जहां खिलाड़ियों को ओलंपिक में पदक के लिए अगले साल तक खुद को फिट रखना होगा वहीं प्रशिक्षकों को भी अब नई रणनीति तैयार करनी होगी। आयोजकों के लिए भी दोबारा टूर्नामेंटों का आयोजन बड़ी चुनौती है। इसके लिए उन्हें दोबारा बजट तैयार करना होगा। फिर से प्रायोजकों को रुपए लगाने के लिए तैयार करना होगा। साथ ही खिलाड़ियों की फीस भी बड़ा मुद्दा होगा। हालांकि इस बीच ओलंपिक अगले साल तक टलने से उन खिलाड़ियों का फायदा होगा जो इस साल खेलों के महाकुंभ के लिए क्वालीफाई नहीं कर सके थे। उनके पास भी मौका होगा जो किसी कारण से या क्वालीफायर के दौरान चोटिल हो गए थे। अब उन्हें उबरने के लिए पूरे एक साल का समय मिल गया। भारत सरकार की टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना भी कोरोना महामारी के दौरान खिलाड़ियों के लिए वरदान साबित होगी। ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर चुके खिलाड़ियों को 2021 में आयोजित होने वाले ओलंपिक की तैयारियों के लिए पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।

खिलाड़ियों के लिए टॉप्स बनेगा वरदान

संदीप भूषण

कोविड 19 महामारी के कारण स्थगित ओलंपिक के आयोजन को लेकर तारीखों की घोषणा कर दी गई है। तोक्यो ओलंपिक अब अगले साल 23 जुलाई से आठ अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। इस साल इसे 24 जुलाई से नौ अगस्त के बीच कराया जाना था। इसे लेकर सभी देशों ने तैयारियां भी शुरू कर दी थी। कई क्वालीफायर भी हो चुके थे। इनमें भारत के खाते में 41 कोटा आए थे। इससे यह पक्का हो गया कि लगभग 80 खिलाड़ी ओलंपिक में भारत का झंडा लहराने के लिए तैयार हैं। हालांकि कोरोना महामारी के कारण एथलीटों की तैयारी और व्यवस्था पर सरकार को ज्यादा खर्च करना होगा।

बता दें कि फरवरी तक भारत के खाते में 31 कोटे थे लेकिन मुक्केबाजों के धमाकेदार प्रदर्शन ने अचानक ही इसकी संख्या बढ़ा दी। भारतीय खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन ने यह भी साबित किया कि भारत सरकार ने जिस उद्देश्य के साथ टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) की शुरुआत की थी, उसमें वह सफल हो रही है।

दरअसल, 2016 के रियो ओलंपिक में भारत ने 117 खिलाड़ियों का बड़ा दल भेजा था। इनमें 63 पुरुष और 54 महिलाएं शामिल थे। यह ओलंपिक इतिहास में भारत का सबसे बड़ा दल था। पूरे देश को उम्मीद थी कि पदकों की संख्या लंदन से बेहतर होगी। लेकिन हुआ इसके उलट। भारत के खाते में सिर्फ दो पदक आए। ओलंपिक में इस प्रदर्शन के बाद सरकार ने भारत को खेल महाशक्ति बनाने की दिशा में कई अहम कदम उठाए। इसमें से एक टॉप्स है। इस योजना के तहत सरकार हर उस खिलाड़ी को सवारने का काम करती है जिसके भीतर प्रतिभा और क्षमता हो। इस योजना ने खिलाड़ियों को आर्थिक मोर्चे पर मजबूत किया और उन्हें सिर्फ खेल में ध्यान लगाने में मदद की। अब इसका फायदा भी दिखने लगा है।

आरटीआइ के तहत मिली जानकारी के मुताबिक 2016 से जनवरी 2020 तक टॉप्स के तहत लगभग 56 करोड़ रुपए खिलाड़ियों पर खर्च किए गए। इसमें तीरंदाजी से लेकर जूडो तक के खिलाड़ी शामिल हैं। नौ ओलंपिक कोटा हासिल कर इतिहास रचने वाले मुक्केबाजों पर सरकार ने 2016 से जनवरी 2020 तक लगभग तीन करोड़ एक लाख 85 हजार रुपए खर्च किए। एथलीटों को संवराने पर सरकार ने छह करोड़ 30 लाख के करीब खर्च किए। वहीं निशानेबाजी पर सबसे ज्यादा खर्च किया गया। निशानेबाजों को ओलंपिक तैयारी के लिए 11 करोड़ 68 लाख के करीब रुपए दिए गए। इसका फायदा भी खूब दिखा। तोक्यो ओलंपिक में अब के रेकार्ड 15 निशानेबाज अपना हुनर दिखाएंगे। यह संख्या 2016 के रियो ओलंपिक के मुकाबले तीन अधिक है। यही नहीं खेलों के इस महाकुंभ में रैंकिंग के आधार पर भी कई निशानेबाज हिस्सा ले सकते हैं।

भारतीय निशानेबाज में बीते कुछ सालों में आश्चर्यजनक तौर पर वृद्धि देखने को मिला है। देश के कई युवा ने सर्वोच्च स्तर पर प्रदर्शन करते हुए विश्व कप, राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते हैं।

इसके अलावा पहलवानों को भी दांव-पेच सिखाने में सरकार ने कोई कमी नहीं की। उन्हें पांच करोड़ 25 लाख रुपए दिए गए। बात विनेश फोगाट की हो या बजरंग पूनिया की या फिर रवि कुमार दहिया की, इन सभी पहलवानों का प्रदर्शन बीते समय में काफी अच्छा रहा है। टॉप्स के माध्यम से सरकार ने भी इनकी मदद की और प्रशिक्षण में कहीं कोई कमी नहीं रहने दी। इसके अलावा भी कई खेलों के खिलाड़ियों को इस योजना के तहत फायदा पहुंचाया जा रहा है ताकि वो ओलंपिक के अपने सपने को साकार कर सकें।

आरटीआइ में दिए जवाब के मुताबिक इस वक्त टॉप्स योजना के तहत 94 खिलाड़ियों को मदद दी जा रही है। इसका फायदा भी दिखने लगा है। जिन 71 लोगों ने ओलंपिक कोटा हासिल किया है उनमें से ज्यादातर खिलाड़ी टॉप्स में शामिल हैं। मसलन, भालाफेंक एथलीट नीरज चोपड़ा, तीन हजार मीटर स्टीपलचेज अविनाश साबले और 400 मीटर रिले टीम में मोहम्मद अनस। वहीं टॉप्स में शामिल निशानेबाजों ने तो झंडा ही फंहराया। इस योजना में शामिल 17 निशानेबाजों में से 15 ने कोटा हासिल किया। मुक्केबाजी में टॉप्स के नौ में से पांच ने कोटा हासिल किया। यह खेलों में भारत के बढ़ती ताकत ही नमूना है।

56
करोड़ रुपए खर्च किए गए टॉप्स योजना के तहत 2016-20 तक

11
करोड़ 68 लाख के करीब रुपए दिए गए निशानेबाजों को योजना के तहत

बढ़ेगा पदक का इंतजार

कोरोना महामारी के कारण ओलंपिक के एक साल के लिए टलने से क्वालीफाई कर चुके खिलाड़ियों के लिए पदक का इंतजार लंबा हो गया। हालांकि इसका सकारात्मक पक्ष भी है। उन्हें अपनी तैयारी पुख्ता करने के लिए एक साल का समय मिल गया।

खर्च में भी होगी बढ़ोतरी

टॉप्स में शामिल खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर समय-समय पर समीक्षा होती है। अधिकारी इस दौरान कुछ नाम शामिल करते हैं तो कुछ को इस योजना से बाहर किया जाता है। लेकिन ओलंपिक टलने से क्वालीफाई कर गए खिलाड़ियों के लिए टॉप्स के तहत सहायता देना हर हाल में जारी रखना होगा। इससे सरकार को खाते से ज्यादा खर्च करने होंगे।

क्या है टॉप्स

भारत सरकार ने 2020 ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना की शुरुआत की। इसके तहत ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें तैयारी के लिए वित्तीय समर्थन दिए जाने का प्रावधान है।

ओलंपिक : जापान सरकार पर कोरोना से पड़ी दोहरी मार

जापान अपनी उम्दा तकनीक और कर्मठता के लिए जाना जाता है। उसने अब तक कई त्रासदियों का सामना किया और उससे उबरा भी है। ओलंपिक 2020 की मेजबानी जब तोक्यो को सौंपी गई तो जापान में रहने वाले लोगों को लिए यह किसी पर्व की घोषणा की तरह ही था। 2013 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जापान को मेजबान बनाया और तब से ही वह इसकी तैयारी में जुट गया। जनवरी 2020 तक उसने अपनी तैयारी लगभग पूरी भी कर ली। भीषण गर्मी से बचने के लिए तकनीक का इस्तेमाल हो या खेल गांव बनाने, सबमें उसने सौ फीसद नंबर हासिल किए। लेकिन अचानक ही कोविड 19 महामारी के कारण ओलंपिक को स्थगित करना पड़ा और अब इसका आयोजन अगले साल किया जाना है। हालांकि इससे जापान को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। साथ ही इसे जुड़े हितधारकों को भी खामियाजा भुगतना पड़ा है।

ओलंपिक के आयोजन के लिए शुरुआती बजट में संशोधन के साथ जापान ने इसे 12.6 बिलियन डॉलर किया। हालांकि स्थानीय अखबारों का कहना है कि इसके आयोजन में निर्धारित बजट से ज्यादा खर्च किया गया है। 2021 में इसके आयोजन से अब यह बजट और बढ़ जाएगा। साथ ही कई स्तर पर जापान को नुकसान भी उठाना पड़ेगा।

एक शोध रपट की माने तो जापान के ओलंपिक आयोजन समिति को खेलों के महाकुंभ के स्थगित होने से लगभग 600 अरब येन का नुकसान होगा। वहीं तोक्यो शहर और हितधारकों का 597 अरब येन का नुकसान होगा। रपट के मुताबिक खेलों से स्थानीय व्यापारियों को जो फायदा होने वाला था उसमें लगभग साढ़े तीन सौ अरब की कमी आएगी। वहीं जापानी सरकार को 150 अरब येन का घाटा होगा।

दूसरी तरफ इतने बड़े आयोजन के प्रसारण के लिए भी भव्य इंतजाम किए गए थे। स्थगन के बाद स्थानीय प्रायोजक और प्रसारकों को लगभग 900 मिलियन डॉलर का झटका लगा है। राष्ट्रीय प्रसारक को भी लगभग 1200 मिलियन का नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना होगा।

किसी भी टूर्नामेंट के आयोजन के साथ ही उसके लिए बीमा का भी इंतजाम किया जाता है। इससे किसी भी विपरीत समय में आयोजनकर्ता के नुकसान की कुछ हद तक भरपाई यहीं से होती है। जाहिर है कि ओलंपिक के लिए भी इस योजना को अमलीजामा पहनाया गया होगा। रपट के मुताबिक 2020 तोक्यो ओलंपिक के बीमा प्रदाता कंपनियों को भी नकसाने उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए।

आंकड़ों की बात करें तो प्रसारण अधिकार और प्रायोजकों को दिए गए बीमा से कंपनी को लगभग दो हजार मिलियन डॉलर का नुकसान होगा। वहीं, एथलीटों के रहने व उनके स्टेडियम तक की व्यवस्था पर किए गए बीमा से कंपनी को लघबग 600 मिलियन डॉलर का नुकसान होगा।

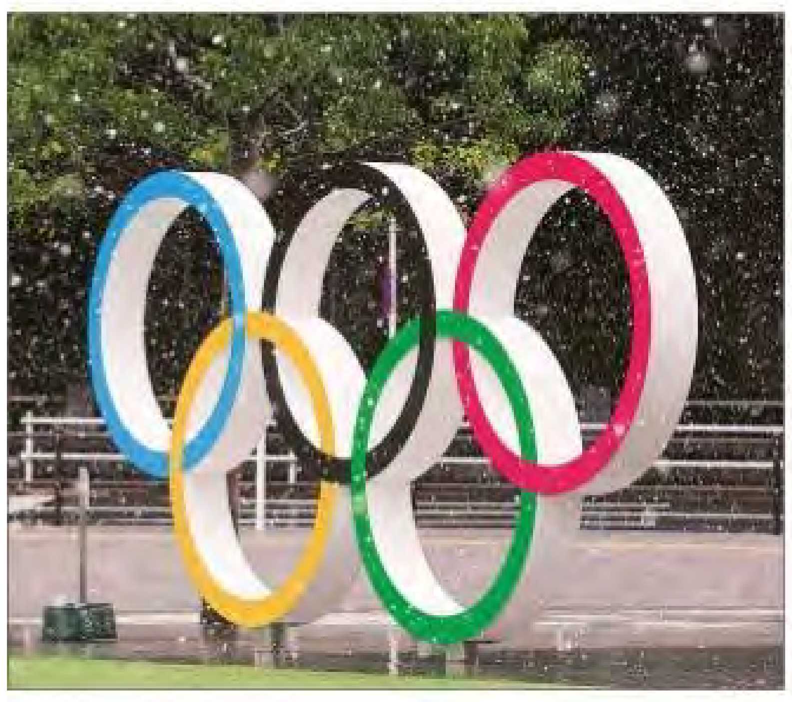

ओलंपिक स्थगन से लगभग 11 हजार एथलीट प्रभावित हुए हैं। इनमें कई ऐसे देश के भी हैं जहां की अर्थव्यवस्था काफी खराब है। ऐसे में खिलाड़ियों की तैयारी पर एक साल और खर्च करना उनके लिए अतिरिक्त बोझ से कम नहीं है। वहीं इसकी जद में लगभग 44 सौ पैराएथलीट भी आएंगे। वहीं 80 हजार से ज्यादा कार्यकर्ताओं को भी कोरोना महामारी से झटका लगा है।

12.6
बिलियन डॉलर था ओलंपिक का संशोधित बजट

900
मिलियन डॉलर का नुकसान होगा स्थानीय प्रायोजक और प्रसारकों को

600
बिलियन येन का नुकसान होगा तोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति को

फुर्सत में

खेल गतिविधियां बंद होने के कारण क्रिस्टियानो रोनाल्डो परिवार के साथ समय गुजार रहे हैं। उन्होंने इस तस्वीर को ट्विटर पर साझा किया है।

फुटबॉल की भी निकाली हवा

कोरोना विषाणु महामारी ने दुनिया की लगभग आधी आबादी को घर में कैद होने पर मजबूर कर दिया है। कारोबार पूरी तरह ठप है। खेल गतिविधियां बंद हैं। कई टूर्नामेंटों को रद्द किया जा चुका है। कई की तारीखें आगे बढ़ा दी गई हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान फुटबॉल जगत को हुआ है। लोकप्रियता के मामले में शीर्ष पर काबिज इस खेल के खिलाड़ियों, टीमों और प्रायोजकों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है।

इटली, ब्रिटेन सहित कई यूरोपिय देश पूरी तरह से इस महामारी के चपेट में हैं। ऐसे में इंग्लिश प्रीमियर लीग और सीरी ए जैसी शीर्ष लीग बंद है। यूरोपियन फुटबॉल संघ अकेले लगभग 2800 मिलियन यूरो का रेवेन्यू वाले लीगों का नेतृत्व करता है। वहीं फीफा के रेवेन्यू की बात करें तो यह 4.64 बिलियन डॉलर के करीब है। दूसरी तरफ अमेरिका में भी फुटबॉल से जुड़ी सभी गतिविधियां ठप हैं।

कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित यूरोपियन देशों में होने वाले लीगों की कमाई की बात करें तो स्पेन को करीब 3790 मिलियन यूरो, इटली को 2570 मिलियन यूरो, जर्मनी 3720 मिलियन यूरो और फ्रांस को 1930 मिलियन यूरो है। इंग्लैंड इसमें सबसे आगे है जिसे इंग्लिश प्रीमियर लीग के सहारे करीब 5940 मिलियन की कमाई होती है। यहां होने वाली लीगों के मुनाफे में सबसे बड़ा हिस्सा मीडिया के अधिकार बेचने का ह फुटबॉल चैंपियनशिप को 2021 तक के लिए टाल दिया है। ऐसे में उन्हें लगभग 300 मिलियन यूरो का नुकासान उठाना पड़ेगा। हालांकि यह आंकड़ा सिर्फ स्थगन तक सीमित है। अगर किसी कारण से 2019/20 सत्र के इस चैंपियनशिप को रद्द कर दिया जाता है तो नुकसान का आंकड़ा लगभग 100 मिलियन यूरो बढ़ जाएगा।

यूरोपियन फुटबॉल संघ को सबसे ताकतवर और कमाई वाला संघ माना जाता है। ऐसे में अगर 2019/20 सत्र के ज्यादातर मैच रद्द होते हैं तो इसका खामियाजा मीडिया प्रसारकों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। एक रपट के मुताबिक अगर इंग्लिश प्रीमियर लीग को रद्द कर दिया जाता है तो करीब मीडिया प्रसारकों को लगभग 800 मिलियन यूरो का नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं इटली की शीर्ष फुटबॉल लीग सीरी ए के रद्द या स्थगन पर भी मीडिया प्रसारकों को नुकसान होगा। इस टूर्नामेंट के मुख्य प्रसारकों में शामिल स्काई को लगभग 252 मिलियन यूरो और डेंज को 64.3 मिलियन यूरो का नुकसान होगा।

जनसत्ता के पाक्षिक खेल पेज के लिए लेख भेजें
Khel.jansatta@expressindia.com

आइपीएल 2020 पर कोविड 19 का बाउंसर

जब क्रिकेट की बात आती है तो भारत का नाम आना लाजमी है। यहां क्रिकेट को धर्म और खिलाड़ियों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। क्रिकेट का मैच भारतीय प्रशंसकों के लिए निर्जला एकादशी से कम नहीं होता। ऐसे देश में जब इंडियन प्रीमियर लीग का सत्र शुरू होता है तो मानों महोत्सव का रूप ले लेता है। लगभग महीने भर चलने वाले इस क्रिकेट महोत्सव में कई देश के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। उन्हें बड़ी बोली के साथ फ्रेंचाइजी टीम में शामिल किया जाता है। कहावत यह भी मशहूर है कि आइपीएल में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। लेकिन इस साल इसके आयोजन के बीच कोरोना विषाणु महामारी ने तबाही मचा रखी है। मार्च के अंतिम सप्ताह में शुरू होने वाले इस महोत्सव को 15 अप्रैल तक टाल दिया गया है। हालात नहीं सुधरे तो इसे रद्द भी किया जा सकता है। ऐसे में समझने की कोशिश करते हैं कि आइपीएल खिलाड़ियों, फ्रेंचाइजियों और अन्य हितधारकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है।

15 अप्रैल के बाद आइपीएल को शुरू किया जाता है तो बीसीसीआइ के पास इसे दो तरह से आयोजित कराने का विकल्प है। इन विकल्पों पर पहले भी चर्चा की जा चुकी है। पहला रास्ता तो यह होगा कि 60 मैच के इस टूर्नामेंट को कम समय में ही करा दिया जाए। इसके लिए उन्हें एक दिन में दो मैच कराने होंगे। पहले सिर्फ शनिवार और रविवार को ही दो मैच कराए जाते थे। बीसीसीआइ के पास दूसरा रास्ता है कि मैचों की संख्या को घटाया जाए। ऐसे में लीग मैचों की संख्या को कम किया जा सकता है। इन दोनों ही विकल्पों से आइपीएल के हितधारकों को वित्तीय नुकसान होना तय है। हालांकि यह पहले विकल्प में नुकसान कम और दूसरे में ज्यादा है।

इन दोनों के अलावा एक विकल्प यह भी है कि आइपीएल को रद्द कर दिया जाए। इसकी संभावना भी ज्यादा है। क्योंकि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, उन हालात में इसे करा पाना काफी मुश्किल है। साथ ही भारत सरकार के अलावा कई देश की सरकारों ने अपने यहां से विदेशी के आने या किसी भी नागरिक के विदेश जाने पर 15 अप्रैल के बाद तक भी पाबंदी लगा रखी है। ऐसे में जिन विदेशी खिलाड़ियों पर मोटी रकम खर्च की गई है उनका भारत आना तय नहीं है।

अब अगर आइपीएल के आयोजन के तीनों विकल्पों पर निगाह डालें तो नुकसान तय है लेकिन कितना, इसका अंदाजा लगा पाना अभी मुश्किल है। फिर भी फ्रेंचाइजियों के अब तक के मुनाफे और आइपीएल के कारोबार व ब्रांड वैल्यू के मुताबिक नुकसान बड़ा होगा। खर्च के चक्र पर ध्यान लगाए तो प्रायोजक और प्रसारक हर साल बीसीसीआइ को लगभग 4000 करोड़ रुपए देते हैं। बीसीसीआइ इसका लगभग 50 फीसद हिस्सा फ्रेंचाइजियों को देती है। हर फ्रेंचाइजी 85 करोड़ रुपए खिलाड़ियों पर खर्च करता है। जो कुल मिलाकर 680 करोड़ रुपए होता है। इसके बाद बीसीसीआइ और फ्रेंचाइजी दोनों 50-50 लाख रुपए उस राज्य संघ को देते हैं जो मैच का आयोजन करता है।

अब आइपीएल से कमाई की बात करें तो बीसीसीआइ हर साल करीब 2000 करोड़ रुपए प्रसारक और प्रायोजकों से कमाता है। प्रसारणकर्ता को विज्ञापन और अन्य मदों से करबी 3300 करोड़ रुपए मिलते हैं। वहीं अन्य केंद्रीय प्रायोजकों को करीब साढ़े सात सौ करोड़ की कमाई होती है। हर फ्रेंचाइजी को प्रतिवर्ष केंद्रीय पूल के तहत 250 करोड़ मिलते हैं। साथ ही उन्हें स्थानीय प्रायोजकों से लगभग 30 करोड़ की कमाई होती है। क्रिकेटरों के खाते में 680 करोड़ रुपए जाते हैं।

अब ऐसे में जाहिर है कि अगर आइपीएल रद्द हुआ तो इन सबों को बड़ा नुकासान उठाना पड़ेगा। अगर रद्द न होकर इसे पहले या दूसरे विकल्प के तहत भी कराया गया तो भी हजारों करोड़ का नुकसान होगा। यानी कोरोना विषाणु ने भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े महाकुंभ को डंस लिया है।

आइपीएल से कमाई की बात करें तो बीसीसीआइ हर साल करीब 2000 करोड़ रुपए प्रसारक और प्रायोजकों से कमाता है। प्रसारणकर्ता को विज्ञापन और अन्य मदों से करबी 3300 करोड़ रुपए मिलते हैं। वहीं अन्य केंद्रीय प्रायोजकों को करीब साढ़े सात सौ करोड़ की कमाई होती है। हर फ्रेंचाइजी को प्रतिवर्ष केंद्रीय पूल के तहत 250 करोड़ मिलते हैं। साथ ही उन्हें स्थानीय प्रायोजकों से लगभग 30 करोड़ की कमाई होती है। क्रिकेटरों के खाते में 680 करोड़ रुपए जाते हैं।

www.readwhere.com

स्वास्थ्यकर्मियों को डब्लूएचओ के मानक वाली सुरक्षा सामग्री मुहैया कराने का मामला

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 1 अप्रैल (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने देश में कोरोना विषाणु के मरीजों का उपचार कर रहे डाक्टरों, नर्सों और सहयोगी कर्मचारियों को विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक वाली सुरक्षा सामग्री उपलब्ध कराने के लिए याचिका पर बुधवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह के पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मामले में सुनवाई के दौरान सालिसीटर जनरल तुषार मेहता को इस पर गौर करने और अगले सप्ताह जवाब देने का निर्देश दिया।

डॉक्टरों, नर्सों और सहयोगी कर्मचारियों को विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुरूप सुरक्षा सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश देने के लिए नागपुर निवासी एक चिकित्सक ने यह याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि उचित सुरक्षा सामग्री के अभाव में कोरोना विषाणु संक्रमण से ग्रस्त मरीजों का इलाज करते समय चिकित्सक, नर्स और दूसरे सहयोगी कर्मचारियों के भी इस वायरस की चपेट में आने का खतरा है।

याचिका में कहा गया है कि यह इस तरह का इलाज कर रहे चिकित्सकों, नर्सों और दूसरे सहयोगी कर्मचारियों को अपने बचाव के

-डॉक्टरों, नर्सों और सहयोगी कर्मचारियों को विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुरूप सुरक्षा सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश देने के लिए नागपुर निवासी एक चिकित्सक ने यह याचिका दायर की है।

-याचिका में कहा गया है कि केंद्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोरोना विषाणु से संक्रमित मरीजों का इलाज करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और दूसरे सहायक कर्मचारियों के पास हजमत सूट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), कलफ लगे कपड़े, मेडिकल मास्क, दस्ताने, चेहरे की रक्षा करने वाले उपकरण, श्वास यंत्र और सिर ढंकने सहित सारे सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हों।

लिए इस तरह की सुरक्षा सामग्री उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है।

याचिकाकर्ता जेरिल बनैत, जो स्वयं एक चिकित्सक हैं, ने छोटे कस्बों और शहरों में कोविड-19 विशेष जांच केंद्र स्थापित करने का राज्यों को निर्देश देने का भी अनुरोध किया है। इसके अलावा, उन्होंने संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 25 जनवरी को जारी दिशानिर्देशों का सख्ती से अमल सुनिश्चित करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है।

याचिका में कहा गया है कि कोविड-19 के मामले में पीपीई के तर्कसंगत उपयोग के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर अमल सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकारियों को निर्देश दिए जाएं। इसी तरह, चिकित्सकों और दूसरे कर्मचारियों के लिए भोजन, उन्हें ले जाने के लिए अलग व्यवस्था और आवास या पृथक कमरों की सुविधा प्रदान करने का भी अनुरोध याचिका में किया गया है ताकि उनके परिवारों को सुरक्षा मिल सके।

याचिका में कोविड-19 के संभावित मरीजों की जांच और निगरानी के लिए तत्काल व्यापक स्तर पर कदम उठाने और निजी एजंसियों या लैब के जरिए जांच के बारे में दिशानिर्देश जारी करने का भी अनुरोध किया गया है। डा बनैत के अनुसार, 'चूंकि कोविड-19 से बचाव या इलाज के लिए कोई निश्चित दवा नहीं है, इसलिए डॉक्टरों के लिए लगातार अपने मरीजों के संपर्क में रहना और उनके लक्षणों पर निगाह रखना जरूरी है। उचित सुरक्षात्मक सामग्री के अभाव में ये चिकित्सक अपने दायित्वों का निर्वहन करने के दौरान खुद इस वायरस की चपेट में आने का जोखिम मोल ले रहे हैं।'

मनरेगा मजदूरों को अग्रिम भुगतान के लिए सोनिया ने पीएम को पत्र लिखा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 अप्रैल।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार अधिनियम (मनरेगा) के तहत पंजीकृत मजदूरों को 21-21 दिन की दिहाड़ी का अग्रिम भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है। कोरोना लॉकडाउन की वजह से करोड़ों मजदूरों को हुए नुकसान का हवाला देते हुए सोनिया ने मनरेगा मजदूरों को अविलंब आर्थिक सहायता मुहैया कराए जाने की जरूरत बताई है।

प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में मनरेगा को गरीबों की जीवन रेखा करार देते हुए दावा किया है कि करोड़ों गरीबों के लिए तह योजना वरदान साबित हुई है। सोनिया ने लिखा है कि फसलों की कटाई के इस बेहद महत्त्वपूर्ण मौसम में लाखों मजदूर बेरोजगार होने को विवश हैं। उनके पास आय का कोई दूसरा स्रोत भी नहीं है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग मनरेगा के तहत रोजगार की मांग कर सकते हैं जबकि कोरोना महामारी के मद्देनजर किए गए लॉकडाउन के तहत सुरक्षित दूरी के मद्देनजर सबको रोजगार देना मुमकिन नहीं हो पाएगा। दूसरी ओर यदि कोरोना के इस लॉकडाउन के बाद इन गरीब मजदूरों को रोजगार मिलता भी है तो भी उन्हें वेतन मिलने में कम से कम एक महीने का समय लगेगा।

विभिन्न देशों की तकनीक व श्रेष्ठ अनुभव अपनाने को भारत इच्छुक

नई दिल्ली, 1 अप्रैल (भाषा)।

भारत कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दक्षिण कोरिया, जर्मनी, चीन जैसे देशों से अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी खरीदने और इस महामारी से निपटने में इन देशों के श्रेष्ठ पहल व अनुभवों को अपनाने को इच्छुक है। इन देशों में स्थित भारतीय मिशनों से सहयोग के संभावित क्षेत्रों की तत्काल पहचान करने और चिकित्सा उपकरणों व प्रौद्योगिकी की खरीद के लिए संबंधित प्राधिकार से संपर्क करने को कहा गया है।

यह पहल ऐसे समय में की गई है जब पिछले कुछ दिनों में देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के पॉजिटिव मामलों की संख्या में तेजी देखी गई है। प्रधानमंत्री ने सोमवार को भारतीय उच्चायोग/दूतावासों के प्रमुखों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संवाद के दौरान इस महामारी से निपटने में श्रेष्ठ पहल, नवोन्मेष, वैज्ञानिक अनुसंधान, चिकित्सा उपकरण की जरूरत को रेखांकित किया था।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार भारत की खासतौर पर दक्षिण कोरिया के व्यापक जांच के उपायों व संदिग्धों की डिजिटल निगरानी जैसे कदमों पर खास नजर है। दक्षिण कोरिया का 'पता लगाओ, जांच करो और उपचार करो' की रणनीति को वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता मिली है । दक्षिण कोरिया ने इस महामारी से निपटने में लॉकडाउन नहीं किया और वहां कारोबार व आर्थिक गतिविधियां जारी हैं ।

चीन द्वारा भी 3300 लोगों की मौत और 80 हजार से अधिक लोगों के संक्रमित होने के बाद अपने देश में कोरोना वायरस के और अधिक फैलाव को रोकने के अनुभव को देखते हुए भारत इस संबंध में चीन व कुछ अन्य देशों से चिकित्सा उपकरण एवं प्रौद्योगिकी खरीदने को इच्छुक है। अधिकारियों ने बताया कि में भविष्य की जरूरतों के लिए तैयारी करनी है। इसलिए हम उपलब्ध श्रेष्ठ प्रौद्योगिकी व चिकित्सा उपकरणों के लिए वैश्विक बाजार को देख रहे हैं।

बेजिंग में भारतीय दूतावास को चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए संबंधित प्राधिकार से समन्वय स्थापित करने को कहा गया है। कई अवसरों पर चीन ने कहा कि वह इस महामारी से निपटने के लिए भारत को हर संभव मदद देने को तैयार है। अधिकारियों का कहना है कि भारत तत्काल 10 हजार वेंटिलेटर की खरीद के लिए चीन के कई आपूर्तिकर्ताओं के संपर्क में है।

उन्होंने बताया कि भारत कोरोना वायरस से निपटने के जर्मनी के प्रयासों को भी जांच परख रहा है। सूत्रों ने बताया कि वायरस के संक्रमण की प्रयोगशाला जांच के लिए ट्रंप प्रशासन से सहयोग को लेकर वाशिंगटन में भारतीय राजनयिक ट्रंप प्रशासन से समन्वय कर रहे हैं।

निजामुद्दीन के मरकज से देश में बढ़ी संक्रमितों की संख्या

पेज 1 का बाकी

के मामले रोकने के लिए पूर्ण बंदी का पालन सुनिश्चित करना ही एकमात्र उपाय है। इसलिए हम सभी को जरूरी सामान की खरीदारी के समय भी सामुदायिक दूरी का विशेष ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने कहा, 'हमें सबकुछ पता है, हमें कुछ नहीं होगा' वाली सोच से बाहर निकलकर सरकार की ओर से दिए जा रहे निर्देशों को सौ फीसद पालन करना होगा।

अग्रवाल ने कहा कि इसकी रोकथाम के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में बुधवार को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक में राज्यों के स्तर पर संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों और पूर्ण बंदी का पालन सुनिश्चित करने के उपायों की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि बैठक में प्रवासी मजदूरों को संक्रमण के खतरे से बचाने के लिए पृथक रखने और उनकी सहायता के लिए शुरू किए गए कार्यों को पूरा करने के प्रयासों की भी समीक्षा की गई।

संवाददाता सम्मेलन में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) के रमन आर गंगाखेड़कर ने बताया कि देश भर में कार्यरत आइसीएमआर की प्रयोगशालाओं में 24 घंटों में 4562 नमूनों की जांच की गई जबकि अब तक कुल 47,951 जांच हुई हैं।

मरकज खाली कराने के बाद शुरू हुई मौलाना साद की तलाश

पेज 1 का बाकी

अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया है। इसके अलावा बाकी बचे लोगों को पृथक केंद्र (क्वारंटाइन सेंटर) ले जाया गया है। साइबर सेल इन 2361 लोगों के संपर्क में आए लोगों की भी शिनाख्त कर रहा है। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के जिम्मे है।

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मौलाना साद फोन का इस्तेमाल नहीं करता। उनके दो घर हैं, एक निजामुद्दीन में और एक जाकिर नगर में। फिलहाल उसके पते ठिकाने के बारे में अभी पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन सूत्रों का मानना है कि उसने खुद को आइसोलेशन में रखा है। पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआइआर में मौलाना साद, डॉक्टर जीशान, मुफ्ती शहजाद, मोहम्मद अशरफ, मुर्सलीन सैफी, यूनिस मोहम्मद और सलमान के नाम हैं।

इस बीच, मरकज को खाली कराने के बाद दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के अलग-अलग इलाके में स्थित मस्जिदों और मदरसों को खंगालना शुरू कर दिया है। वजीराबाद और मंगोलपुरी मस्जिदों में छिपे लोगों को भी पुलिस ने ढूंढ निकाला है। आशंका है कि इसी तरह से भारत और भारत के बाहर के नागरिक निजामुद्दीन से निकलकर दिल्ली के अलग-अलग इलाके में छिपे हो सकते हैं। पुलिस ने आम लोगों से भी यह अनुरोध किया है कि वे ऐसे किसी व्यक्ति और सामूहिक रूप से रह रहे लोगों के बारे में तुरंत सूचना उपलब्ध कराएं ताकि महामारी को रोका जा सके। पुलिस ने इनकी तलाश में मस्जिदों और मदरसों के साथ अन्य संदिग्ध ठिकानों की भी पहचान शुरू कर दी है।

वजीराबाद की गली नंबर नौ में स्थित जामा मस्जिद के मौलवी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मस्जिद में 15 विदेशी मौजूद थे जो पहले निजामुद्दीन के मरकज में शामिल हुए थे। इन 15 में से 12 नागरिक इंडोनेशिया के हैं। ये नागरिक निजामुद्दीन में आयोजित जमात से लौटकर इन मस्जिदों में ठहरे थे। इन सभी लोगों के नमूने लेने के बाद क्वांरटाइन में रहने के लिए कहा गया है। इस बात की भी जांच की जा रही है कि ये 15 विदेशी नागरिक इस दौरान कहां-कहां ठहरे थे और कौन-कौन इनके संपर्क में आया था।

मंगोलपुरी में भी मरकज से लौटे कुछ मौलवियों को संक्रमण की आशंका के बाद अस्पताल में जांच के लिए ले जाया गया है। यहां मिले सभी सात विदेशी इंडोनेशिया के हैं। इनके भी नमूले लेने के बाद क्वांरटाइन में भेज दिया है।

अमेरिका में मरने वालों की संख्या चार हजार के पार

पेज 1 का बाकी

अंततः उम्मीद की कोई रोशनी दिखेगी। लेकिन ये दो हफ्ते बहुत-बहुत दर्दनाक होने वाले हैं।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार केवल न्यूयॉर्क में 31 मार्च तक कोरोना विषाणु के 41,771 मामले सामने आ चुके हैं और 1,096 लोगों की मौत हो चुकी है। कम से कम 8,400 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और उनमें से 1,888 लोग आइसीयू में हैं। अमेरिका में कोरोना विषाणु का केंद्र बने न्यूयॉर्क राज्य में कोरोना विषाणु से मृतकों की संख्या डेढ़ हजार के पार हो गई।

राज्य के गवर्नर एंड्रियू कुओमो ने आगाह किया है कि यह संकट खत्म होने से पहले हजारों लोगों की जान ले सकता है। राज्य और शहर के अधिकारी पर्याप्त चिकित्सा उपकरणों की खरीद व आपूर्ति और यहां तक कि स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों का इंतजाम करने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। पूरे राज्य में अस्पताल अपनी क्षमता से अधिक काम कर रहे हैं, ऐसे में सेंट्रल पार्क, सम्मेलन केंद्रों, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मैदान समेत पूरे शहर भर के विभिन्न स्थानों पर अस्थायी अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है।

उधर, अमेरिका में कोरोना विषाणु से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें एक-दूसरे से दूरी बनाए रखने समेत आवागमन पर रोक तक शामिल है ताकि तेजी से देश में पांव पसार रहे कोरोना विषाणु को रोका जा सके। अमेरिका के शीर्ष वैज्ञानिकों व अनुसंधानकर्ताओं के प्रयासों के बावजूद भी अब तक इस खतरनाक विषाणु का टीका नहीं बन पाया है। इस तरह के टीके बनने में वर्षों लग जाते हैं लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इस प्रक्रिया को तेज कर रखा है लेकिन अभी भी इसमें महीनों का समय लग सकता है।

वाइट हाउस के संवादताता सम्मेलन में मंगलवार को राष्ट्रीय एलर्जी व संक्रामक बीमारी संस्थान के निदेशक और कोरोना विषाणु से निपटने के लिए वाइट हाउस कार्य बल के सदस्य एंथनी फौसी ने बताया कि उन्हें विश्वास है कि इन कदमों से नए मामलों में कमी आएगी।

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अगले 30 दिन में कोरोना विषाणु के खिलाफ लड़ाई में ये कदम आवश्यक हैं। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि अगर 30 अप्रैल तक चीजें नियंत्रण में नहीं आईं तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

ग्राहकों को मोहलत से लाभ नहीं, भरना होगा ब्याज

पेज 1 का बाकी

लगाने की अनुमति दी थी। केंद्रीय बैंक ने कहा था कि अगर इस अवधि के दौरान कर्ज की किस्त नहीं आती है तो उसे चूक नहीं माना जाना चाहिए तथा उसकी सूचना कर्ज जानकारी रखने वाली कंपनियों को नहीं दी जानी चाहिए। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) ने ग्राहकों को भेजी सूचना में कहा कि मोहलत अवधि के दौरान जो भी बकाया राशि है, उस पर ब्याज जुड़ता रहेगा। बढ़ा हुआ ब्याज उन कर्जदारों से अतिरिक्त ईएमआइ के जरिए लिया जाएगा, जो तीन महीने की मोहलत का विकल्प चुनते हैं। एसबीआइ ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर संबंधित ग्राहक का मकान कर्ज 30 लाख रुपए हैं और इसे लौटाने की अवधि 15 साल बची हुई है, तो तीन महीने की मोहलत अवधि का विकल्प लेने पर 2.34 लाख रुपए के करीब अतिरिक्त ब्याज लगेगा जो आठ किस्त के बराबर है।

इसी प्रकार, अगर ग्राहक ने छह लाख रुपए का वाहन कर्ज ले रखा है और उसे लौटाने के लिए 54 महीने का समय बचा है तो छूट अवधि का विकल्प चुनने पर उसे 19,000 रुपए करीब अतिरिक्त ब्याज देना होगा जो 1.5 अतिरिक्त ईएमआइ के बराबर है।

बुजुर्ग दंपति के आगे कोरोना हुआ बेदम

पेज 1 का बाकी

दौरान भी थॉमस पझनकांजी और नारियल की चटनी, कप्पा ही खाने के लिए मांगते थे और उन्हें यही दिया गया। उन्होंने कहा, 'वे लोग (दादा दादी) हमारे आने (इटली से) और घर को खुशियों से भर देने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन.... अब हम उनके घर लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। परिवार ने बुजुर्ग दंपति के लौटने की खुशी में पहले से ही तली हुई मछली, ग्रेवी वाली मछली और चावल आदि बना कर रखा है।

थॉमस और मरियम्मा के तीन बच्चे, सात पोते-पोतियां और 14 परपोते-परपोतियां हैं। परिवार में रिजो, उसके माता-पिता, दादा-दादी के अलावा उसकी बहन, बहनोई और चाचा भी कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे।

रिजो ने बताया, 'दादा दादी को उम्र संबंधी दिक्कतें भी थीं। लेकिन कोट्टायम मेडिकल कॉलेज के नर्सों और डॉक्टरों ने उन्हें अपने परिवार की तरह माना और उनका ख्याल रखा। हमारा जिस तरह से ख्याल रखा गया, उसके लिए हम सरकार, स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं।' रिजो की बहन और बहनोई दोनों नर्स हैं और आठ महीने पहले इटली से लौटे हैं।

सरकार पीपीएफ और छोटी बचत पर पुरानी ब्याज दर बहाल करे : चिदंबरम

नई दिल्ली, 1 अप्रैल (भाषा)।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र और लोक भविष्य निधि समेत लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें कम करने के फैसले की आलोचना करते हुए बुधवार को कहा कि सरकार को 30 जून तक के लिए पुरानी ब्याज दरें बहाल करनी चाहिए।

पूर्व वित्त मंत्री ने ट्वीट कर कहा, 'पीपीएफ और लघु बचत पर ब्याज दर कम करना तकनीकी रूप से सही हो सकता है, लेकिन ऐसा करने का यह गलत समय है।' चिदंबरम ने कहा, 'इस बहुत ही मुश्किल घड़ी और आय को लेकर अनिश्चितता के दौर में लोग अपनी बचत पर ब्याज से होने वाली आय पर निर्भर होते हैं।

सरकार को इस निर्णय पर तत्काल पुनर्विचार करना चाहिए और पहले की ब्याज दर को 30 जून तक बहाल करना चाहिए।' उन्होंने यह भी कहा, 'मेरे विचार से हमें विकास दर को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए।

फिलहाल लोगों की जिंदगियां बचाने पर जोर होना चाहिए।'

चिदंबरम ने पिछले दिनों घोषित वित्तीय पैकेज का जिक्र करते हुए कहा, 'मैं इस बात से चिंतित हूं कि सरकार ने 25 मार्च को बहुत ही कम वित्तीय पैकेज की घोषणा के बाद अब तक वित्तीय सहायता पैकेज का ऐलान नहीं किया।'

गौरतलब है कि सरकार ने मंगलवार को राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र और लोक भविष्य निधि समेत लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें 2020-21 की पहली तिमाही के लिए 1.4 प्रतिशत तक घटा दीं।

बैंक जमा दरों में कटौती के बीच यह कदम उठाया गया है।

पंद्रह साल से रह रहे लोगों को मिलेगा मूल निवासी का दर्जा

पेज 1 का बाकी

(विकेंद्रीकरण और भर्ती) अधिनियम है जिसमें मूल निवासी श्रेणी का उपबंध है। इस उपबंध में समूह चार तक की नौकरियों को सुरक्षित बनाया गया है। नए कानून के अनुसार जम्मू कश्मीर में 15 साल तक रहने वाला या सात साल तक पढ़ाई करने वाले और किसी शैक्षणिक संस्थान में दसवीं एवं बारहवीं कक्षाओं की परीक्षा देने वाला कोई भी व्यक्ति मूल निवासी है। राहत और पुनर्वास आयुक्त (प्रवासी) द्वारा प्रवासी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति को भी मूल निवासी माना जाएगा। राज्य में दस साल तक सेवाएं दे चुके नौकरशाहों (अखिल भारतीय सेवाओं के) के बच्चे भी इस श्रेणी में आएंगे।

केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, अखिल भारतीय सेवाओं, सार्वजनिक उपक्रम और केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त इकाइयों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वैधानिक इकाइयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अधिकारियों और केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त शोध संस्थानों के अधिकारियों के बच्चे भी इस श्रेणी में आएंगे बशर्ते इन अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर में दस साल से अधिक नौकरी की हो।

इस अधिसूचना के अनुसार, उपरोक्त शर्तों में किसी भी शर्त को पूरा करने वाले या जम्मू कश्मीर के ऐसे बाशिंदों के बच्चे, जो अपने रोजगार, कारोबार या पेशेवर या व्यावसायिक कारणों से इस केंद्रशासित प्रदेश के बाहर रहते हैं लेकिन उनके माता-पिता इस उपखंड की किसी भी शर्त को पूरा करते हैं, तो भी वे इस केंद्रशासित प्रदेश के निवासी समझे जाएंगे।

सरकार ने इस केंद्रशासित प्रदेश के निवासियों के लिए समूह चार की नौकरियां भी सुरक्षित की हैं और कहा कि कोई व्यक्ति तब तक समूह-4 तक के वेतनमान वाले पद के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश का मूल निवासी नहीं हो। समूह-4 पुलिस महकमे में कांस्टेबल के दर्जे के कर्मचारी के समान स्तर के हैं। सरकार ने इस केंद्रशासित प्रदेश के निवासी संबंधी नियम प्रक्रिया तय करते हुए पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के 138 कानूनों में से 28 निरस्त कर दिए हैं।

सरकार के बुधवार के कदम पर नवगठित जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी समेत राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने एक बयान में कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह ऐसे समय में जारी किया गया जबकि पूरा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह कदम जख्मों पर नमक छिड़कना है क्योंकि इस कानून में ऐसी कोई सुरक्षा नहीं है जिसका वादा किया गया था।

24 घंटे में 437 मामले, अब तक 41 की मौत

पेज 1 का बाकी

संक्रमितों की संख्या 302 पहुंच गई है। वहीं, केरल में संक्रमण के 241, कर्नाटक में 101 और तमिलनाडु में 234 मामले सामने आए हैं।

तेलंगाना में कोरोना विषाणु का संक्रमण 96 लोगों तक, राजस्थान में 93 तक, आंध्र प्रदेश में 83 तक, गुजरात में 82 तक, जम्मू कश्मीर में 62 तक, हरियाणा में 43 तक, मध्य प्रदेश में 66 तक, पंजाब में 42 तक, पश्चिम बंगाल में 37 तक, बिहार में 23 तक, लद्दाख में 13 लोगों तक, चंडीगढ़ में 16 तक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10 लोगों तक पहुंच चुका है।

छत्तीसगढ़ में नौ, उत्तराखंड में सात, गोवा में पांच, ओड़ीशा में चार, हिमाचल प्रदेश में तीन, पुदुचेरी में तीन, मणिपुर और मिजोरम में एक-एक मामला सामना आया है।

कोरोना में बीसीजी टीके भारत के लिए कवच

पेज 1 का बाकी

अधिक लोगों की जान गई है। इटली में 1,05,000 मामले सामने आए हैं और 12 हजार से अधिक लोगों की जान गई है। वहीं, नीदरलैंड में 12 हजार से अधिक मामले सामने आए हैं और एक हजार से अधिक लोगों की मौत हुई है।

अध्ययन के अनुसार संक्रमण और मौतों की कम संख्या बीसीजी टीकाकरण को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एक 'गेम-चेंजर' बना सकती हैं।

बीसीजी टीका भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा है और यह लाखों बच्चों को उनके जन्म के समय या इसके तुरंत बाद लगाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक टीबी रोगियों वाला देश होने के साथ भारत ने 1948 में बीसीजी टीकाकरण की शुरुआत की थी। भारतीय विशेषज्ञों ने कहा कि वे आशावान हैं, लेकिन इस बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा।

लवली प्रोफेशनल यूनिर्विसटी, पंजाब के एप्लाइड मेडिकल साइंसेज संकाय की डीन मोनिका गुलाटी ने कहा, 'हर छोटी चीज हमें उम्मीद की किरण दिखाती है। लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन यह सही बात है कि बीसीजी टीका सार्स संक्रमण के खिलाफ भी काफी प्रभावी रहा।' उन्होंने कहा, 'यह न सिर्फ इलाज में, बल्कि तीव्रता को कम करने भी प्रभावी था।' गुलाटी ने रेखांकित किया कि सार्स वायरस भी एक तरह का 'कोरोना वायरस' ही है।

उन्होंने कहा, 'क्योंकि मौजूदा महामारी बीसीजी का टीका लगाने वाले देशों में कम गंभीर है और यह टीका दूसरे कोरोना वायरस के खिलाफ भी प्रभावी था, इसलिए यह एक उम्मीद की किरण है।'

कोलंबिया एशिया अस्पताल, गाजियाबाद के इंटरनल मेडिसिन विभाग के दीपक वर्मा ने कहा कि कोविड-19 के किसी टीके की अनुपस्थिति में यह एक उत्साहजनक घटनाक्रम है। यह समझने में कुछ समय लगेगा कि टीबी का टीका कोरोना वायरस के खिलाफ किस तरह काम करता है।

हैदराबाद स्थित सीएसआइआर सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलीकुलर बॉयोलॉजी के निदेशक राकेश मिश्रा ने कहा कि एनवाईआईटी का अध्ययन रोचक है, लेकिन अधिक वैज्ञानिक ब्योरे की प्रतीक्षा है।

संपर्क में आए यात्रियों का पता लगाने को पांच ट्रेनों पर नजर

पेज 1 का बाकी

जगहों की यात्रा की। आशंका है कि इन लोगों के संपर्क में आए लोग संक्रमित हुए होंगे।

नई दिल्ली से ये सभी ट्रेनें 13 से 19 मार्च के बीच रवाना हुई थीं। इनमें आंध्र प्रदेश को जाने वाली दुरंतो एक्सप्रेस, चेन्नई तक जाने वाली ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, चेन्नई को ही जाने वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस, नई दिल्ली -रांची राजधानी एक्सप्रेस और आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस शामिल हैं।

अभी रेलवे के पास जमातियों के संपर्क में आए लोगों की वास्तविक संख्या नहीं हैं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि हर ट्रेन में लगभग 1000-1200 यात्री और रेलवे कर्मचारी होते हैं, जिन सभी को खतरा हो सकता है।

राज्य के अधिकारियों ने कहा कि रेलवे जिला अधिकारियों को यात्रियों की सूचियां प्रदान कर रहा है जिनको जमात में शामिल लोगों की सूची से मिलाया जा रहा है, ताकि उनके संपर्क में आए लोगों का पता लगाया जा सके।

पहली से आठवीं तक के छात्र अगली कक्षा में

पेज 1 का बाकी

अगली कक्षा में जाने और विश्वविद्यालय के दाखिले के लिए होती है। बोर्ड की ओर से संबद्ध विद्यालयों को कक्षा एक से आठ तक शिक्षा अधिकार कानून के तहत पास करने के लिए कहा गया है। वहीं, नौवीं और ग्यारहवीं के विद्यार्थियों को कक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर अगली कक्षा में भेजने की सलाह दी गई है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 19 मार्च 2020 के बाद विद्यालयों को बंद कर दिया गया था। सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी के मुताबिक कोरोना संक्रमण की वजह से बोर्ड अभी इस स्थिति में नहीं है कि वह परीक्षाओं की तिथियां बता सके। उन्होंने कहा कि जब भी परीक्षाएं शुरू होंगी विद्यार्थिओं और उनके अभिभावकों को दस दिन पहले सूचित किया जाएगा। त्रिपाठी के मुताबिक उत्तर पूर्वी दिल्ली को छोड़कर पूरे देश में दसवीं की कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी क्योंकि शेष देश में दसवीं की प्रमुख विषयों की परीक्षााएं आयोजित हो चुकी थीं।

उत्तर पूर्वी दिल्ली में भी हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं, बारहवीं की पूरे देश में 12 विषयों की और उत्तर पूर्वी दिल्ली में 11 विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों की वजह से कुछ परीक्षाएं स्थगित की गई थीं। अन्य विषयों की परीक्षाओं के लिए बोर्ड अलग से दिशा निर्देश जारी करेगा। बोर्ड ने विदेश में कोई परीक्षा नहीं कराने का भी फैसला किया है। सीबीएसई 25 देशों में परीक्षाएं आयोजित करता है लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से अधिकतर देशों में पूर्ण बंदी है। ऐसे में परीक्षाएं आयोजित करना मुमकिन नहीं है।

देश में बनी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए बोर्ड ने उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य भी रोका हुआ है। मूल्यांकन के लिए भी जल्द ही बोर्ड दिशानिर्देश जारी करेगा लेकिन यह कब जारी होंगे, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। सचिव के मुताबिक मूल्यांकन कार्य शुरू करने से चार दिन पहले मूल्यांकन से संबंधित सभी लोगों को सूचना दी जाएगी। बोर्ड की ओर से सभी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है और कहा है कि वे सही जानकारी बोर्ड की वेबसाइट से ले सकते हैं।

www.readwhere.com

खबर कोना

इवांका ट्रंप ने मोदी के योगासन वीडियो को बताया शानदार

वाशिंगटन, 1 अप्रैल (भाषा)।

कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान लोगों को फिट रहने के लिए प्रोत्साहित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ट्विटर पर साझा किए गए योगासन वीडियो की इवांका ट्रंप ने सराहना करते हुए उसे शानदार बताया है। इवांका ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी व उनकी वरिष्ठ सलाहकार हैं। मोदी ने 'योग निद्रा' का वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया था, 'जब भी समय मिलता है, मैं हफ्ते में 1-2 बार योग निद्रा का अभ्यास अवश्य करता हूं।'उन्होंने कहा कि इससे शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहता है, साथ ही यह तनाव और चिंता को भी कम करता है। इंटरनेट पर आपको योग निद्रा के कई वीडियो मिलेंगे। अंग्रेजी और हिंदी में 1- 1वीडियो साझा कर रहा हूं। इवांका ने मोदी के वीडियो रिट्वीट करते हुए लिखा, 'यह शानदार है। शुक्रिया नरेंद्र मोदी।'इवांका अपने पिता डोनाल्ड ट्रंप के साथ फरवरी में भारत यात्रा पर भी आई थी। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने ट्वीट किया कि योग मन और शरीर के बीच तालमेल बनाने में मदद करता है। अलग रहने के इस दौर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग के माध्यम से हमें एक साथ रहना और जागरूक रहना सीखा रहे हैं।

सऊदी अरब की मुसलमानों से अपील, इस बार हज स्थगित करें

रियाद, 1 अप्रैल (एएफपी)।

सऊदी अरब के हज मंत्री ने कोरोना वायरस के चलते उत्पन्न अनिश्चितता के कारण मुसलमानों से इस बार हज की तैयारियां स्थगित करने की अपील की है। इस महीने की शुरुआत में सऊदी अरब ने अपने शहरों में कोरोना वायरस के फैलने के डर के चलते "उमरा" तीर्थयात्रा निलंबित कर दी थी। इस अभूतपूर्व कदम के बाद से सालाना हज पर भी अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे थे। सऊदी अरब के हज मंत्री मोहम्मद बिन्तऐन ने सरकार द्वारा संचालित ' अल एखबरिया टेलीविजन' से कहा कि सऊदी अरब हज और उमरा के इच्छुक लोगों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन मौजूदा हालात में इस वैश्विक महामारी के मद्देनजर सऊदी अरब मुसलमानों और अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा को लेकर प्रतिबद्ध हैं। लिहाजा हमने सभी देशों के अपने मुसलिम भाइयों से कहा है कि वे हालात ठीक होने तक हज के लिये इंतजार करें।

किर्गिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री, उपप्रधानमंत्री बर्खास्त

बिश्केक, 1 अप्रैल (एएफपी)।

किर्गिजस्तान सरकार में कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिम्मेदार दो वरिष्ठ सदस्यों को बुधवार को बर्खास्त कर दिया गया। राष्ट्रपति सूरोनबे जीनबेकोव ने बीमारी से निपटने के उनके प्रयासों की निंदा की थी। राष्ट्रपति की आधिकारिक वेबसाइट पर स्वास्थ्य मंत्री कोस्मोस्बेक चोलपोंबेव और उपप्रधानमंत्री अल्तीनाई उमरबेकोवा को बर्खास्त करने की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति ने कोविड-19 के खिलाफ देश की टास्क फोर्स का नेतृत्व करने में मदद करने वाले दोनों नेताओं की निंदा करते हुए उनके काम को असंतोषजनक बताया था। जीनबेकोव ने कहा था कि उन्होंने बीमारी को फैलने दिया। किर्गिजस्तान में कोरोना वायरस के 111 मामले सामने आए हैं, और अब तक किसी की मौत की खबर नहीं है।

अमेरिका में कोरोना के प्रकोप के बीच आया जनगणना दिवस

ओरलैंडो, 1 अप्रैल (एपी)।

अमेरिका में बुधवार को जनगणना दिवस ऐसे समय में आया जब देश कोरोना वायरस के प्रकोप से बुरी तरह प्रभावित हो है। जनगणना में उन लोगों की गिनती की जाती है जो पिछले एक दशक में कभी भी यहां रहे हैं। हालांकि जनगणना अधिकारियों ने संकल्प जताया कि यह काम वर्षांत की समयसीमा तक पूरा कर लिया जाएगा। कोरोना के कारण अमेरिकी जनगणना ब्यूरो को क्षेत्रीय कामकाज मार्च के मध्य से अप्रैल के मध्य तक एक महीने के लिए निलंबित करना पड़ा है। तब पांच लाख अस्थायी जनगणना कर्मियों की नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया तेज की जाएगी। ब्यूरो ने बेघर लोगों और कॉलेज छात्रावासों तथा नर्सिंग होम जैसे स्थानों पर रहने वाले लोगों की गिनती भी टाल दी है और इस काम को जुलाई के आखिर से अगस्त के मध्य तक के लिए बढ़ा दिया है।

ब्रिटेन में भारतीय और विदेशी चिकित्सकों की वीजा अवधि बढ़ी

लंदन, 1 अप्रैल (भाषा)।

भारतीय और अन्य विदेशी डाक्टरों को राहत देते हुए ब्रिटिश सरकार ने कोरोना वायरस के संकट के खिलाफ लड़ाई को देखते हुए उनके वीजा की अवधि को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। इनके वीजा की मियाद इस साल अक्तूबर में खत्म हो रही है। ये चिकित्सक देश की राष्ट्रीय स्वस्थ्य सेवा (एनएचएस) के लिए कार्यरत हैं।

चीन ने किया लक्षण मुक्त कोरोना का खुलासा

संक्रमण का नया दौर शुरू होने को लेकर चिंताएं बढ़ीं

चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने अचानक घोषणा की कि वह ऐसे रोगियों की जानकारी जारी करेगा जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखाई नहीं दिए। चीन ने ऐसे 1,541 रोगियों को सोमवार तक चिकित्सा निगरानी में रख रखा था, इनमें विदेश से आए 205 लोग शामिल थे।

बेजिंग, 1 अप्रैल (भाषा)।

चीन ने बुधवार को पहली बार जानलेवा कोरोना वायरस के 1,541 ऐसे मामलों का खुलासा किया है जिसमें रोगी के भीतर वायरस के लक्षण दिखाई ही नहीं दिए इससे देश में कोरोना वायरस संक्रमण का नया दौर शुरू होने को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग (एनएचसी) ने मंगलवार को अचानक घोषणा की कि वह ऐसे रोगियों की जानकारी जारी करेगा जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखाई नहीं दिए। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिंहुआ ने एनएचसी के हवाले से एक बयान में कहा कि चीन ने ऐसे 1,541 रोगियों को सोमवार तक चिकित्सा निगरानी में रख रखा था, इनमें विदेश से आए 205 लोग शामिल थे।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के प्रमुख चांग जाइल ने कहा चीन बुधवार से ऐसे रोगियों की संख्या और उनकी हालत के बारे में जानकारी प्रकाशित करेगा। एनएचसी के बयान में कहा गया है कोविड-19 से संक्रमित लक्षण-मुक्त रोगियों के कारण संक्रमण और अधिक फैल सकता हैं।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से कोविड-19 सबसे बड़ी चुनौती : गुतारेस

- भीषण वैश्विक संकट है क्योंकि यह एक संयोजन है, एक ओर एक बीमारी है जो पूरी दुनिया में हर किसी के लिए खतरा है और दूसरी ओर इसके आर्थिक प्रभाव हैं जिससे मंदी आएगी और ऐसी मंदी आएगी कि हालिया इतिहास में उसकी कोई मिसाल नहीं देखी गई होगी। इन दो तत्वों का मेल और यह तथ्य कि यह अस्थिरता, अशांति और संघर्षों को जन्म देगा : संयुक्त राष्ट्र महासचिव

संयुक्त राष्ट्र, 1 अप्रैल (भाषा)।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने कोरोना वायरस को द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद सबसे बड़ी चुनौती करार देते हुए कहा कि यह महामारी न केवल लोगों की जान ले रही है बल्कि आर्थिक मंदी की ओर भी ले जा रही है। हालिया इतिहास में ऐसा भयानक संकट नहीं पैदा हुआ।

जान्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुमानों के अनुसार दुनिया में कोरोना वायरस के 8,50,500 पुष्ट मामले सामने आए हैं और 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में अब दुनिया के सर्वाधिक 1,84,183 मामले हैं और यहां मरने वालों का आंकड़ा चार हजार को पार कर गया है।

गुतारेस ने मंगलवार को 'साझी जिम्मेदारी, वैश्विक एकजुटता : सामाजिक आर्थिक प्रतिक्रिया' विषय पर रिपोर्ट साझा करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र के पिछले 75 सालों के इतिहास में ऐसा संकट पहले नहीं देखा गया। हम उसका सामना कर रहे हैं - ऐसा संकट जो लोगों की जान ले रहा है, इंसान को पीड़ा दे रहा है, लोगों की जिंदगी को दुरूह कर रहा है।

गुतारेस ने इस रिपोर्ट को आनलाइन जारी करते हुए कहा कि मौजूदा महामारी स्वास्थ्य संकट से कहीं आगे की चीज है। बाद में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह भीषण वैश्विक संकट है क्योंकि यह एक संयोजन है, एक ओर एक बीमारी है जो पूरी दुनिया में हर किसी के लिए खतरा है और दूसरी ओर इसके आर्थिक प्रभाव हैं जिससे मंदी आएगी और ऐसी मंदी आएगी कि हालिया इतिहास में उसकी कोई मिसाल नहीं देखी गई होगी। इन दो तत्त्वों का मेल और यह तथ्य कि यह अस्थिरता, अशांति और संघर्षों को जन्म देगा। इनसे हमें यह मानने को मजबूर होना पड़ रहा है कि वास्तव में यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद से सबसे बड़ा संकट है। इसके लिए मजबूत और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है और इस प्रकार के कदम एकजुटता के साथ ही संभव हैं। यह तभी होगा जब हम सब एक साथ आएंगे, अपने राजनीतिक खेलों को भुलाकर एक साथ आएंगे और इस समझ के साथ एक साथ आएंगे कि आज मानवता दांव पर है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि इस मानवीय संकट से निपटने के लिए विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की ओर से समन्वित, निर्णायक, समग्र और नवोन्मेषी नीतिगत कार्रवाई की जरूरत है। इसके लिए हमें गरीबों और अधिक संवेदनशील देशों के लोगों के लिए अधिकतम आर्थिक और तकनीकी समर्थन भी जुटाना होगा। उन्होंने इस दिशा में त्वरित समन्वित स्वास्थ्य प्रतिक्रिया की जरूरत बताई ताकि संक्रमण के प्रसार को काबू करने के साथ ही इस महामारी को खत्म किया जा सके।

गुतारेस ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मामलों की जांच क्षमता बढ़ाने, प्रभावितों का पता लगाने, उन्हें अलग-थलग रखने और लोगों की आवाजाही को सीमित किए जाने की तत्काल जरूरत है। उन्होंने इस महामारी से निपटने के लिए नया बहु-साझेदारी वाला 'ट्रस्ट फंड' बनाने की वकालत करते हुए कहा कि जब हम इस संकट से उबर जाएंगे जो कि हम निश्चित ही उबरेंगे, उसके बाद हमारे सामने एक सवाल होगा। या तो हम अपनी दुनिया में लौट जाएं जो पहले के जैसी थी या फिर हम उन मुद्दों से निर्णायक तरीके से निपटें जो हमें संकटों के प्रति अनावश्यक रूप से कमजोर बनाते हैं ।

संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार इस महामारी के कारण 50 लाख से लेकर ढाई करोड़ नौकरियां खत्म हो जाएंगी और अमेरिका को श्रमिक आय के रूप में 960 अरब से लेकर 3.4 खरब डालर का नुकसान होगा। व्यापार और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अंकटाड) ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से वैश्विक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर 30. 40 फीसद का नकारात्मक दबाव पड़ेगा और विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार अंतरराष्ट्रीय आगमन में 20.30 फीसद की गिरावट आ जाएगी।

लक्षण नहीं उभरे थे कोविड-19 के

प्रख्यात विषाणु विज्ञानी गीता रामजी का निधन

जोहानिसबर्ग, 1 अप्रैल (भाषा)।

भारतीय मूल की प्रख्यात विषाणु विज्ञानी गीता रामजी की कोरोना वायरस संक्रमण से मौत हो गई। रामजी मशहूर दवा विज्ञानी थीं और एचआईवी निरोधक शोध की प्रमुख थीं। वह एक सप्ताह पहले लंदन से लौटी थीं लेकिन उनमें कोविड-19के कथित तौर पर कोई लक्षण नहीं थे। उनकी उम्र 64 वर्ष थी।

वह क्लीनिकल ट्रायल्स यूनिट की प्रधान शोधकर्ता व एचआईवी प्रिवेंशन रिसर्च यूनिट ऑफ साउथ अफ्रीकन मेडिकल रिसर्च काउंसिल ऑफिसेज(एसएएमआरसी) की यूनिट डायरेक्टर थीं। एसएएमआरसी के अध्यक्ष व सीईओ ग्लेंडा ग्रे की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बेहद दुख के साथ आपको यह सूचित किया जाता है कि प्रोफेसर गीता रामजी का आज अस्पताल में निधन हो गया। प्रोफेसर रामजी का कोविड-19से जुड़ी जटिलताओं के चलते निधन हो गया।रामजी का विवाह फार्मासिस्ट प्रवीन रामजी से हुआ था। उनके अंतिम संस्कार की अभी घोषणा नहीं की गई है। दक्षिण अफ्रीका में अंतिम संस्कार में शामिल होने की संख्या को सीमित रखा गया है क्योंकि देश में 21 दिन का बंद है। राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने पिछले सप्ताह बंद की घोषणा की थी।

कोरोना महामारी से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र में दो प्रस्ताव पेश

संयुक्त राष्ट्र, 1 अप्रैल (एपी)।

कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने इसकी महासभा में दो प्रतिद्वंद्वी प्रस्ताव पेश किए हैं क्योंकि इस वैश्विक संस्था की बैठकें नहीं हो रही है। बैठकें नहीं होने के चलते बनाए गए मतदान के नए नियमों के मुताबिक यदि किसी एक देश ने भी ऐतराज जताया तो प्रस्ताव पारित नहीं हो सकेगा। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देश हैं।

135 से अधिक देशों द्वारा अनुमोदित एक प्रस्ताव में इस महामारी को रोकने, इसके प्रभाव को कम करने और इसे शिकस्त देने के लिए कहीं अधिक तीव्र अंतरराष्ट्रीय सहयोग की अपील की गई है। इनमें सूचना का आदान-प्रदान, वैज्ञानिक ज्ञान और सर्वश्रेष्ठ गतिविधियां तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा सुझाए गए संबद्ध दिशानिर्देश शामिल हैं।

दूसरा प्रस्ताव मध्य अफ्रीकी गणराज्य, क्यूबा, निकारागुआ और वेनेजुएला के समर्थन से रूस ने पेश किया है। इसमें भी कोरोना वायरस महामारी का मुकाबला करने के लिए डब्लूएचओ की नेतृत्वकारी भूमिका पर जोर दिया गया है लेकिन इसमें व्यापार युद्ध बंद करने और संरक्षणवादी उपायों को लागू करने की अपील की गई है। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी के बगैर एकपक्षीय तरीके से प्रतिबंध नहीं लगाने की अपील भी की गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रमुख टी. मुहम्मद बांदे ने दोनों प्रस्ताव सोमवार को सभी सदस्य देशों को भेज दिए।

ब्रिटेन में कोरोना से 13 वर्षीय बच्चे की मौत

लंदन, 1 अप्रैल (एएफपी)।

ब्रिटेन में कोरोना वायरस से 13 वर्षीय बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। बच्चे के परिवार के अनुसार उसे पहले कोई बीमारी नहीं थी।

बच्चे की मौत लंदन के किंग्स कॉलेज अस्पताल में मंगलवार सुबह हुई। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना वायरस से जान गंवाने वाला वह सबसे छोटा शख्स है। इससे पहले बेल्जियम में मंगलवार को जान गंवाने वाली 12 वर्षीय बच्ची को यूरोप की सबसे कम उम्र की पीड़िता माना जा रहा था। ब्रिटेन के मृतक का नाम इस्माइल मोहम्मद अब्बदुलवहाब था। सांस लेने में तकलीफ के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पारिवारिक मित्र मार्क स्टीफन ने परिवार के हवाले से कहा कि उसे पहले वेंटिलेटर और फिर कोमा (इन्ड्यूज्ड) में रखा गया, लेकिन कल दुर्भाग्यवश उसकी मौत हो गई। किंग्स कॉलेज में लेक्चरर नतालिया मैकडर्मोट ने कहा, 'जैसा कि हमें पता है कि बच्चों को बुजुर्गों की तुलना में कोविड-19 से कम खतरा है लेकिन यह मामला ब्रिटेन और दुनिया भर में संक्रमण के प्रसार को कम करने के लिए हमारे द्वारा बरती जाने वाली सभी सावधानियों के महत्व पर जोर देता है।' उन्होंने आशंकित समूह से परे मौत के ऐसे मामलों में शोध की अपील करते हुए कहा कि इससे किसी भीतरी जेनेटिक संवेदनशीलता का संकेत मिल सकता है।

'स्टार वार्स' के 'मेजर इमेट' का किरदार निभाने वाले एंड्रियू जैक का निधन

लंदन, 1 अप्रैल (भाषा)।

'स्टार वार्स' में मेजर इमेट का किरदार निभाने के लिए विख्यात अभिनेता एंड्रियू जैक का निधन कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से 76 साल की उम्र में हो गया।

उनके एजेंट जिल मैकलॉ ने बताया कि उनका निधन इंग्लैंड के चेर्टसी के अस्पताल में मंगलवार को हुआ। उनकी पत्नी गैब्रियल रोगर ने बताया कि दो दिन पहले ही एंड्रियू कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। उन्हें दर्द नहीं था और शांतिपूर्ण तरीके से उनका निधन हो गया।

डायलेक्ट कोच के रूप में उन्होंने हॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया है। वह 'मेन इन ब्लैकः इंटरनेशल' और 'द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स (ट्रायलॉजी)' में काम कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने 'बैटमेन बिगिन्स' में अभिनेता क्रिश्चियन बेल की आवाज पर भी काम किया था।

कोरोना को लेकर पाक में शिया हजारा समुदाय निशाने पर

वाशिंगटन, 1 अप्रैल (भाषा)।

अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) ने पाकिस्तान में प्रांतीय सरकार द्वारा जानलेवा कोरोना वायरस फैलाने के लिए हाशिये पर पड़े कबायली अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने की रिपोर्टों पर चिंता जताई है।

यूएससीआइआरएफ ने मंगलवार को बयान में कहा कि बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में लॉकडाउन (बंद) के तहत हजारा समुदाय के दो इलाके हजारा टाउन और मारी आबाद को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को हजारा बहुल इलाकों में जाने से रोक दिया है और हजारा पुलिसकर्मियों को इस संदेह में कथित रूप से जबरन छुट्टी पर भेज दिया है कि उन्हें अपने रिश्तेदारों से यह बीमारी लग सकती है। आयोग की आयुक्त अनुरीमा भार्गव ने कहा कि हम इस बात से चिंतित हैं कि बलूचिस्तान में सरकारी अधिकारी पहले से उत्पीड़ित और हाशिये पर पड़े हजारा शिया समुदाय को इस स्वास्थ्य संकट के लिए कुबार्नी का बकरा बना रहे हैं। यह विषाणु, धर्म, जाति या सीमा नहीं पहचानता है और इसका इस्तेमाल किसी एक समुदाय के साथ भेदभाव के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर लोगों ने कोरोना वायरस को 'शिया वायरस' बताया । उन्हें इस बात की आशंका है कि ईरान से लौट रहे जायरीन के जरिए यह फैला है। आयोग के आयुक्त जॉनी मूर ने कहा कि हम पाकिस्तान के हजारा शिया समुदाय को लेकर काफी फिक्रमंद हैं।

दुनियाभर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 43 हजार से ज्यादा

पेरिस, 1 अप्रैल (एएफपी)।

दुनिया भर में कोरोना संक्रमण से भारतीय समयानुसार बुधवार शाम साढ़े चार बजे तक 43,082 लोगों के मरने की आधिकारिक रूप से पुष्टि हुई है। एएफपी ने आधिकारिक सूत्रों से यह आंकड़े जुटाए हैं। चीन में दिसंबर में आए पहले मामले के बाद से अभी तक 186 देशों और क्षेत्रों में 8,65,970 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इनमें से कम से कम 1,72,500 लोगों के संक्रमण मुक्त होने की सूचना है।

एएफपी के कार्यालयों ने राष्ट्रीय प्राधिकारों और विश्व स्वास्थ्य संगठन से आंकड़े एकत्र किए हैं, लेकिन संभवतः यह संक्रमित लोगों की वास्तविक संख्या का एक हिस्सा भर ही है। कई देशों में सिर्फ उन मामलों की जांच की जा रही है जिनमें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है। इटली में कोरोना विषाणु संक्रमण से मौत का पहला मामला फरवरी के अंत में आया था, लेकिन अब वहां संक्रमण से मरने वालों की संख्या 12,428 हो गई है। देश में 1,05,792 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और अभी तक 15,729 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं।

स्पेन में 9,053 लोगों की मौत इस विषाणु संक्रमण से हुई है, जबकि 1,02,136 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। हांगकांग और मकाउ से इतर चीन में अभी तक 3,312 लोगों के मरने और 81,554 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। वहां 76,238 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। मंगलवार से अभी तक देश में संक्रमण के 36 नए मामले आए हैं और सात लोगों की मौत हुई है। फ्रांस में अभी तक 3,523 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है जबकि 52,128 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। अमेरिका में सबसे ज्यादा 1,89,633 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। देश में वायरस संक्रमण से अभी तक 4,081 लोगों की मौत हुई है जबकि 7,138 लोगों के संक्रमण से उबरने की सूचना है।

यूरोप संक्रमित लोगों के लिए बिस्तरों की कमी का कर रहा सामना

रोम, 1 अप्रैल (एपी)।

कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए अस्पतालों में आइसीयू बेड की अत्यधिक कमी का सामना कर रहे यूरोपीय देश तेजी से अस्थायी अस्पताल बना रहे हैं और हाई-स्पीड ट्रेनों तथा सैन्य विमानों से इन मरीजों को प्रभावित शहरों से बाहर ले जा रहे हैं। हालांकि, बड़ा सवाल यह है कि क्या वे इन अस्थायी अस्पतालों को संचालित करने के लिए पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्य सेवा कर्मी पा सकेंगे। इटली और चीन में वायरस के फैलने की दर धीमी पड़ने के बावजूद स्पेन और फ्रांस में अस्पताल अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच गए हैं और अमेरिका व ब्रिटेन खुद को इस स्थिति के लिये तैयार कर रहे हैं। पेरिस आपात सेवा कर्मी क्रिस्टोफ प्रुधोम ने कहा कि ऐसा लगता है कि हम तीसरी दुनिया में हैं।

शेरपाओं और गाइडों के लिए पर्वतारोहण ही एकमात्र आजीविका | **रोजी का संकट** | अप्रैल के शुरू से मई के अंत तक चलता है सीजन

माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोहण बंद, शेरपाओं को आजीविका की चिंता

- इस शहर में कोरोना वायरस के संक्रमण का कोई मामला नहीं है, लेकिन सीमाओं के वैश्विक लॉकडाउन और हवाई यात्रा पर प्रतिबंध के चलते माउंट एवरेस्ट पर्वतारोहण भी बंद हो गया है। खुमजुंग के शेरपा एवरेस्ट फतह में पर्वतारोहियों की मदद करते है
- कोरोना वायरस के चलते आधार शिविर सूना पड़ा है। नामचे बाजार भी सूना पड़ा है जो पर्वतरोहण अभियान बिंदु से पहले पड़नेवाला अंतिम नगर है। पोर्टर, कुक और अन्य लोग भी आजीविका पर मंडराते खतरे से चिंतित हैं। शेरपा पेम्बा गालजेन ने कहा कि सीजन रद्द हो जाने से किसी के पास काम नहीं बचा है।

खुमजुंग, 1 अप्रैल (एएफपी)।

विश्व में कोरोना वायरस के कहर के चलते सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट का पर्वतारोहण भी बंद करना पड़ा है और इससे जाने-माने स्थानीय शेरपाओं की आजीविका पर खतरा मंडराने लगा है। पर्वतारोहण के सीजन में पर्वतीय नगर खुमजुंग गुलजार रहता था लेकिन अब यह खाली पड़ा है।

इस शहर में कोरोना वायरस के संक्रमण का कोई मामला नहीं है, लेकिन सीमाओं के वैश्विक लॉकडाउन और हवाई यात्रा पर प्रतिबंध के चलते माउंट एवरेस्ट पर्वतारोहण भी बंद हो गया है। खुमजुंग के शेरपा एवरेस्ट फतह में पर्वतारोहियों की मदद करते हैं। फुरबा न्यामगाल शेरपा 17 साल की उम्र से ही एवरेस्ट और अन्य पर्वत चोटियों पर चढ़ाई में पर्वतारोहियों की मदद करते रहे हैं, लेकिन अब वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं।

उनकी ही तरह सैकड़ों गाइडों और पर्वतारोहण के साहसिक कार्य से जुड़े लोगों को भविष्य की चिंता सता रही है। खुमजुंग के घरों में रस्सियां और पर्वतारोहण में काम आने वाली अन्य चीजें अब भी टंगी हैं। ट्रेकरों और पर्वतारोहियों से गुलजार रहने वाले हॉस्टल और चाय की दुकानें अब खाली पड़ी हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंची है।

नेपाल ने 12 मार्च को सभी पर्वतीय अभियानों के परमिट निलंबित कर दिए थे और तत्काल प्रभाव से अपनी पर्वत चोटियों के आरोहण को बंद कर दिया था। शेरपाओं और गाइडों का कहना है कि पर्वतारोहियों का मार्गदर्शन करना ही उनकी एकमात्र आजीविका है। अप्रैल के शुरू से मई के अंत तक चलने वाले एवरेस्ट सीजन में की गई कमाई से उनके परिवारों का सालभर का खर्च चल जाता था।

कोरोना वायरस के चलते आधार शिविर सूना पड़ा है। नामचे बाजार भी सूना पड़ा है जो पर्वतरोहण अभियान बिंदु से पहले पड़नेवाला अंतिम नगर है। पोर्टर, कुक और अन्य लोग भी आजीविका पर मंडराते खतरे से चिंतित हैं। शेरपा पेम्बा गालजेन ने कहा कि सीजन रद्द हो जाने से किसी के पास काम नहीं बचा है। उड़ानों से लेकर दुकानों और पोर्टरों तक कोई काम नहीं है। हर कोई अपने घर लौट रहा है। एवरेस्ट अभियान से जुड़ी टीमों का मार्गदर्शन करने वाले गाइड डामियान बेनेगस ने कहा कि पोर्टरों और रसोई के काम से जुड़े लोगों पर सबसे बुरा असर पड़ेगा क्योंकि उनके पास कोई बचत नहीं है।

इस स्थिति के चलते नेपाल के पर्यटन उद्योग पर भी बुरा असर पड़ा है जिसका देश के सकल घरेलू उत्पादन में लगभग आठ प्रतिशत का योगदान है। हालांकि, एवरेस्ट क्षेत्र के निवासी सरकार के फैसले से सहमत हैं। उनका मानना है कि कोरोना वायरस के संक्रमण का जोखिम वास्तविक है। रोजगार संकट का सामना कर रहे लोगों के लिए सरकार की ओर से अभी किसी आर्थिक राहत की घोषणा नहीं की गई है। नेपाल माउंटेनियरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष संता बीर लाम्बा ने कहा कि सरकार को पर्वतारोहण क्षेत्र ही नहीं, बल्कि अन्य क्षेत्रों के प्रभावित लोगों की भी मदद करनी चाहिए।

www.readwhere.com

मथुरा में बुधवार को सरकारी राशन की दुकान से खाद्यान्न लेते समय व्यक्तिगत दूरी का पूरा ध्यान रखते ग्राहक।

वित्त वर्ष के पहले दिन शेयर बाजारों में गिरावट, सूचकांक 1,203 अंक लुढ़का

मुंबई, 1 अप्रैल (भाषा)।

शेयर बाजारों में नए वित्त वर्ष की शुरुआत अच्छी नहीं रही। बंबई शेयर बाजार का सूचकांक बुधवार को 1,203 अंक लुढ़क गया। कोरोना महामारी के कारण वैश्विक स्तर पर कमजोर धारणा का असर घरेलू बाजारों पर भी पड़ा। इससे नए वित्त वर्ष के पहले ही दिन निवेशकों को 3,20,633.05 करोड़ रुपए की चपत लगी।

तीस शेयरों वाला सूचकांक मंगलवार को 1,203.18 अंक यानी 4.08 फीसद टूटकर 28,265.31 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 343.95 अंक यानी 4 फीसद का गोता लगा कर 8,253.80 अंक पर बंद हुआ। एशिया के कुछ देशों से औद्योगिक उत्पादन के कमजोर आंकड़े और कोरोना वायरस मामलों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए वैश्विक बाजारों में गिरावट आई। संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या यह संकेत देती है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए आगे का रास्ता कठिन है। वाहनों की बिक्री के कमजोर आंकड़े और भारत के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल करने से चूकने की खबर से निवेशकों का भरोसा हिला है।

सूचकांक के शेयरों में सर्वाधिक नुकसान में टेक महिंद्रा रही। कंपनी का शेयर 9.21 फीसद तक लुढ़क गया। उसके बाद क्रम से कोटक बैंक (8.81 फीसद), टीसीएस (6.23 फीसद), इन्फोसिस (5.65 फीसद), एक्सिस बैंक (5.50 फीसद) और एसबीआइ (5.26 फीसद) का स्थान रहा। दूसरी तरफ मात्र हीरो मोटो कार्प, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस और टाइटन के शेयर 2.21 फीसद तक लाभ में रहे।

कारोबारियों के अनुसार घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट वैश्विक बाजारों के अनुरूप रही। कोरोना महामारी से राहत मिलने की संभावना नहीं दिखने के साथ बाजार में गिरावट आई। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आवागमन पर रोक का असर कारोबार पर दिख रहा है।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि वित्त वर्ष के पहले दिन की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। घरेलू बाजारों पर वैश्विक बाजारों का असर पड़ा। बैंकों की फंसी संपत्ति और वाहनों की बिक्री की संख्या से भी बाजार पर असर पड़ा। एफआइआइ ने मार्च में 62,000 करोड़ रुपए की इक्विी बेची और संक्रमण बढ़ने के साथ बाजार स्थिति और बदतर होने की आशंका कर रहा है।

दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों से औद्योगिक उत्पादन के कमजोर आंकड़े से एशियाई बाजारों में गिरावट का रुख रहा। वैश्विक स्तर पर चीन में शंघाई, हांगकांग, जापान में टोक्यो और दक्षिण कोरिया के सोल में 4 फीसद तक की गिरावट दर्ज की गई। यूरोप के प्रमुख बाजारों में भी शुरुआती कारोबार में गिरावट का रुख रहा। इसी बीच, वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 5.20 फीसद लुढ़ककर 24.98 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

फिच सोल्यूशंस का आकलन

भारत का राजकोषीय घाटा 2020-21 में जीडीपी के 6.2 फीसद तक जाने की आशंका

नई दिल्ली, 1 अप्रैल (भाषा)।

साख निर्धारण और अन्य सेवाएं देने वाली अमेरिकी कंपनी फिच सोल्यूशंस ने कहा है कि भारत का राजकोषीय घाटा 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 6.2 फीसद तक जा सकता है। जबकि सरकार ने इसके 3.5 फीसद रहने का अनुमान जताया है। इसका कारण कोरोना महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए दिया गया आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज है।

फिच ने कहा कि कोरोना महामारी रोकने के लिए जारी बंद और उसके व्यापक प्रभाव के कारण राजस्व संग्रह पर दबाव पड़ेगा। सरकार को अपने खर्च के वित्त पोषण को लेकर मजबूरन अतिरिक्त कर्ज या केंद्रीय बैंक से अधिक लाभांश लेना पड़ सकता है। एजंसी ने कहा कि हम भारत के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान 2020-21 में संशोधित कर जीडीपी का 6.2 फीसद कर रहे हैं जबकि पूर्व में हमने इसके 3.8 फीसद रहने का अनुमान जताया था। यह बताता है कि सरकार अपने 3.5 फीसद लक्ष्य से चूकेगी।

फिच सोल्यूशंस के अनुसार संशोधित अनुमान के पीछे कोरोना संक्रमण के कारण आर्थिक गतिविधियों में नरमी के परिणास्वरूप राजस्व संग्रह कम रहने और आर्थिक झटकों से निपटने के लिए अधिक व्यय की आशंका है। रिपोर्ट के अनुसार कमजोर आर्थिक गतिविधियों से 2020-21 में राजस्व संग्रह में एक फीसद की गिरावट आ सकती है जबकि पूर्व में इसमें 11.8 फीसद की वृद्धि हुई थी। उसने कहा कि 2020-21 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 4.6 रहने का अनुमान है जबकि पूर्व में इसके 5.4 फीसद रहने की संभावना जताई गई थी। हमने 2019-20 में 4.9 फीसद आर्थिक वृद्धि अनुमान के जरिए जो नरमी की बात कही थी, वह सही लग रही है। इसका कारण घरेलू आवाजाही बाधित होने से आर्थिक गतिविधियां ठप होना और कमजोर वैश्विक मांग है।

एजंसी के अनुसार कोरोना महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियां कई तिमाही तक प्रभावित होने की आशंका है। इससे व्यक्तिगत और कंपनी आयकर संग्रह पर पूरे साल के दौरान असर दिखेगा। दूसरी तरफ 2020-21 में व्यय बढ़ेगा क्योंकि सरकार कोरोना संकट को देखते हुए आर्थिक और सामाजिक दोनों मोर्चों पर कदम उठा रही है। फिच के अनुसार- हमारा अनुमान है कि कम राजस्व संग्रह के बावजूद व्यय 22.2 फीसद बढ़ेगा। कोरोना महामारी के कारण मानवीय संकट को देखते हुए सरकार के पास 2020-21 के बजट में निर्धारित योजना के विपरीत अपना व्यय बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सरकार ने 26 मार्च को 1.7 लाख करोड़ रुपए (जीडीपी का 0.8 फीसद) का प्रोत्साहन पैकेज जारी किया। इस पैकेज में गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना, चिकित्सा कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना आदि शामिल हैं।

निजी बैंकों ने ग्राहकों पर छोड़ा मासिक किस्त का फैसला

मुंबई, 1 अप्रैल (भाषा)।

कोरोना महामारी के कारण पड़ने वाले आर्थिक असर को कम करने के लिए ऋण स्थगन के प्रस्ताव पर ज्यादातर निजी बैंकों ने इस विकल्प को चुनने का फैसला ग्राहकों पर ही छोड़ा दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च-मई 2020 के दौरान तीन महीने के लिए ऋण अदायगी की मासिक किस्तों (ईएमआइ) को टालने की बात कही थी, हालांकि इस पर अंतिम फैसला बैंकों पर छोड़ा था।

निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक ने कहा कि वह ग्राहकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे अतिरिक्त ब्याज शुल्क और ऋण अवधि में बढ़ोतरी से बचने के लिए अपने खाते में पर्याप्त धनराशि रखें। एचडीएफसी बैंक ने अपनी वेबसाइट पर कहा- अगर आप ईएमआइ को स्थगित करना नहीं चाहते हैं, तो आपको अपनी ओर से किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। हम आपके अदायगी निर्देशों को जारी रखेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक ने ग्राहकों से कहा है कि अगर वह ऋण स्थगन करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें ईमेल से सूचना देनी होगी।

निजी क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े बैंक आइसीआइसीआइ बैंक ने वेतनभोगी वर्ग के ऋण स्थगन चुनने का विकल्प दिया है, जबकि कारोबारियों का ऋण स्थगन अपने आप हो जाएगा। एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर कहा गया है कि वह इस संबंध में एक योजना को लागू करने की दिशा में काम कर रहा है और इस बारे में ग्राहकों को जल्द जानकारी दी जाएगी।

उधर, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कहा है कि अगर कोई ग्राहक बैंक को यह सूचना नहीं देता है कि वह ईएमआइ देने के लिए तैयार है, तो सभी तरह के ऋण के लिए उनकी ईएमआइ तीन महीने तक स्थगित हो जाएगी। विशेषज्ञों ने पहले ही साफ कर दिया है कि यह ब्याज माफी नहीं है, बल्कि भुगतानों को टाला जा रहा है, जिसका अर्थ है कि ग्राहकों को अतिरिक्त ब्याज लागत ऋण अदायगी करनी होगी।

कोरोना से लड़ने के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन 1,125 करोड़ देंगे

बंगलुरु, 1 अप्रैल (भाषा)।

विप्रो लिमिटेड, विप्रो एंटरप्राइजेज लिमिटेड और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने कोरोना विषाणु से पैदा हुए अभूतपूर्व स्वास्थ्य और मानवीय संकट से मुकाबला करने के लिए 1,125 करोड़ रुपए देने की बुधवार को प्रतिबद्धता जताई।

विप्रो और फाउंडेशन ने एक संयुक्त बयान में कहा कि ये संसाधन महामारी के खिलाफ लड़ाई की सीमा में समर्पित चिकित्सा और सेवा बिरादरी को सक्षम बनाने और इस महामारी के व्यापक मानव प्रभाव को कम करने में मदद करेंगे। विप्रो लिमिटेड कंपनी सौ करोड़ रुपए देगी जबकि विप्रो एंटरप्राइजेज लिमिटेड 25 करोड़ रुपए और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन 1,000 करोड़ रुपए देंगे। यह रकम विप्रो की वार्षिक सीएसआर गतिविधियों और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सामान्य जनकल्याणकारी खर्चों के अलावा है। बयान में कहा गया है कि इन पहलों को संबंधित सरकारी संस्थानों के साथ सावधानीपूर्वक समन्वित किया जाएगा।

यूनाइटेड बैंक, ओरिएंटल बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय

नई दिल्ली, 1 अप्रैल (भाषा)।

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने बुधवार को कहा कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआइ) और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) की सभी शाखाओं ने उसकी शाखाओं के रूप में काम करना शुरू कर दिया है।

यूबीआइ और ओबीसी का पीएनबी में विलय एक अप्रैल से प्रभावी हो गया है। विलय के बाद जो बैंक सामने आया है, यह शाखाओं और कारोबार, दोनों लिहाज से भारतीय स्टेट बैंक के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। पीएनबी ने एक बयान में कहा कि इस विलय से वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और अगली पीढ़ी के बैंक का रास्ता प्रशस्त हुआ है। अब जमाकर्ताओं समेत सभी ग्राहकों को पीएनबी का ग्राहक माना जाएगा। बयान में बताया गया कि अब पीएनबी की देश भर में 11 हजार से अधिक शाखाएं, 13 हजार से अधिक एटीएम, एक लाख कर्मचारी और 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार होगा।

पीएनबी के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसएस मल्लिकार्जुन राव ने कहा कि भौगोलिक रूप से उपस्थिति में विस्तार से हमें अधिक दक्ष और प्रभावी तरीके से ग्राहकों की सेवा करने में मदद मिलेगी। बैंक ने विलय के बाद ग्राहकों की मदद के लिए सभी शाखाओं और कार्यालयों में बैंक साथी की नियुक्ति की है। बैंक ने अपना नया लोगो भी पेश किया है।

मार्च में जीएसटी संग्रह घट कर 97,597 करोड़ रहा

नई दिल्ली, 1 अप्रैल (भाषा)।

माल व सेवा कर (जीएसटी) संग्रह मार्च नहीने में घटकर 97,597 करोड़ रुपए रह गया। फरवरी में जीएसटी संग्रह 1.05 लाख करोड़ रुपए रहा था।

वित्त मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि कुल 97,597 करोड़ रुपए के जीएसटी संग्रह में से केंद्रीय जीएसटी संग्रह का हिस्सा 19,183 करोड़ रुपए रहा। इसी तरह राज्य जीएसटी संग्रह का हिस्सा 25,601 करोड़ रुपए रहा। एकीकृत जीएसटी संग्रह 44,508 करोड़ रुपए रहा। इसमें से 18,056 करोड़ रुपए आयात पर जुटाए गए। बयान के अनुसार 31 मार्च, 2020 तक कुल 76.5 लाख जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल किए गए।

मारुति सुजुकी की मार्च में बिक्री 47 फीसद गिरी

नई दिल्ली, 1 अप्रैल (भाषा)।

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने बुधवार को कहा कि मार्च 2020 में उसकी बिक्री 47 फीसद घटकर 83,792 इकाई रह गई।

मारुति सुजुकी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कंपनी ने पिछले साल मार्च में 1,58,076 इकाइयां बेची थीं। बयान में बताया गया कि उसकी घरेलू बिक्री मार्च 2019 की 1,47,613 इकाइयों की तुलना में 46.4 फीसद घटकर मार्च 2020 में 79,080 इकाई रह गई। इस दौरान कंपनी की ऑल्टो और वैगनआर जैसी छोटी कारों की बिक्री 15,988 इकाई रही, जो पिछले साल इसी महीने में 16,826 इकाई थी। इसी तरह कंपनी की छोटी कारों की बिक्री में पांच फीसद की कमी आई। स्विफ्ट, सेलेरियो, इग्निस, बलेनो और डिजायर जैसे मॉडल वाले कॉम्पैक्ट खंड में बिक्री 50.9 फीसद घटकर 40,519 इकाई रही। इसी तरह विटारा ब्रेजा, एस-क्रॉस और एर्टिगा सहित यूटिलिटी वाहनों की बिक्री 53.4 फीसद घटकर 11,904 इकाई रही। कंपनी ने कहा कि इस दौरान निर्यात में 55 फीसद की कमी आई थी। आर्थिक सुस्ती और कोरोना वायरस से मारुति सुजुकी की कुल बिक्री 2019-20 में 16 फीसद गिरी।

अशोक लीलैंड की बिक्री 90 फीसद घटी : अशोक लीलैंड ने बुधवार को बताया कि मार्च 2020 में उसके वाहनों की बिक्री में 90 फीसद की गिरावट हुई है। अशोक लीलैंड ने कहा कि घरेलू बाजार में कंपनी की मार्च में कुल बिक्री 1,787 इकाई रही, जो एक साल पहले इसी महीने में 20,521 इकाई थी। इस तरह कंपनी की बिक्री में 91 फीसद की गिरावट दर्ज की गई। कंपनी ने बताया कि घरेलू बाजार में मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री पिछले महीने की 15,235 इकाइयों के मुकालबे 90 फीसद घटकर 1,498 इकाई रह गई है। इस दौरान हल्के वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में 95 फीसद की कमी आई।

हुंडई की बिक्री 47 फीसद गिरी : हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड मार्च में बिक्री 47.21 फीसद गिरकर 32,279 वाहन रह गई। कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसने पिछले साल मार्च में 61,150 वाहनों की बिक्री की थी। आलोच्य माह के दौरान कंपनी की घरेलू बिक्री पिछले साल के 44,350 वाहनों की तुलना में 40.69 फीसद गिरकर 26,300 वाहन रह गई। इस दौरान कंपनी का निर्यात भी 16,800 वाहनों से 64.41 कम होकर 5,979 वाहनों पर आ गया।

रिजर्व बैंक ने आर्थिक नुकसान से निपटने के लिए नए उपायों का एलान किया

नई दिल्ली, 1 अप्रैल (भाषा)।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने बुधवार को कोरोना महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए कुछ नए उपायों की घोषणा की। निर्यात आय की प्राप्ति और उसे स्वदेश भेजने के लिए निर्यातकों को और समय दिया गया है। रिजर्व बैंक ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी आय और व्यय में फौरी तौर पर आने वाले अंतर की भरपाई के लिए दी जाने वाली अग्रिम राशि की सीमा भी 30 फीसद बढ़ा दी है।

> रिजर्व बैंक ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी आय और व्यय में फौरी तौर पर आने वाले अंतर की भरपाई के लिए दी जाने वाली अग्रिम राशि की सीमा 30 फीसद बढ़ा दी है।

कोरोना महामारी का मुकाबला करने के लिए नए उपायों की घोषणा करते हुए आरबीआइ ने कहा कि बैंकों और निवेश फर्मों के लिए पूंजी जरूरत सुनिश्चित करने वाले काउंटर-साइक्लिकल कैपिटल बफर (सीसीवाइबी) को फिलहाल लागू करना जरूरी नहीं है। आरबीआइ ने एक बयान में कहा कि वर्तमान में निर्यातकों द्वारा वस्तुओं और सॉफ्टवेयर निर्यात की पूरी राशि को निर्यात की तारीख से नौ महीने के भीतर देश में लाना होता है। शीर्ष बैंक ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण आई दिक्कतों से 31 जुलाई, 2020 तक किए गए निर्यात से होने वाली आय को देश में लाने की अवधि निर्यात की तारीख से 15 महीने कर दी गई है।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि इस फैसले से निर्यातक कोविड-19 से प्रभावित देशों से विस्तारित अवधि के भीतर भुगतान पा सकेंगे और भविष्य के निर्यात सौदों पर बातचीत के लिए उनके पास अधिक लचीलापन होगा। उसने कहा कि सरकार को उसकी प्राप्तियों और भुगतान में आने वाले अंतर की भरपाई के लिए अस्थाई रूप से अग्रिम नकदी दी गई है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए उसने सभी राज्यों और केंद/शासित प्रदेशों की खर्चों को चलाने के लिए दी जाने वाली सीमा को भी करीब 30 फीसद बढ़ा दिया है।

आरबीआइ ने राज्य सरकारों के लिए उनके सामान्य खर्चों की सीमा की समीक्षा के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया था। समिति की सिफारिशें अभी मिलनी बाकी हैं लेकिन उसकी अंतिम रिपोर्ट आने तक सीमा में फिलहाल यह वृद्धि करने का फैसला किया गया है। संशोधित सीमा 1 अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक मान्य होगी। आरबीआइ ने केंद्र सरकार के खर्चों के लिए जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान यह सीमा 70,000 करोड़ रुपए निर्धारित की है, जो पिछली तिमाही में 60,000 करोड़ रुपए थी।

राज्य बीएस-4 वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराएं : केंद्र

नई दिल्ली, 1 अप्रैल (भाषा)।

केंद्र सरकार ने राज्यों से भारत चरण-4 (बीएस-4) वाहनों की बिक्री और पंजीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने पिछले सप्ताह देशव्यापी बंद खत्म होने के बाद दस दिन तक बीएस-4 वाहनों की बिक्री की अनुमति दी है। हालांकि दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इन वाहनों की बिक्री नहीं की जा सकेगी।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 वाहनों की बिक्री की समय सीमा 31 मार्च, 2020 तय की थी। फेडरेशन आफ आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) ने कोरोना फैलने और अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बीच सुप्रीम कोर्ट से इस समय सीमा को बढ़ाने की अपील की थी, जिस पर शीर्ष अदालत ने यह फैसला दिया।

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा है कि संबंधित राज्य-संघ शासित प्रदेशों के परिवहन विभाग को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता के पीठ ने शुक्रवार को इस मामले पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की थी।

बिना सबसिडी रसोई गैस सिलेंडर 61.5 रुपए सस्ता हुआ

नई दिल्ली, 1 अप्रैल (भाषा)।

बिना सबसिडी के बाजार मूल्य आधारित रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 61.5 रुपए की कटौती की गई है। अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के अनुरूप देश में भी एलपीजी सिलेंडर सस्ते किए गए हैं।

दिल्ली में अब बिना सबसिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर का दाम 744 रुपए प्रति सिलेंडर पर आ गया है। उपभोक्ताओं को सालाना 14.2 किलोग्राम के 12 सिलेंडर सबसिडी वाली कीमत पर मिलते हैं। उसके बाद जरूरत होने पर उपभोक्ता बाजार कीमत पर सिलेंडर खरीदते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की अधिसूचना के अनुसार मार्च से यह बाजार मूल्य आधारित सिलेंडर कीमत में दूसरी कटौती है। इससे पहले एक मार्च को सिलेंडर के दाम 53 रुपए घटाए गए थे। वहीं फरवरी में बिना सबसिडी वाले सिलेंडर के दाम में 144.5 रुपए की भारी वृद्धि की गई थी। इन दो कटौतियों के बाद भी सिलेंडर का दाम फरवरी के स्तर से ऊंचा है।

देश में रसोई गैस सिलेंडर बाजार मूल्य पर बेचा जाता है। सबसिडी के पात्र ग्राहकों के बैंक खातों में सबसिडी का पैसा भेजा जाता है। अधिसूचना के अनुसार व्यावसायिक इस्तेमाल वाले रसोई गैस सिलेंडर का दाम भी घटकर 1,381.50 से 1,285 रुपए पर आ गया है।

सिर्फ पांच फीसद ट्रक ही सड़कों पर, ढुलाई हो रही प्रभावित

नई दिल्ली, 1 अप्रैल (भाषा)।

ड्राइवरों और श्रमिकों की वजह से देशभर में माल ढुलाई का प्रमुख परिवहन साधन यानी ट्रक सड़कों से लगभग गायब हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से देश में इस समय बंद लागू है। इसकी वजह से ट्रक आपरेटरों को चालकों और माल चढ़ाने-उतारने के लिए श्रमिकों की कमी से जूझना पड़ रहा है।

आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआइएमटीसी) ने बुधवार को कहा कि देशभर में कुल ट्रकों की संख्या 90 लाख है। इनमें से सिर्फ पांच फीसद ट्रक सड़कों पर हैं। इससे माल की ढुलाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। एआइएमटीसी ने कहा कि गृह मंत्रालय ने रविवार को अधिसूचना जारी कर बंद के दौरान गैरजरूरी वस्तुओं की आवाजाही की अनुमति दे दी है, इसके बावजूद स्थिति नहीं सुधरी है। इसकी वजह से बहुत से ट्रक चालक अपने घरों को वापस लौट गए हैं या ऐसे स्थानों पर रुके हैं, जहां उन्हें खाने और ठहरने की सुविधा मिल रही है।

एआइएमटीसी की कोर समिति के चेयरमैन व पूर्व अध्यक्ष बाल मलकित सिंह ने कहा कि देशभर में 90 लाख वाणिज्यिक वाहन हैं। 3,500 राज्य, जिला, तालुका स्तर के निकाय एआइएमटीसी से संबद्ध हैं। सिर्फ पांच फीसद वाणिज्यिक वाहन ही परिचालन कर रहे हैं। इनके जरिए मुख्य रूप से एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति हो रही है। इसके अलावा छोटी दूरी के लिए दूध के टैंकर भी चल रहे हैं। सिंह ने बताया कि अभी बाजार में जो फल, सब्जियां आ रही हैं वे किसान खुद अपने माध्यमों से ला रहे हैं।

उन्होंने कहा कि 24 मार्च की बंदी की घोषणा से पहले ही आंशिक बंदी लागू थी। कई राज्यों ने अपनी सीमाओं को सील किया हुआ था। इस वजह से लाखों ट्रक फंसे हुए हैं। जिस समय बंदी की घोषणा की गई, उसके बाद बड़ी संख्या में ट्रक चालक अपने घरों को लौट गए। राजमार्गों पर ढाबे आदि भी बंद हैं जिसकी वजह से बड़ी संख्या में ट्रक चालक सुरक्षित स्थानों, मसलन जहां उन्हें भोजन और रहने की सुविधा उपलब्ध है, वहां चले गए हैं। सिंह ने कहा कि सामान चढ़ाने-उतारने के लिए मजदूर भी नहीं मिल रहे हैं। इस वजह से ट्रकों का परिचालन प्रभावित हुआ है।

यूनिसिस सॉफ्टवेयर पर धोखाधड़ी मामले में 55 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल (भाषा)।

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने यूनिसिस सॉफ्टवेयर एंड होल्डिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों के कारोबार में धोखाधड़ी में भागीदारी को लेकर 11 निकायों पर 55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

बाजार नियामक सेबी ने यह जुर्माना दीपा सौरभ शाह, सुनील जैन, राहुल गुप्ता, डीसेंट विनकॉम, एंथनी गयेन, दिलीप कुमार मंडल, बद्री प्रसाद एंड संस, प्रेमसागर विनिमय, नित्यधारा प्लाजा, कंकर बार्टर और नवदुर्गा इंवेस्टमेंट कंसल्टेंट्स पर लगाया है।

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालय: कार्यपालक अभियंता (उत्तर-पूर्व)-I

2142, जनता फ्लैट्स जी.टी.बी. एन्क्लेव, दिल्ली-110093

प्रेस एनआईटी सं. 123 (2019-20)

क्रम सं.	कार्य का विवरण	निविदा राशि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	ईई(एनई)-I के अंतर्गत एसी-64 में ट्रेन्चलेस एचडीडी पद्धति द्वारा तिकोना पार्क से बलवीर नगर रोड तक 450 एमएम डाया ओडी एचडीपीई पाइप सीवर लाइन का पी/एल (पुनर्आमंत्रित)	रु. 4596298.00	31.3.2020 2020_DJB_190128_1	15.4.2020 2.10 अप.

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.com पर देखें।

पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी

विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019-20/946

हस्ता./-

कार्यपालक अभियंता (उत्तर-पूर्व)-I

www.readwhere.com

निजामुद्दीन जमात में शामिल लोगों की पहचान में जुटे दक्षिण भारतीय राज्य

चेन्नई, 1 अप्रैल (भाषा)।

दिल्ली में निजामुद्दीन स्थित मरकज के तबलीगी जमात में शामिल हुए लोगों में से कई में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होने के बाद दक्षिण भारत के विभिन्न राज्य इस धार्मिक आयोजन में शिरकत करने वालों की पहचान कर उन्हें पृथक रखने के प्रयास में जुट गए हैं। अभी तक तमिलनाडु और तेलंगाना में ऐसे 2,000 लोगों की पहचान हुई है जो इसमें शामिल हुए थे।

तेलंगाना में छह लोगों की वायरस संक्रमण से मौत हुई है और वे सभी मार्च में निजामुद्दीन मरकज में धार्मिक आयोजन में शामिल हुए थे। वहीं तमिलनाडु में मंगलवार को संक्रमण के 57 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अभी तक 124 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। तमिलनाडु में मंगलवार को आए 57 मामलों में से 50 लोगों ने दिल्ली के आयोजन में हिस्सा लिया था।

अन्य राज्य भी दिल्ली के उस धार्मिक आयोजन से लौटे लोगों का पता लगाने में जुटे हुए हैं। तमिलनाडु ने आयोजन से लौटे सभी लोगों से अनुरोध किया है कि वे स्वयं आगे आएं और संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। दक्षिणी दिल्ली के निजामुद्दीन (पश्चिम) इलाके में स्थित मरकज कोरोना संक्रमण का हॉट स्पॉट बन चुका है और यहां एक से 15 मार्च तक हुए तबलीगी जमात के आयोजन में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया था और देश के अलग-अलग कोनों में अपने-अपने घर लौटे हैं।

दिल्ली में ही आयोजन में शामिल होने वालों में से 24 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है और 441 अन्य में लक्षण दिखने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इसका तेलंगाना और तमिलनाडु पर भी बेहद बुरा प्रभाव हुआ है और तेलंगाना में सोमवार को एक दिन में छह लोगों की कोविड-19 से मौत हुई है। तेलंगाना प्रशासन का अनुमान है कि राज्य के करीब 1,000 लोगों ने दिल्ली की जमात में हिस्सा लिया होगा। तेलंगाना में जिन छह लोगों की मौत हुई है उनमें से दो की हैदराबाद के गांधी अस्पताल, दो लोगों की निजी अस्पतालों में जबकि दो अन्य की निजामाबाद और गडवाल नगर में हुई है। सरकार के मुताबिक, जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान कर उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए जिला कलेक्टरों के मातहत विशेष दल बनाए गए हैं।

तबलीगी जमात के आयोजन में शामिल हुए लोगों में से 110 के तमिलनाडु में संक्रमित होने की पुष्टि, राज्य में कोरोना विषाणु से संक्रमित लोगों की संख्या 234 हुई।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी का कहना है कि आयोजन में करीब 1,500 लोग शामिल हुए थे और उनमें से 1,131 लौटे हैं। उन्होंने कहा कि करीब 515 लोगों की पहचान की गई है। आयोजन में शामिल होने वाले अन्य लोग स्वेच्छा से अधिकारियों से संपर्क करें... हमें अभी बाकी लोगों के पते नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि अभी कुछ लोगों से संपर्क नहीं हो सका है, लेकिन जिनसे हुआ है, उन सभी को पृथक रखा जा रहा है।

तमिलनाडु के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने 'तबलीगी जमात' के लोगों से अपील की है कि वे तुरंत स्वास्थ्य अधिकारियों से संपर्क कर आयोजन में भाग लेने वालों का फोन नंबर उन्हें मुहैया कराएं क्योंकि उनमें संक्रमण का खतरा है। अधिकारियों ने बताया कि आंध्र प्रदेश में बुधवार को 43 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है और उनमें से ज्यादातर लोग तबलीगी जमात के आयोजन में शामिल हुए थे।

कर्नाटक सरकार ने अभी तक 78 ऐसे लोगों की पहचान की है जिन्होंने निजामुद्दीन मरकज में हुए आयोजन में हिस्सा लिया था। वहीं केरल में इसमें भाग लेने वाले राज्य के सभी लोगों की पहचान कर ली है। केंद्र शासित शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी बुधवार को दो लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई, दोनों व्यक्ति मार्च में निजामुद्दीन मरकज में हुए आयोजन में शामिल हुए थे।

तबलीगी कार्यक्रम में शामिल उत्तर प्रदेश के 569 लोगों की पहचान

लखनऊ, 1 अप्रैल (भाषा)।

उत्तर प्रदेश में 569 ऐसे लोगों की पहचान की गई है जिन्होंने दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात में हिस्सा लिया था और इन लोगों को पृथक रखा गया है। अपर मुख्य सचिव (गृह एवं सूचना) अवनीश कुमार अवस्थी ने बुधवार को यहां संवाददाताओं को बताया कि राज्य में 218 विदेशी नागरिक भी मिले हैं, जो पर्यटन वीजा पर आए थे लेकिन उनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उनका तबलीगी जमात से किसी तरह का संबंध था ।

अवस्थी ने कहा कि संबंधित जिलाधिकारियों और पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि ऐसे लोग इन लोगों पृथक रखे जाएं और ऐसे मामलों में समुचित मेडिकल प्रक्रियाओं का भी पालन किया जाए। विदेशी नागरिकों के बारे में उन्होंने कहा कि पर्यटन वीजा पर आने वाले लोग धार्मिक उत्सव या मिशनरी गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी लेकिन फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता उन्हें पृथक रखना है।

प्रयागराज की मस्जिद में मिले 37 लोग, सात इंडोनेशियाई शामिल

प्रयागराज, 1 अप्रैल (भाषा)।

कोरोना वायरस के कारण देश भर में जारी बंद के बीच मंगलवार को काटजू रोड स्थित शेख अब्दुल्ला मस्जिद में 37 लोग मिले हैं जिनमें इंडोनेशिया के सात नागरिक भी शामिल है। इन्हें जार्ज टाउन स्थित कमला भवन में पृथक रखा गया है।

पुलिस अधीक्षक (नगर) बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शेख अब्दुल्ला मस्जिद में स्थित मुसाफिरखाना में ये लोग 22 मार्च से ठहरे थे जिसमें से नौ लोग ऐसे हैं जो दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात में शामिल हुए थे।

जनसेवा कोलकाता में बुधवार को राष्ट्रव्यापी पूर्ण बंदी के दौरान एक राहत शिविर में खाने के डिब्बे तैयार करते इस्कॉन के सदस्य।

निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए 89 लोगों का पता लगाया

मुंबई/रायपुर, 1 अप्रैल (भाषा)।

महाराष्ट्र के नागपुर और अहमदनगर में ऐसे कम से कम 89 लोगों का पता चला है जो पिछले महीने दिल्ली के पश्चिमी निजामुद्दीन में मरकज में आयोजित धार्मिक समागम में शरीक हुए थे। नागपुर के निगमायुक्त तुकाराम मुंडे ने कहा कि इनमें से 54 लोग नागपुर में मिले हैं और उन्हें पृथक कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इन लोगों की चिकित्सा जांच की जा रही है।

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि इनके अलावा अहमदनगर में ऐसे 35 लोगों का पता लगाया गया है जो उस धार्मिक समागम में शामिल हुए थे। उनमें से 29 इंडोनेशिया, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, घाना और अन्य देशों हैं और बाकी के स्थानीय हैं। समूह में शामिल एक विदेशी और एक स्थानीय व्यक्ति संक्रमित पाए गए थे।

अहमदनगर पुलिस को सोमवार को सूचना मिली थी कि तबलीगी जमात के कुछ सदस्य समागम में भाग लेकर जिले में लौटे हैं और वे लोग अहमदनगर के नेवासा, जामखंड तथा मुकुंदनगर इलाकों में ठहरे हुए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि इसके बाद पुलिस ने उन लोगों की तलाश की और पाया कि उनमें से कम से कम 35 लोग उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इन सभी को जिला सरकारी अस्पताल ले जाया गया और बाद में पृथक कर दिया गया।

जमात में शामिल होने गए और उनके संपर्क में आए छत्तीसगढ़ के 101 लोगों की पहचान कर उन्हें पृथक केंद्रों में भेजा गया है। इनमें से कई दूसरे राज्य के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इन 101 लोगों में से आठ दुर्ग जिले से, 17 बिलासपुर जिले से, 20 कोरबा जिले से और छह बलौदाबाजार-भाठापारा जिले से हैं।

राज्य में स्वास्थ्य विभाग की सचिव निहारिका बारिक ने बताया कि विभाग धार्मिक आयोजन से आए लोगों की जांच कर रहा है। यदि किसी एक में भी कोराना संक्रमण की पुष्टि होती है को सभी के नमूने लिए जाएंगे।

मध्यप्रदेश : सभी 107 लोगों की पहचान हुई

भोपाल/देहरादून, 1 अप्रैल (भाषा)।

निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए मध्य प्रदेश के सभी 107 लोगों की पहचान कर ली गई है और इन लोगों को पृथक रखा गया है। भोपाल के जिलाधिकारी तरुण कुमार पिथोड़े ने बुधवार को बताया कि हमने निजामुद्दीन मरकज में कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी 107 लोगों की पहचान कर इन्हें पृथक कर दिया है। इन पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। इसमें कोई चिंता करने या घबराने की बात नहीं है।

एक दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जमात के इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मध्य प्रदेश वापस आए लोगों की पहचान करने और उन्हें पृथक रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे। इस सम्मेलन में शामिल होने वाले छह लोगों की तेलंगाना और एक व्यक्ति की जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस संक्रमण से मौत हो गई।

कोरोना विषाणु संकट के बीच निजामुद्दीन मरकज में शामिल होने गई उत्तराखंड की जमात के सभी 26 सदस्य अभी दिल्ली में ही हैं। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) अशोक कुमार ने यहां बताया कि निजामुद्दीन मरकज में उत्तराखंड से शामिल जमात के सभी 26 लोग अभी दिल्ली में ही हैं।

निजामुद्दीन मरकज से लौटे दस लोगों को जम्मू में पृथक रखा

जम्मू/ईटानगर/संभल, 1 अप्रैल (भाषा)।

राष्ट्रीय राजधानी के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैदराबाद के नौ लोगों समेत 10 लोगों की बुधवार को पहचान कर ली गई और उन्हें एक स्वास्थ्य केंद्र में पृथक रखा गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जम्मू कश्मीर पुलिस के कर्मियों ने इन लोगों की पहचान की और उन्हें जम्मू के बाहरी क्षेत्र में भटिंडी भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के संभल जिला प्रशासन ने भी निजामुद्दीन मरकज में शामिल दो लोगों को बुधवार को पृथक कर दिया।

जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने बताया कि इनके नमूने लिए जा रहे हैं।

इस बीच, अरुणाचल सरकार ने भी तबलीगी जमात के इज्तिमा में शामिल होकर लौटे शख्स के नमूने बुधवार को कोविड-19 की जांच के लिए भेज दिए। लोहित के पुलिस अधीक्षक डॉ वांगडी थुंगन ने बताया कि जिले के चिकित्सा अधिकारियों ने 29 साल के एक व्यक्ति की लार (स्वाब) के नमूने असम के डिब्रूगढ़ स्थित आइसीएमआर के क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भेजे हैं। थुंगन ने बताया कि वह शख्स 16 मार्च को निजामुद्दीन से निकला था और 24 मार्च से घर में पृथक रह रहा है।

ओड़ीशा ने व्यक्ति को पृथक केंद्र भेजा

भुवनेश्वर, 1 अप्रैल (भाषा)।

ओड़ीशा सरकार ने दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के आयोजन में हिस्सा लेकर लौटे और एक व्यक्ति की पहचान कर उसे पृथक केंद्र में भेज दिया है। सरकारी सूत्रों ने बुधवार को बताया कि निजामुद्दीन से लौटा यह चौथा व्यक्ति है।

केंद्रपाड़ा के जिलाधिकारी समर्थ वर्मा ने बताया कि व्यक्ति को मंगलवार को उसके घर से लेकर अस्पताल में पृथक वार्ड में रखा गया है क्योंकि उसके कोरोना संक्रमित होने की आशंका बहुत ज्यादा है। उसके परिवार के सदस्यों को घर में ही पृथक रखा गया है।

वर्मा ने कहा- हम उसके रक्त के नमूने को कोविड-19 की जांच के लिए भेजेंगे। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो हम उससे मिलने वालों का पता लगाएंगे। पुलिस यह पता करने में जुटी है कि जिले से कौन-कौन निजामुद्दीन के तबलीगी जमात में शामिल होने गया था।

पिछले महीने गुजरात के लगभग 1500 लोग निजामुद्दीन इलाके में थे : सरकार

अमदाबाद/जयपुर, 1 अप्रैल (भाषा)।

पिछले महीने गुजरात के लगभग 1500 लोग राष्ट्रीय राजधानी के निजामुद्दीन इलाके में थे जहां कोरोना वायरस महामारी के चलते फिलहाल कड़ा लॉकडाउन है। अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि हालांकि राज्य सरकार को इस इलाके में हुए आयोजन शामिल होने वाले लोगों की सही संख्या के बारे में पता नहीं है।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक पुलिस और नगर निकाय अधिकारियों की संयुक्त टीमों ने सूरत, भावनगर और बोताड़ शहर के लहभग 60 लोगों की पहचान की जो संभवतः निजामुद्दीन इलाके मौजूद थे। उन सभी को मंगलवार रात से पृथक सेवा में रख दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार प्रशासन इन अलग-अलग शहरों में इन 1500 लोगों की पहचान करने में जुटा हुआ है।

मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में गुजरात से मरकज में शामिल होने दिल्ली जाने वाले हर व्यक्ति को खोजकर पृथक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि से लोगों की सही संख्या बुधवार शाम तक बता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने मरकज में शामिल होने वालों के खिलाफ लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पूरे समाज को खतरे में डालने वाले इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को सहन नहीं किया जाएगा।

इस बीच सूरत नगरपालिका आयुक्त वांछानिधि पाणि ने कहा कि रात भर में 43 लोगों की पहचान कर उन्हें केंद्रीय पृथक सेवा में भेज दिया गया है।

इंदौर में स्वास्थ्य कर्मियों पर पथराव, दो महिला डॉक्टर घायल

इंदौर (मध्य प्रदेश), 1 अप्रैल (भाषा)।

कोरोना वायरस से संक्रमित एक मरीज के संपर्क में आए लोगों को ढूंढने गए स्वास्थ्य कर्मियों पर यहां बुधवार को कुछ लोगों ने अचानक पथराव कर दिया। पथराव के कारण दो महिला डॉक्टरों के पैरों में चोटें आई हैं।

यह घटना शहर के टाटपट्टी बाखल इलाके में हुई। वहां कोरोना वायरस के खिलाफ अभियान चला रहे स्वास्थ्य विभाग के पांच सदस्यीय दल में शामिल एक महिला डॉक्टर ने अपनी पहचान का खुलासा करने से इनकार करते हुए संवाददाताओं से कहा, 'मैं बहुत डरी हुई हूं। हम कोरोना वायरस संक्रमण के एक मरीज के संपर्क में आए लोगों को ढूंढने गए थे।' महिला डॉक्टर ने बताया, 'हमने जैसे ही इन लोगों से उनकी सेहत की स्थिति से जुड़े सवाल करने शुरू किए, उन्होंने इसका विरोध कर दिया। तभी वहां कुछ और लोग आ धमके जिन्होंने हम पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। शुक्र है कि कुछ पुलिस कर्मी पास ही थे, इसलिए हमारी जान बच गई।'

इस बीच, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रवीण जड़िया ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि हमारा दल लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए काम कर रहा था। लेकिन रहवासियों ने नासमझी में इस दल पर ही पथराव कर दिया। उन्होंने कहा कि पथराव में हमारी दो महिला डॉक्टरों के पैरों में चोटें आई हैं। पथराव के दौरान दोनों महिला डॉक्टरों ने तहसीलदार की गाड़ी में किसी तरह छिप कर खुद को बचाया। जड़िया ने बताया कि घटना की शिकायत छत्रीपुरा पुलिस थाने में दर्ज करा दी गई है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घटना के दौरान बैरिकेड तोड़े गए हैं और पथराव भी किया गया है। इन दोनों घटनाओं पर पुलिस संज्ञान ले रही है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की मांग सूचना 13(2)
शाखा कार्यालयः गाँव सेहानी, मेरठ रोड, गाजियाबाद, उ0प्र0

यह मांग सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत एतद्द्वारा कर्जदारों/गारंटरों को उनकी गारंटी में दी गई ऋण सुविधा की बकाया राशि का भुगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए जारी की गई है। यदि आप अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत इस सूचना के संदर्भ में नीचे वर्णित राशि और उस पर आगे ब्याज और प्रासंगिक व्यय, लागत आदि का भुगतान करने में असफल रहते हैं तो बैंक कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) और अन्य लागू प्रावधान के अंतर्गत उसे प्राप्त सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचना दी जाती है कि आप बिना बैंक की लिखित अनुमति लिये इस सूचना में नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टे पर देने या अन्य लेनदेन नही कर सकते है। **बकाया राशि के साथ खाता और प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:**

अचल सम्पत्ति की अनुसूची एवं अन्य विवरण

कर्जदार/गारंटर का नाम	प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण	13(2) सूचना की तिथि एवं राशि
कर्जदारः (1) श्रीमती रानी त्यागी पत्नी श्री राज कुमार त्यागी एवं (2) श्री राज कुमार त्यागी पुत्र धीरज त्यागी दोनों का पताः मकान नं.61, सादिक नगर, सेहानी, गाजियाबाद उ0प्र0-201001.	श्रीमती रानी त्यागी पत्नी श्री राज कुमार त्यागी के नाम में साम्यिक बंधक जमीन के सभी भाग एवं हिस्से सम्पत्ति का पता खसरा नं.680, मकान नं.61 (पुराना), परगना-लोनी (क्षेत्रफल 62.50 वर्ग गज) सेहानी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। जो घिरा है: उत्तरः पुनीत फार्म दक्षिणः 15 फीट चौड़ी इंटरलॉकिंग टाईल रोड पूर्वः संजय शमा पश्चिमः दयानन्द त्यागी।	31/03/2019 को एनपीए 04/03/2020 को बकाया रू.6,50,863/- (जो इस सूचना की तिथि को बकाया मूलधन प्लस ब्याज को दर्शाता है)

आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अंतर्गत पूर्व में जारी सभी सूचनाएं वापिस ली जाती हैं।

स्थानः गाजियाबाद, उ0प्र0
दिनांकः 04.03.2020
प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेहानी, गाजियाबाद, उ0प्र0।

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank
आईएनए कॉलोनी शाखा, शुभांचल हॉस्टल बिल्डिंग,
आईएनए कॉलोनी, नई दिल्ली-23, दूरभाष : 011-24618597, 24690642
www.syndicatebank.in ई-मेल:br.9007@syndicatebank.co.in

हम निम्नलिखित सम्पत्तियों के परिप्रेक्ष्य में सम्बद्ध समाचारों में प्रकाशित निम्नलिखित विज्ञापन का सन्दर्भ लेते हैं।

क्र.सं.	शाखा का नाम	कर्जदार का नाम	विज्ञापन की तिथि	उस समाचार पत्र का नाम जिसमें विज्ञापन प्रकाशित हुआ था
1	आईएनए कॉलोनी	मैसर्स श्रीजी स्टील इस प्रोपराइटर श्री जगमोहन लाल (कर्जदार) 2) श्रीमती सरोज बाला (जमानती) के माध्यम से प्रतिनिधानित	13.03.2020	फाइनेंशियल एक्सप्रेस एवं जनसत्ता

इस विज्ञापन द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कोविड-19 के कारण उपर्युक्त नीलामियों को अगली सूचना/प्रकाशन तक आस्थगित किया जाता है।

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 01/04/2020
अधिकृत प्राधिकारी
सिंडीकेट बैंक

फार्म जी
रूचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण
[दिवाला और शोधन अक्षमता (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला रिजोल्यूशन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 36ए(1) के अंतर्गत]

संगत विवरण

1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	स्काईहाई इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट देनदार के गठन की तिथि	28 मई, 2013
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट देनदार गठित/पंजीकृत है	कंपनी पंजीयक कानपुर/कंपनी अधिनियम, 1956.
4.	कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U70102UP2013PTC057259
5.	कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय, यदि कोई हो, का पता	पंजीकृत कार्यालय : गोमती प्लाजा, दूसरी मंजिल, विकास खंड-1, गोमती नगर लखनऊ यूपी-226010 कॉर्पोरेट कार्यालय : मरीना सूट, सेल ऑफिस, पार्क टाऊन, एनएच-24, गाजियाबाद, यूपी
6.	कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में दिवाला प्रारंभ तिथि	7 जनवरी, 2020
7.	रूचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	2 अप्रैल, 2020
8.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के अंतर्गत रिजोल्यूशन आवेदकों के लिए योग्यता की उपलब्धता	इसे ई-मेल cirp.skyhigh@gmail.com पर मेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है
9.	धारा 29ए के अंतर्गत लागू अयोग्यता मानकों की उपलब्धता	इसे ई-मेल cirp.skyhigh@gmail.com पर मेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है
10.	रूचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि	30 अप्रैल, 2020
11.	भावी रिजोल्यूशन आवेदकों की वैकल्पिक सूची जारी करने की तिथि	10 मई, 2020
12.	वैकल्पिक सूची के लिए आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि	15 मई, 2020
13.	भावी रिजोल्यूशन आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	25 मई, 2020
14.	भावी रिजोल्यूशन आवेदकों के लिए रिजोल्यूशन योजना हेतु सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स एवं अनुरोध जारी करने की तिथि	16 मई, 2020
15.	रिजोल्यूशन योजना के लिए अनुरोध, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन एवं भावी जानकारी प्राप्त करने का तरीका	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला रिजोल्यूशन प्रक्रिया) करने विनियम, 2016 के विनियम 36ख(1) के अंतर्गत इसे प्राप्त करने के योग्य सभी भावी रिजोल्यूशन आवेदकों (पीआरए) को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में साझा किया जाएगा।
16.	रिजोल्यूशन योजना जमा करने की अंतिम तिथि	15 जून, 2020
17.	रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के लिए रिजोल्यूशन योजना जमा करने का तरीका	रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अर्थात् अमित अग्रवाल, एच-63, विजय चौक लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 को संबोधित करके मुहरबंद लिफाफे में डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से और उसके बाद पुष्टि के लिए ई-मेल किया जाएगा।
18.	अनुमोदन के लिए न्यायिक प्राधिकरण के पास रिजोल्यूशन योजना जमा करने की अनुमानित तिथि	20 जून, 2020
19.	रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम एवं पंजीकरण संख्या	अमित अग्रवाल पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-02/IP-N00185/2017-18/10456
20.	बोर्ड में पंजीकृत अनुसार रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम, पता एवं ई-मेल	अमित अग्रवाल एच-63, विजय चौक लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 ईमेल आईडी : amitagcs@gmail.com
21.	रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए उपयोग होने वाला पता एवं ई-मेल	अमित अग्रवाल एच-63, विजय चौक लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 ईमेल आईडी : cirp.skyhigh@gmail.com
22.	विस्तृत विवरण उपलब्ध है:	इसे ई-मेल cirp.skyhigh@gmail.com पर मेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है
23.	फार्म जी के प्रकाशन की तिथि	2 अप्रैल, 2020

हस्ता/-
अमित अग्रवाल
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-02/IP-N00185/2017-18/10456
एच-63, विजय चौक लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
कृते स्काईहाई इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
(2 अप्रैल, 2020)

www.readwhere.com

दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार ग्रैंडस्लैम पर असर

विंबलडन किया गया रद्द

लंदन, 1 अप्रैल (एएफपी)।

दुनिया भर के खेल कैलेंडर को तहस नहस करने वाली कोरोना वायरस महामारी के कारण बुधवार को सबसे पुराना ग्रैंडस्लैम टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन रद्द कर दिया गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार यह टूर्नामेंट रद्द किया गया है।

ऑल इंग्लैंड क्लब ने आपात बैठक के बाद यह घोषणा की कि इस साल यह टूर्नामेंट नहीं होगा। विंबलडन क्लब के ग्रासकोर्ट पर 29 जून से 12 जुलाई के बीच खेला जाना था। आयोजकों ने एक बयान में कहा कि बड़े खेद के साथ ऑल इंग्लैंड क्लब के बोर्ड और चैंपियनशिप की प्रबंध समिति ने फैसला किया है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण विंबलडन 2020 नहीं खेला जा सकेगा।

आठ बार के चैंपियन रोजर फेडरर ने ट्वीट किया,'बेहद दुखी हूं।' वहीं सात बार की चैंपियन सेरेना विलियम्स ने कहा कि वह इस फैसले से स्तब्ध हैं। सिमोना हालेप ने ट्वीट किया,'यह सुनकर काफी दुख हुआ कि इस साल विंबलडन नहीं खेला जाएगा। पिछले साल का फाइनल मेरे जीवन के सबसे सुखद दिनों में से था लेकिन अभी हम जिससे गुजर रहे हैं, वह टेनिस से बड़ा है।'

अब अगला सत्र 28 जून से 11 जुलाई 2021 के बीच होगा। यह टूर्नामेंट पहली बार 1877 में खेला गया और उसके बाद से हर साल होता आया है। सिर्फ 1915 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और 1940 से 1945 के बीच दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यह नहीं खेला गया।

इसके साथ ही एटीपी और डब्लूटीए ने विंबलडन की तैयारी के लिए होने वाले टूर्नामेंट भी रद्द कर दिए हैं। अब नया सत्र 13 जुलाई से पहले शुरू नहीं हो सकेगा। कोरोना वायरस के कारण तोक्यो ओलंपिक स्थगित हो चुके हैं।

विंबलडन इस महामारी के कारण रद्द होने वाला पहला ग्रैंडस्लैम है। मई में होने वाला फ्रेंच ओपन अब सितंबर के आखिर में होगा। अमेरिकी ओपन 31 अगस्त से 13 सितंबर के बीच न्यूयार्क में खेला जाएगा।

यूएस ओपन का आयोजन 31 अगस्त से ही होगा : आयोजक

न्यूयार्क, 1 अप्रैल (एएफपी)।

अमेरिकी ओपन के आयोजकों ने बुधवार को कहा कि यह ग्रैंडस्लैम अपने तय समय 31 अगस्त से यहां शुरु होगा। कोरोना वायरस महामारी के न्यूयार्क में बढ़ने के बाद यहां के नेशनल टेनिस सेंटर के इंडोर कोर्ट का इस्तेमाल अस्थायी अस्पताल की सुविधा के लिए किया जा रहा है।

अमेरिकी टेनिस संघ (यूएसटीए) ने कहा कि वह स्थिति पर नजर बनाए रखेगा और जरूरत के मुताबिक बदलाव करेगा। यूएसटीए के बयान के मुताबिक, 'मौजूदा समय में यूएसटीए की योजना यूएस ओपन को निर्धारित समय पर कराने की है। हम टूर्नामेंट की तैयारी का काम जारी रखेंगे।'

बयान के मुताबिक, 'यूएसटीए कोविड-19 महामारी के कारण तेजी से बदलते स्थिति की सावधानीपूर्वक निगरानी कर रहा है और किसी भी आकस्मिक स्थिति का सामना करने की योजना बना रहा है।' अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले न्यूयार्क में ही सामने आए हैं।

क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने तैयार किया चार सूत्री कार्यक्रम

जोहानिसबर्ग, 1 अप्रैल (भाषा)।

क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) ने दुनिया भर में फैली घातक कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में संगठन से जुड़े सभी लोगों की हर तरह से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चार सूत्री रणनीति तैयार की है। दक्षिण अफ्रीका में 16 अप्रैल तक लॉकडाउन है और ऐसे में सीएसए के कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी जॉक फॉल ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए योजना तैयार की। इसमें अंतरिम निदेशक ग्रीम स्मिथ ने भी हिस्सा लिया।

फॉल ने कहा कि इस समय स्वास्थ्य सबसे अहम है। हमारी दुनिया में खेल बेहद महत्त्वपूर्ण चीज है और इससे कई लोगों की आजीविका चलती है लेकिन ईमानदारी से कहूं तो विश्व अभी इससे भी बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। सीईओ ने कहा कि संगठन उनके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की भलाई के लिए अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा है और उसने चार सूत्री योजना बनाई है।

फॉल ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए हमने चार सूत्री रणनीति बनाई है और इसमें पहली हर किसी की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। दूसरा संदेश पहुंचाने के लिए अपने स्टार क्रिकेटरों का उपयोग करना। हमने अभी तक अपने अभियानों में ऐसा देखा भी है। उन्होंने कहा कि तीसरा अपने हितधारकों के संपर्क में रहना है ताकि हम यह पता कर सकें कि वे वर्तमान परिस्थिति से कैसे प्रभावित हैं और यह हमें कैसे प्रभावित कर सकता है।

चौथा योजना से जुड़ा है। इसमें हम यह पता करेंगे कि कोविड-19 कैसे हम पर प्रभाव डालता है और इससे हमारी वित्तीय स्थिति कैसे प्रभावित होती है। इसके बाद दुनिया कभी पहले जैसी नहीं होगी।

कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में संगठन से जुड़े सभी लोगों की हर तरह से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चार सूत्री रणनीति तैयार की गई है।

"इस समय स्वास्थ्य सबसे अहम है। हमारी दुनिया में खेल बेहद महत्त्वपूर्ण चीज है और इससे कई लोगों की आजीविका चलती है। संगठन प्रत्येक व्यक्ति की भलाई के लिए अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा है और उसने चार सूत्री योजना बनाई है। **-जॉक फॉल**, सीईओ

केवल भारतीय खिलाड़ियों के साथ भी आइपीएल को तैयार : राजस्थान रॉयल्स

नई दिल्ली, 1 अप्रैल (भाषा)।

राजस्थान रॉयल्स के सीईओ रंजीत बरठाकुर ने बुधवार को कहा कि इस मुश्किल समय में केवल भारतीय खिलाड़ियों के साथ छोटी अवधि का आइपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) भी अच्छा होगा। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि इस टी-20 लीग के भाग्य का फैसला 15 अप्रैल से पहले किए जाने की संभावना नहीं है।

कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में खेल गतिविधियां ठप पड़ी हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआइ) ने इस धनाढ्य लीग को लेकर अभी तक फैसला नहीं किया है। इसे कोविड-19 महामारी और विदेशी नागरिकों के भारत में प्रवेश पर लगी पाबंदी को देखते हुए कम से कम 15 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया था। पूर्व कार्यक्रम के अनुसार यह टूर्नामेंट 29 मार्च से शुरू होना था।

बरठाकुर ने कहा कि हम केवल भारतीय खिलाड़ियों के साथ छोटे टूर्नामेंट के लिए तैयार हैं। आखिरकार यह है तो इंडियन प्रीमियर लीग ही। महामारी को रोकने के लिए देश भर में 'लॉकडाउन' है और वर्तमान हालात देखकर इसके आयोजन की संभावना नहीं लग रही है। बीसीसीआइ के पास हालांकि कुछ द्विपक्षीय शृंखलाओं की तिलांजलि देकर साल के अंत में आइपीएल के आयोजन का विकल्प है।

रॉयल्स के कार्यकारी अधिकारी ने उम्मीद जताई कि बीसीसीआइ फ्रेंचाइजी के सर्वश्रेष्ठ हितों को ध्यान में रखकर फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि यह असाधारण समय है और स्थिति में सुधार पर बीसीसीआइ को अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने होंगे। बरठाकुर ने कहा कि पहले हम केवल भारतीय खिलाड़ियों के आइपीएल के बारे में नहीं सोच सकते थे लेकिन अब भारत में पर्याप्त अच्छे खिलाड़ी हैं। आइपीएल नहीं करवाने के बजाय केवल भारतीय खिलाड़ियों के साथ टूर्नामेंट आयोजित कराना बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट का आयोजन कब हो सकता है, इसका फैसला बीसीसीआइ को करना है और मेरा मानना है कि ऐसा फैसला 15 अप्रैल के बाद ही किया जाना चाहिए।

"हम केवल भारतीय खिलाड़ियों के साथ छोटे टूर्नामेंट के लिए तैयार हैं। आखिरकार यह है तो इंडियन प्रीमियर लीग ही।

-रंजीत बरठाकुर,
सीईओ राजस्थान रॉयल्स

बरठाकुर ने कहा कि पहले हम केवल भारतीय खिलाड़ियों के आइपीएल के बारे में नहीं सोच सकते थे लेकिन अब भारत में पर्याप्त अच्छे खिलाड़ी हैं।

फुकुशिमा में एक महीने तक रहेगी ओलंपिक मशाल

तोक्यो, 1 अप्रैल (एपी)।

ओलंपिक मशाल अप्रैल के आखिर तक जापान के फुकुशिमा में रहेगी। तोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति ने बुधवार को फुकुशिमा में आधिकारिक 'हैंडओवर समारोह' का आयोजन किया। कोरोना वायरस के चलते लागू पाबंदियों को ध्यान में रखकर लोगों को इसके पास भीड़ लगाने की अनुमति नहीं है। ओलंपिक मशाल यूनान से 20 मार्च को यहां पहुंची और पिछले सप्ताह मशाल रिले फुकुशिमा से शुरू हुई थी। यह जापान का वह इलाका है जो भूकंप, सुनामी और परमाणु रिसाव की त्रासदी झेल चुका है।

बजरंग को ओलंपिक में मिलेगी वरीयता

नई दिल्ली, 1 अप्रैल (भाषा)।

स्टार भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया विश्व कुश्ती की नवीनतम रैंकिंग में दूसरे स्थान पर बरकरार हैं। इससे उन्हें 65 किलोग्राम वर्ग में अगले साल के तोक्यो ओलंपिक में शीर्ष चार में वरीयता मिलना लगभग तय है। तेजी से उभरते रवि दहिया को भी अगले साल 23 जुलाई से आठ अगस्त तक होने वाले इस बड़े प्रतियोगिता में शीर्ष चार वरीयता मिलना तय है।

कुश्ती का संचालन करने वाली वैश्विक इकाई (यूडब्लूडब्लू) की नवीनतम रैंकिंग में बजरंग दूसरे जबकि बेहद ही प्रतिस्पर्धी माने जाने वाले 57 किग्रा में दहिया चौथे स्थान पर हैं। रूस के ओलंपिक चैंपियन गधजिमुराद रशीदोव 65 किग्रा में 60 अंक के साथ शीर्ष पर हैं जबकि बजरंग के नाम 59 अंक है।

पिछले सत्र में नूर-सुल्तान में स्वर्ण जीत कर रशीदोव ने 65 किलोग्राम में शीर्ष स्थान पर अपनी जगह पक्की की थी। बजरंग साल की शुरुआत विश्व चैंपियनशिन में कांस्य पदक जीतने के बाद 25 अंकों के साथ तीसरे रैंकिंग से करने के बाद कजाखस्तान के दौलत नियाजबेखोव की जगह दूसरे स्थान पर पहुंचे थे। नियाजबेखोव मैजूदा रैंकिंग में भी 56 अंक के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

रूस के विश्व चैंपियन जाउर यूग्वे 60 अंक के साथ 57 किग्रा की रैंकिंग में शीर्ष पर हैं। विश्व चैंपियनशिप के उप विजेता सुलेमान 58 अंक के साथ दूसरे जबकि स्टीवन माइक (48) और दहिया (45) क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता दीपक पूनिया 65 किलोग्राम में ईरान के दिग्गज हसन यजदानी के बाद दूसरे स्थान पर हैं। यजदानी ने इस साल की शुरुआत में घुटने की सर्जरी कराई थी जिसके बाद वह मैटेलो पेलकोनिक और एशियाई चैंपियनशिप में भाग नहीं ले सके थे।

यजदानी ने दीपक पर 20 अंकों की बढ़त हासिल की थी लेकिन भारतीय पहलवान ने एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य-पदक के साथ 14 अंकों की यजदानी के अंतर को कम किया। ओलंपिक के अन्य तीन भार वर्ग में 74 किग्रा, 97 किग्रा और 125 किग्रा के शीर्ष -10 में कोई भारतीय पहलवान नहीं है। हर भार वर्ग के शीर्ष चार खिलाड़ियों को तोक्यो ओलंपिक में वरीयता दी जाएगी।

पूनिया विश्व कुश्ती की नवीनतम रैंकिंग में दूसरे स्थान पर बरकरार हैं।

सफलता का कोई मंत्र नहीं, केवल मेहनत करो : मैरी कॉम

नई दिल्ली, 1 अप्रैल (भाषा)।

ओलंपिक कांस्य पदक विजेता और छह बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम ने साफ किया कि उनकी सफलता का कोई मूलमंत्र नहीं है। वह कड़ी मेहनत के दम पर ही इस मुकाम तक पहुंची हैं। 37 वर्षीय मुक्केबाज अपने दूसरे ओलंपिक खेलों की तैयारियों में जुटी हैं जिसे कोविड-19 महामारी के कारण 2021 तक टाल दिया गया है।

मैरी कॉम बुधवार को भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के 'मेकिंग ऑफ ए चैंपियन' विषय पर बात कर रही थीं जो कि साई का खिलाड़ियों के लिए फेसबुक 'लाइव सेसन' है। महामारी के चलते लॉकडाउन होने के कारण अधिकतर खिलाड़ी अपने घरों या हॉस्टल में बंद हैं। मैरी कॉम ने कहा कि उन्होंने जो सफलताएं हासिल की उसके पीछे कोई राज नहीं छिपा है।

उन्होंने कहा कि मेरे पास सफलता का कोई मंत्र नहीं है। कड़ी मेहनत करो और आप जो भी कर रहे हो उसके प्रति ईमानदार बने रहो। बस यही मैं करती हूं। उतार-चढ़ाव तो आते रहते हैं लेकिन आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए ध्यान नहीं हटाना चाहिए।

मैरी कॉम ने कहा कि मुक्केबाजी की मेरी यात्रा आसान नहीं रही। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और ओलंपिक स्तर पर पहुंचना आसान नहीं था लेकिन अगर आपके अंदर इच्छाशक्ति है और जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो।

उन्होंने कहा कि मेरी शुरुआती जिंदगी कठिनाईयों से भरी थी। मैं गरीब परिवार में पली बढ़ी जहां कई तरह की मुश्किलें थीं। मैं उन्हें याद तक नहीं करना चाहती हूं। इस मुक्केबाज ने सभी को संकट की इस घड़ी में अपने घरों में ही रहने की सलाह दी।

विश्व कप फाइनल की शर्ट नीलाम कर रहे बटलर

लंदन, 1 अप्रैल (एएफपी)।

इंग्लैंड के जोस बटलर कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों का उपचार कर रहे अस्पतालों की मदद के लिए विश्व कप फाइनल में पहनी अपनी शर्ट को नीलाम कर रहे हैं। इस 29 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने जुलाई में न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए फाइनल में इंग्लैंड की रोमांचक जीत में अहम भूमिका निभाई थी।

उन्होंने अर्धशतक बनाया था और फिर सुपर ओवर में बल्लेबाजी की थी। इसके अलावा उन्होंने मैच की अंतिम गेंद पर मार्टिन गुप्टिल को रन आउट किया था। बटलर ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में कहा कि इस जर्सी पर विश्व कप विजेता टीम के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हैं और इसे ईबे पर नीलाम किया जा रहा है। इससे मिलने वाली धनराशि रॉयल ब्राम्पटन एंड हेयरफील्ड हास्पिटल चैरिटी में जाएगी।

उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय अस्पताल, चिकित्सक, नर्स और एनएचएस अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। उन्हें आने वाले समय में अधिक से अधिक सहयोग की जरूरत पड़ेगी। बटलर ने कहा कि पिछले सप्ताह रॉयल ब्राम्पटन एंड हेयरफील्ड अस्पताल चैरिटी ने कोविड-19 से बचने की तैयारियों के लिए फेफड़े और हृदय रोगों से जुड़े दो अस्पतालों को जीवनदायनी उपकरण उपलब्ध कराने के लिए आपात अपील की थी। उन्होंने कहा कि धनराशि जुटाने के उनके प्रयास के तहत मैं अपनी उस शर्ट को नीलाम कर रहा हूं जो पिछले साल मैंने विश्व कप फाइनल में पहनी थी। इस पर उस टीम में शामिल सभी खिलाड़ियों के हस्ताक्षर हैं।

ईसीबी ने छह करोड़ दस लाख पौंड के मदद की घोषणा की

लंदन, 1 अप्रैल (भाषा)।

इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने कोविड-19 महामारी से पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव का सामना करने के लिए छह करोड़ दस लाख पौंड के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। उसने खिलाड़ियों के वेतन में कटौती करने की अभी कोई घोषणा नहीं की है।

'तिल का ताड़ बना दिया गया'

नई दिल्ली, 1 अप्रैल (भाषा)।

पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की संस्था को दान देने का आग्रह करती अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर पूर्व हरफनमौला युवराज सिंह आलोचना झेल रहे हैं। उन्होंने बुधवार को कहा कि उनका इरादा किसी को आहत करने का नहीं था और मदद की उनकी गुहार को लेकर तिल का ताड़ बना दिया गया।

युवराज और हरभजन सिंह ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अफरीदी के चैरिटी फाउंडेशन की मदद के लिए ट्वीट किया था। दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव के मद्देनजर उनके इस ट्वीट की काफी आलोचना हो रही है।

युवराज ने आज ट्वीट किया,'मुझे समझ में नहीं आता कि जरूरतमंदो की मदद को लेकर किए गए एक ट्वीट पर इतना हंगामा क्यो बरपा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि अपने अपने देश में लोगों की मदद करें। मेरा इरादा किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था।'

गांगुली बने वार्न की भारत एकादश के कप्तान

नई दिल्ली, 1 अप्रैल (भाषा)।

आस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर शेन वार्न ने पूर्व कप्तान और वर्तमान में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली को अपनी सर्वकालिक भारतीय एकादश का कप्तान चुना है। लेकिन उन्हें दिन में तारे दिखाने वाले वीवीएस लक्ष्मण को इस टीम में जगह नहीं मिली। वार्न ने इस टीम में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और नवजोत सिंह सिद्धू को भी रखा है।

वार्न ने कहा कि उन्होंने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और वर्तमान कप्तान विराट कोहली को इसलिए नजरअंदाज किया क्योंकि उन्होंने केवल उन्हीं खिलाड़ियों में से टीम चुनी है जिनके खिलाफ वह खेले हैं। वार्न ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर कहा कि मैं केवल उन्हीं खिलाड़ियों को चुन रहा हूं जिनके खिलाफ मैं खेला और इसलिए महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली इस टीम का हिस्सा नहीं बन रहे हैं।

धोनी जहां इस खेल के सर्वकालिक विकेटकीपर बल्लेबाजों में शामिल हैं वहीं कोहली सभी प्रारूपों के सर्वकालिक बल्लेबाजों में से एक हैं। वार्न ने लक्ष्मण को भी नजरअंदाज किया है जिन्हें एक समय उन्होंने अपना कड़ा प्रतिद्वंद्वी बताया था। उन्होंने कहा कि गांगुली को टीम में रखने के लिए इस कलात्मक हैदराबादी बल्लेबाज को टीम से बाहर करना पड़ा।

उन्होंने कहा कि मैंने गांगुली को चुना क्योंकि मैं उन्हें अपनी टीम का कप्तान बनाना चाहता था और इसलिए लक्ष्मण को टीम में जगह नहीं मिली। वार्न ने विकेटकीपर के तौर पर नयन मोंगिया को चुना है। इस टीम में 1983 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान कपिल देव, स्पिनर अनिल कुंबले और हरभजन सिंह व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ भी शामिल हैं।

इस लेग स्पिनर ने वीरेंद्र सहवाग और सिद्धू को सलामी बल्लेबाज चुना है। उनकी बल्लेबाजी लाइन अप में राहुल द्रविड़, तेंदुलकर और मोहम्मद अजहरूद्दीन शामिल हैं। अन्य सलामी बल्लेबाजों पर सिद्धू को प्राथमिकता देने के बारे में वार्न ने कहा कि पंजाब का यह बल्लेबाज उनके दिनों में स्पिन के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे।

उन्होंने कहा कि मैंने नवजोत सिंह को इसलिए चुना है क्योंकि मैं जिन भी खिलाड़ियों के खिलाफ खेला उनमें वह स्पिन के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज थे। मैं अन्य जितने भी स्पिनरों के साथ खेला उन्होंने भी मुझसे कहा कि सिद्धू स्पिन के खिलाफ शानदार हैं।

धोनी और कोहली टीम में नहीं

वार्न ने कहा कि उन्होंने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और वर्तमान कप्तान विराट कोहली को इसलिए नजरअंदाज किया क्योंकि उन्होंने केवल उन्हीं खिलाड़ियों में से टीम चुनी है जिनके खिलाफ वह खेले हैं।

वीरेंद्र सहवाग और सिद्धू को सलामी बल्लेबाज चुना है। उनकी बल्लेबाजी लाइन अप में राहुल द्रविड़, तेंदुलकर और मोहम्मद अजहरूद्दीन शामिल हैं।

नई तारीखों की तलाश में तैराकी विश्व चैंपियनशिप

रोम, 1 अप्रैल (एपी)।

कोविड-19 महामारी के कारण तोक्यो ओलंपिक के नई तारीखों की घोषणा के बाद फीना अगले विश्व चैंपियनशिप के लिए नई तिथि की तलाश में है। फीना विश्व में तैराकी प्रतियोगिता का संचालन करने वाली इकाई है।

हर दो साल में होने वाली इस चैंपियनशिप का आयोजन जापान के फुकुओका में 16 जुलाई से एक अगस्त 2021 तक होना था। सोमवार को तोक्यो ओलंपिक की तारीखों को एक साल आगे बढ़ा दिया गया और अब उसका आयोजन 23 जुलाई से आठ अगस्त 2021 तक होगा।

ऐसे में फीना के पास दो विकल्प बचते हैं जिसमें इसका आयोजन सितंबर-अक्तूबर 2021 या फिर मई-जून (2022) में करना शामिल है। चैंपियनशिप को हालांकि एक साल तक टालने का फैसला मुश्किल हो सकता है क्योंकि 2022 में पहले से राष्ट्रमंडल खेलों, यूरोपीय तैराकी चैंपियनशिप, पैन-पैसेफिक चैंपियनशिप और वाटर पोलो चैंपियनशिप जैसी अहम प्रतियोगिताए हैं।

फीना के कार्यकारी निदेशक कॉर्नेल मारकुलसु ने मंगलवार को बताया कि हम पहले फुकुओका की जानकारी लेंगे, साझेदारों से चर्चा करेंगे, टेलीविजन और दूसरे मुद्दे पर विचार करने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। मारकुलसु ने कहा कि फीना को कोई फैसला करने के लिए दो सप्ताह का समय चाहिए।

दो साल में होने वाली इस चैंपियनशिप का आयोजन जापान के फुकुओका में 16 जुलाई से एक अगस्त 2021 तक होना था।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 136, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com